रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 19, 1986/चैत्र 29, 1908
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 19, 1986/CHAITRA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1986

सूचना

का. आ. 1540.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्रीमती यश छिब्बर, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे दिल्ली राज्य में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए ।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं. 5(39)/86-न्या.]

आर. एन. पोद्दार, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 7th April, 1986

NOTICE

S.O. 1540.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Mrs. Yash Chhibber, Advocate for apopintment as a Notary to practise in Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(39)/86-Judl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1986

का.आ. 1541.—सार्वजनिक परिसर (अवैध कब्जा बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नांकित सारणी के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारी को, भारत सरकार का एक राजपत्रित अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और आगे निदेश देती है कि यह अधिकारी सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसर के संबंध में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन संपदा अधिकारी को इस संबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निष्पादन करेगा :—

अधिकारी का पद	सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां
1	2
सहायक निदेशक (प्रशासन) महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली ।	संपदा निदेशालय द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय को सौंपे गए केन्द्रीय पूल आवास सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय, नई दिल्ली से संबंधित सार्वजनिक भवन या उसके पर

1	2
	लिए गए या अधिग्रहीत किए गए या उनकी ओर से लिए गए सरकारी भवन

[सं. ए-2-6/86-प्रशा. 3/के.रि.पु.ब./ग्रु.मं./एफ पी-4]
वी. के. जैन, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 8th April, 1986

S.O. 1541.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in the column (1) of the Table below being a Gazetted officer of the Government of India, to be the state officer for the purposes of the said Act, and further directs that the said Officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table :—

TABLE

Designation of the officer	Categories of the public premises
1	2
Assistant Director Administration), Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi.	Public premises belonging to or taken on lease requisitioned by or on behalf of the Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi including the General Pool accommodation placed at the disposal of the Directorate General, Central Reserve Police Force by the Directorate of Estates in Delhi/New Delhi.

[No. A-II-6/86-Adm-3/CRPF/MHA/F.P. IV]

V. K. JAIN Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1986

आयकर

का. आ. 1542.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, "मायलापोर, मद्रास स्थित दि श्री वलीश्वर मन्दिर/देवस्थानम्, मद्रास" को ऐतिहासिक महत्व के स्थान के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 6611 (फा.सं. 176/76/85-आ.क.नि. 1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 3rd March, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 1542.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Sction 80-G of thee Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Sri Valleeswarar Temple|Devasthanam, at Mylapore, Madras as a place of historic importance.

[No. 6611(F. No. 176/76/85-IT(AI)]

का. आ. 1543.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, "श्री आत्मानाथ सामी मंदिर, तिरूप्परून्तुरै, तमिलनाडु" को समस्त तमिलनाडु राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजा स्थल अधिसूचित करती है ।

[सं. 6610 (फा. सं. 176/48/85-आ.क. नि.-1)]

S.O. 1543.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Sri Athmanathasamy Temple at Thirupperunthurai, Tamil Nadu" as a place of public worship renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 6610/F. No. 176/48/85-IT(AI)]

केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1986

(आयकर)

का.आ. 1544:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दिनांक 29-10-1981 को अपनी अधिसूचना सं. 4286 (फा.सं. 187/30/81-आ.क. (नि.-1) के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

(1) क्र. सं. 9ख के सामने कालम 2, 3 तथा 4 की प्रविष्टियों का विलोप किया जाता है ।

(2) क्र.सं. 9 तथा 9क के सामने कालम 2, 3 तथा 4 की प्रविष्टियां निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित की जाती हैं :—

क्र. सं.	आयकर आयुक्त	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
9.	दिल्ली (केन्द्रीय)-1	नई दिल्ली	केन्द्रीय परिमण्डल-1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, और 20
9क	दिल्ली (केन्द्रीय)-2	नई दिल्ली	केन्द्रीय परिमण्डल-3, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 25 तथा 26

यह अधिसूचना 1-3-1986 से लागू होगी ।

[सं. 6607 (फा.सं. 187/2/86-आई. टी. ए-1]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 28th February, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 1544.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 4286 dated 29-10-1981 (F.No.187/30/81-IT(AT):—

(1) Entries in Col. 2, 3 & 4 against S.No. 9B are deleted.

(2) Entri s in Col. 2, 3 & 4 against S.No. 9 and 9A are substituted as under:—

S. No.	Commissioner of Income-tax	Headquarters	Jurisdiction
1	2	3	4
9.	Delhi (Central)—I	New Delhi	Central Circles-I, II, IV, V, VI, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX & XX.
9A.	Delhi (Central)—II	New Delhi	Central Circles-III, VII, VIII, IX, X, XVI XVII, XXI, XXII, XXV & XXVI.

This notification shall take effect from 1-3-1986.

[No. 6607 (F.No.187/7/86-IT(AI)]

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1986

शुद्धिपत्र

(आयकर)

का. आ. 1545.—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दिनांक 1-3-1986 की अधिसूचना संख्या 6607 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि-पत्र जारी करता है :—

के लिए

"यह अधिसूचना 1-3-1986 से लागू होगी ।"

पढ़िए

"यह अधिसूचना 1-4-1986 लागू होगी ।"

[संख्या 6612 (फा.सं. 187/2/86-आ.क.नि.-1)]

आर. के. तिवारी, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

New Delhi the 5th March

CORRIGENDUM

(INCOME-TAX)

S.O. 1545:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes issues the following corrigendum in respect of Notification No. 6607 dated 1-3-1986.

FOR	READ
'This notification shall take effect from 1-3-1986.'	'This notification shall take effect from 1-4-1986.'.

No. 61612(F. No. 187/2/86-IT (AI)]

R.K. TEWARI, Under Secy.

Central Board of Direct Taxes

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1986

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 1546.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम, बम्बई को मात्र दो लाख अट्ठासी हजार सात सौ पचास रुपये के समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त निगम द्वारा मात्र तीन करोड़ पचासी लाख रुपये के अंकित मूल्य के ऋणपत्रों के रूप में जारी किए जाने वाले बंधपत्रों "9 प्रतिशत एम. एस. एफ.सी. बंधपत्र 2000 (तृतीय श्रृंखला)" पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है ।

[सं. 16/86-स्टाम्प (फा. सं. 33/18/85-वि.क.)]

बी. आर. मेहमी, अवर सचिव

New Delhi, the 4th April, 1986

ORDER

STAMPS

S.O. 1546.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Maharashtra State Financial Corporation, Bombay to pay consolidated stamp duty of rupees two lakhs and eighty-eight thousand, seven hundred and fifty only, chargeable on account of the stamp duty on "9 per cent M.S.F.C. Bonds 2000 (III Series)" being bonds in the form of debentures of the face value of rupees three crores and eighty-five lakhs only to be issued by the said Corporation.

[No. 1686-Stamps-F. No. 33/18/85-ST]

B. R. MEHMI, Under Secy.

समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1986

का.आ. 1547.— समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 12 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) 'अधिनियम' से तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) "अपील" से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन की गई अपील अभिप्रेत है ;

(ग) "अपीलार्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अधिकरण को अपील करता है, और इसके अन्तर्गत अपीलार्थी का प्राधिकृत प्रतिनिधि भी है ;

(घ) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से निम्नलिखित अभिप्रेत है ,

(i) किसी अपीलार्थी के संबंध में,

(अ) कोई व्यक्ति जो अपीलार्थी का संबंधी है या अपीलार्थी के नियमित नियोजन में है या था, और जो अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया है; या

(आ) भारत में किसी सिविल न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार कोई विधि व्यवसायी जिसे

अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया है ;

या

(इ) कोई लेखापाल जो चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 3 के अधीन गठित इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट आफ इंडिया का या लागत और संकर्म अकाउन्टेंट अधिनियम 1959 (1959 का 23) की धारा 3 के अधीन गठित इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट आफ इंडिया का सदस्य है तथा जिसे अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया है ; या

(ii) किसी सक्षम प्राधिकारी के संबंध में, जो अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में एक पक्षकार है :—

(अ) केन्द्रीय सरकार का कोई विधि अधिकारी ;

(आ) केन्द्रीय सरकार का सरकारी अधिवक्ता या स्थायी परामर्शी, वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ;

(इ) केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया है ;

(ई) कोई विधि व्यवसायी या केन्द्रीय सरकार का अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है ;

(उ) कोई विधि व्यवसायी या केन्द्रीय सरकार का अधिकारी जो इस प्रकार अधिसूचित या प्राधिकृत किसी व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा है ;

(ङ) 'न्यायपीठ' से धारा 12 की उपधारा (6) या (6क) के अधीन गठित अधिकरण की न्यायपीठ अभिप्रेत है ;

(च) 'अध्यक्ष' से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(छ) 'सक्षम प्राधिकारी' से धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में परिभाषित सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) 'विधिक प्रतिनिधि' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधितया प्रतिनिधित्व करता है, और इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे अधिकरण अपने समक्ष लम्बित कार्यवाहियों में मृत व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला मानता है;

(झ) "सदस्य" से अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है।

(ञ) किसी अपील के संबंध में "पक्षकार" से अपीलार्थी, या प्रत्यर्थी अभिप्रेत है और "पक्षकारों" पद का अर्थ अपीलार्थी और प्रत्यर्थी लगाया जाएगा ;

(ट) "रजिस्ट्रार" से अधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे अध्यक्ष ने रजिस्ट्रार के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया है ;

(ठ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ड) "अधिकरण" से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण अभिप्रेत है ।

3. अधिकरण की भाषा—(1) अधिकरण के समक्ष सभी अभिवचन, अपीलार्थी के विकल्पानुसार, अंग्रेजी अथवा हिन्दी में हो सकते हैं ।

(2) अधिकरण के सभी आदेश और अन्य कार्यवाहियां, अधिकरण के विकल्पानुसार, अंग्रेजी या हिन्दी में हो सकते हैं ।

4. अधिकरण का मुख्यालय आदि—(1) अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

(2) सभी अपीलों और अर्जियों की सुनवाई सामान्यतया मुख्यालय पर की जाएंगी या अध्यक्ष के विवेकानुसार मुम्बई, मद्रास, कलकत्ता या किसी अन्य स्थान पर की जा सकती है ।

(3) अधिकरण का कार्यालय ऐसे अवकाश दिनों और अन्य अवकाश दिनों को बन्द रहेगा जिन दिनों केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय बन्द रहते हैं ।

5. अपील और अर्जियां दाखिल करने की प्रक्रिया

(1) अधिनियम की धारा 7 या धारा 9 की उप-धारा (1) या धारा 10 के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अधिकरण को अपील कर सकता है और अपील का ज्ञापन इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में होगा ।

(2) अपील का ज्ञापन अंग्रेजी या हिन्दी में होगा और उसमें अपील के आधार संक्षेप में और विभिन्न शीर्षों के अधीन, किसी तर्क या विवरण के बिना, दिए जायेंगे और ऐसे आधारों को क्रमानुसार संख्यांकित किया जाएगा ।

(3) अपील का ज्ञापन और अर्जी चार प्रतियों में होगी और अपील के ज्ञापन की दशा में उसके साथ उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, चार प्रतियां होंगी तथा उनमें से एक प्रति ऐसे आदेश की प्रमाणित प्रति या अपीलार्थी पर तामील किया गया आदेश होगी ।

(4) उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूपों में क्रम सं. 5 पर दिया गया पता, अपीलार्थी का "रजिस्ट्रीकृत पता" कहलाएगा और जब तक उसमें अधिकरण को दिए गए आवेदन द्वारा, सम्यक रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता वह अपील तथा अन्य संबंधित कार्यवाहियों में, जब तक कि अपील का अंतिम रूप से अवधारण नहीं हो जाता और उसके पश्चात् दो वर्ष की अवधि तक, सभी सूचनाओं, आदेशिकाओं और अन्य संसूचनाओं को तामील के प्रयोजन के लिए अपीलार्थी का पता समझा जाएगा ।

(5) प्रत्येक अपील में सक्षम प्राधिकारी को, जिसने वह आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा ।

(6) अपील का ज्ञापन अपीलार्थी द्वारा स्वयं या जहां एक से अधिक अपीलार्थी हैं वहां उनमें से ऐसे किसी एक के द्वारा या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष या ऐसे अन्य अधिकारी के समक्ष जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्रार को संबोधित रजिस्ट्री डाक से भेजा जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम में, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" पद के अन्तर्गत अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी विधि व्यवसायी या अकांउन्टेंट के नियोजनाधीन कोई व्यक्ति भी है।

(7) जब अपील का ज्ञापन रजिस्ट्री डाक से भेजा जाता है तब उक्त ज्ञापन की अधिकरण के कार्यालय पर पहुंच की तारीख अपील दाखिल करने की तारीख होगी और रजिस्ट्रार अपील के प्रत्येक ज्ञापन पर वह तारीख पृष्ठांकित करेगा जिसको वह अधिकरण के कार्यालय पर प्रस्तुत किया जाता है या प्राप्त होता है तथा पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा।

(8) जब अपील अपीलार्थी पर तामील किए गए आदेश की प्राप्ति के 45 दिन की समाप्ति के पश्चात किन्तु साठ दिन के अपश्चात दाखिल की जाती है तब उसके साथ एक शपथ पत्र से असमर्थित आवेदन होगा जिसमें उन तथ्यों का अधिकथन होगा जिन पर अपीलार्थी अधिकरण का यह समाधान करने के लिए निर्भर करता है कि पैंतालीस दिन के भीतर अपील न दाखिल करने के लिए पास उसके पास पर्याप्त हेतुक था ।

(9) अधिकरण के समक्ष दाखिल की गई प्रत्येक अर्जी के साथ, जिसके अंतर्गत रोकने की अर्जी भी है किन्तु औपचारिक या नेमी प्रकृति की अर्जियां नहीं हैं, एक शपथपत्र होगा और ऐसी दस्तावेजों की प्रतियां भी होंगी जिन पर वह अर्जी के समर्थन के लिए निर्भर है ।

6. अपीलों को रजिस्टर करने की प्रक्रिया—(1) सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तामील के पैंतालीस दिन के भीतर दाखिल प्रत्येक अपील ज्ञापन जो इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में हो और अन्यथा सही हो, इस प्रयोजन के लिए रखी गई बही में रजिस्टर किया जाएगा जो अपील रजिस्टर कहलाएगी और रजिस्ट्रार तदनुसार अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को संसूचित करेगा ।

(2) यदि उप नियम (1) के अंतर्गत दाखिल किया गया अपील ज्ञापन त्रुटिपूर्ण है किन्तु त्रुटियां गौण या तकनीकी प्रकृति की हैं तो रजिस्ट्रार अपील को अनन्तिम आधार पर रजिस्टर करेगा और अपीलार्थी को उन त्रुटियों को उतने समय के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, दूर करने के लिए कहेगा और ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्रुटियां दूर कर दिए जाने पर रजिस्ट्रीकरण अनन्तिम नहीं रहेगा और अपील उपनियम (1) के अधीन नियमित रूप से रजिस्टर की गई समझी जाएगी।

(3) जब अपील का ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तामील की तारीख से पैंतालीस दिन की समाप्ति पर किन्तु साठ दिन के भीतर दाखिल किया जाए और वह अन्यथा सही हो, तथा उसके साथ विलंब को माफ करने के लिए अर्जी दी गई है, तो उसे इस बात के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से संख्यांकित और रजिस्टर किया जाएगा कि अधिकरण को, प्रत्यर्थी को सूचना देने के पश्चात् और पक्षकारों को सुनने के पश्चात यदि यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने में पर्याप्त कारणों से निवारित रहा था और अधिकरण विलंब को माफ कर देता है और तब रजिस्ट्रीकरण अनन्तिम नहीं रहेगा और अपील का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो वह उपनियम (1) के अधीन रजिस्टर की गई थी ।

(4) जब अपील का ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तामील के पश्चात् पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात किन्तु साठ दिन की अवधि के भीतर दाखिल किया जाता है और उसके साथ विलंब को माफ करने की अर्जी नहीं दी जाती है तो रजिस्ट्रार अपील को अनन्तिम रूप से रजिस्टर कर सकता है और अपीलार्थी से, ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाए, विलम्ब को माफ करने की अर्जी दाखिल करने के लिए कह सकता है और इस प्रकार की अर्जी प्राप्त होने की दशा में उसका निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो वह अपील के ज्ञापन के साथ प्राप्त हुई थी और तब अपील का निपटारा अधिनियम (3) में विहित रूप से किया जाएगा।

(5) यदि इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता है या विलंब की माफी के लिए अर्जी दाखिल नहीं की जाती है तो मामला अधिकरण के समक्ष उसके आदेश के लिए रखा जाएगा ।

(6) यदि अपील के ज्ञापन की सारभूत विशिष्टियों में त्रुटि हो तो रजिस्ट्रार त्रुटियों को विनिर्दिष्ट कर सकता है और अपील के ज्ञापन को संशोधन करने के लिए तथा सुधार करने के पश्चात पुनः प्रस्तुत करने के लिए वापिस कर सकता है और जब अपील का ज्ञापन पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो उसका निपटारा इन नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(7) जब अपील का ज्ञापन प्रथम दृष्टया सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तामील की तारीख से साठ दिन से अधिक के पश्चात दाखिल किया गया प्रतीत हो तो अपील रजिस्टर नहीं की जाएगी अपितु रजिस्ट्रार अपीलार्थी से यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि अपीलार्थी कालातीत होने के कारण खारिज क्यों नहीं कर दी जाए।

(8) देरी की माफी का प्रत्येक आवेदन और समय के पश्चात् दाखिल किया गया प्रत्येक अपील का ज्ञापन अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा जो आवेदन/अपील को अधिकरण के समक्ष उसके आदेशों के लिए रखे जाने का निदेश दे सकेगा ।

7. अपील के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात प्रक्रिया—(1) अपील रजिस्ट्रीकृत हो जाने के पश्चात अपील के ज्ञापन और उसके उपाबंधों की एक प्रति, यथाशीघ्र, सक्षम प्राधिकारी को या तो पावती पत्र सहित रजिस्ट्री डाक से भेजकर या संदेशवाहक के माध्यम से तामील की जाएगी तथा पक्षकारों से सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो अनुज्ञात की जाए अपनी पेपर बुक दाखिल करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(2) प्रत्येक पक्षकार अपनी पेपर बुक की चार प्रतियां दाखिल करेगा—

(i) जो सुपाठ्य रूप से टाइप की गई या किसी यांत्रिक साधन से अन्यथा तैयार की गई होगी;

(ii) जिसमें वे सभी दस्तावेज होंगी जिन पर पक्षकार सुनवाई के अनुक्रम में निर्भर रहना चाहता है;

(iii) जिसमें केवल ऐसी दस्तावेजों और ऐसी सामग्री होगी जो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विनिष्ट या प्रस्तुत की गई हो या जिस पर निर्भर किया गया हो ;

(iv) जिसके पृष्ठ क्रमानुसार संख्यांकित होंगे; और ;

(v) जिसमें पूरी विषय-सूची या विषय धारणी होगी।

(3) यदि उपनियम (2) में निर्दिष्ट पेपर बुक में कोई दस्तावेज अंग्रेजी से या हिन्दी से भिन्न भाषा में है तो उसका अंग्रेजी या हिन्दी में सही अनुवाद भी जोड़ा जायेगा ।

(4) पक्षकारों को पावती पत्र सहित रजिस्ट्री डाक से या संदेशवाहक के माध्यम से सूचना तामील करके अपील की सुनवाई की तारीख और समय पक्षकारों को सूचित किया जायेगा।

परन्तु यदि पक्षकार अधिकरण के समक्ष हाजिर हैं तो अधिकरण उन्हें अपील की सुनवाई की तारीख और समय मौखिक रूप से सूचित कर सकता है ।

(5) साक्षियों या दस्तावेजों को समन करने के लिये किसी अर्जी पर, यदि आवश्यक हो तो, अन्य पक्षकार को सूचना देने के पश्चात् सुनवाई की जा सकती है ।

(6) अधिकरण द्वारा जारी की जाने वाली प्रत्येक अभ्यपेक्षा निर्देशपत्र, प्राधिकार पत्र या लिखित सूचना पर रजिस्ट्रार हस्ताक्षर करेगा और वह पावती पत्र सहित रजिस्ट्री डाक से या सन्देशवाहक के माध्यम से भेजा जायेगा या भेजी जाएगी ।

8. अपीलों की संयुक्त सुनवाई और निष्पादन : अधिकरण, जब भी वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, एक या अधिक अपीलों की सुनवाई एक साथ कर सकता है और उनका निष्पादन एक ही आदेश द्वारा कर सकता है ।

9. अपील के आधार: अपीलार्थी अधिकरण की अनुमति के सिवाय, ऐसे किसी आधार के समर्थन में, जो अपील के ज्ञापन में अधिकथित नहीं है, न तो तर्क कर सकता है और न सुना जायेगा, किन्तु अधिकरण अपील का विनिश्चय करने में, केवल उन आधारों तक स्वयं को सीमित नहीं रखेगा जिन्हें अपील के ज्ञापन में उपवर्णित किया गया है या जिनके लिये इस नियम के अधीन अधिकरण की अनुमति प्राप्त की गई है :

परन्तु अधिकरण अपना विनिश्चय अपील के ज्ञापन में वर्णित आधारों से भिन्न किसी ऐसे आधार पर तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस पक्षकार को जो उससे प्रभावित हो सकता है, उस आधार पर सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है

10. स्थगन—अधिकरण किसी मामले की सुनवाई किसी अन्य तारीख के लिये स्थगित कर सकेगा और पक्षकारों को मामले की सुनवाई की की आगामी तारीख और स्थान से सूचित करेगा।

11. अपीलार्थी के व्यतिक्रम के कारण अपील का खारिज किया जाना--यदि सुनवाई के लिये नियत किये गये दिन या किसी अन्य दिन जिस को सुनवाई स्थगित की गई हो, अपीलार्थी अपील की सुनवाई के के लिये पुकार किये जाने पर हाजिर नहीं होता है, तो अधिकरण व्यतिक्रम के कारण अपील को खारिज कर सकता है या उसकी एक पक्षीय सुनवाई के लिये अग्रसर हो सकता है।

परन्तु जहां अपील व्यतिक्रम के कारण खारिज की गई हो या उस पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई हो और अपीलार्थी तत्पश्चात् हाजिर हो जाता है और अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि सुनवाई के लिये पुकार किये जाने के समय उसके हाजिर न होने के लिये पर्याप्त हेतुक था, तो अधिकरण, प्रत्यर्थी को सूचना देने के पश्चात् खारिजी के आदेश को या एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त कर सकता है और अपील को उसके मूल संख्यांक पर पुनः रख सकता है।

12. मृत्यु, दीवालियापन आदि का अपील पर प्रभाव: (1) अपीलार्थी की मृत्यु या उसके दीवालिया न्यायनिर्णित किये जाने मात्र के कारण अपील उपशमित नहीं होगी।

(2) अधिकरण मृत अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा इस निमित्त आवेदन किये जाने पर उसे पक्षकार बना सकता है और अपील में आगे कार्रवाई कर सकता है।

(3) यदि अपीलार्थी की मृत्यु के नब्बे दिन के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो अधिकरण मृत अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख कर लाने के लिये अनुज्ञात करे, कोई आवेदन नहीं किया जाता है तो अपील उपशमित हो जायेगी।

(4) अपीलार्थी के दीवालिया हो जाने पर अपील लेनदारों के फायदे के लिये समनुदेशिती या रिसीवर द्वारा जारी रखी जा सकेगी तथा यदि समनुदेशिती या रिसीवर अपील को जारी रखने में असफल रहता है तो अधिकरण स्वप्रेरणा से या प्रत्यर्थी के आवेदन पर अपील को खारिज कर सकता है।

13. अधिकरण द्वारा मामले का प्रतिप्रेषण—(1) अधिकरण, जब भी वह आवश्यक समझे, सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश को अपास्त कर सकता है और मामले को ऐसे निदेशों को ध्यान में रखते हुए जैसे वह दे, पुनः अवधारण के लिये सक्षम प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकता है।

(2) अधिकरण यदि कार्यवाई के किसी अनुक्रम पर आवश्यक समझता है तो, ऐसे विषयों पर जो वह विनिर्दिष्ट करे, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट या उसके निष्कर्ष मांग सकता है।

(3) उप नियम (2) के अधीन निर्दिष्ट किसी ऐसी रिपोर्ट या निष्कर्ष की प्रति पक्षकारों को दी जायेगी और इसके पूर्व कि अधिकरण अंतिम आदेशों की घोषणा करे, उन पर पुनः सोचा जायेगा।

14. अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना--(1) पक्षकार, अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे किन्तु निम्नलिखित दशाओं में अधिकरण ऐसा साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत करने या साक्षियों की परीक्षा करने की अनुज्ञा दे सकता है, अर्थात्:--

(क) जहां सक्षम प्राधिकारी ने, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल की गई है, किसी ऐसे साक्ष्य को ग्रहण करने से इंकार कर दिया हो तो जो ग्रहण किये जाना चाहिये था, या

(ख) जहां अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रार्थना करने वाला पक्षकार यह सिद्ध कर देता है कि सम्यक् तत्परता बरते जाने पर भी ऐसा साक्ष्य उनकी जानकारी में नहीं था या, सम्यक् तत्परता बरते जाने के पश्चात् भी वह उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब वह आदेश पारित किया गया था जिसके विरुद्ध अपील की गई है, या

(ग) जब अधिकरण उसे आदेश घोषित करने में समर्थ बनाने के लिये, या किसी अन्य तात्विक कारण से, कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या किसी साक्षी का परीक्षण करने की अपेक्षा करता है, या

(घ) जब अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने मामले का विनिश्चय अपीलार्थी को उस विषय पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किये बिना किया है।

(2) अधिकरण जहां भी अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देता है वहां वह उसे ग्रहण करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

15. अपील की सुनवाई—अपीलों की सुनवाई के प्रयोजनों के लिये अधिकरण की बैठक का स्थान खुला न्यायालय समझा जायगा जहां साधारणतः जनता की पहुंच वहां तक हो सकेगी जहां तक वहां उनके लिये सुविधाजनक स्थान है:

परन्तु अधिकरण, यदि वह ठीक समझता है तो, अपील की सुनवाई के किसी अनुक्रम पर यह आदेश कर सकता है कि साधारणतया जनता, या कोई व्यक्ति विशेष, अधिकरण द्वारा उपयोग किये जा रहे कक्ष या भवन में नहीं जायेगा या वहां नहीं रहेगा या सकेगा।

16. आदेश का सुनाया जाना--सुनवाई की समाप्ति पर अधिकरण तुरन्त अपना आदेश सुना सकेगा या अपने आदेश आरक्षित रखे जाते हैं तो अधिकरण अंतिम आदेश सुनाने के पूर्व किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर यह आदेश कर सकेगा कि अपील या अर्जी की पुनः सुनवाई की जाये।

17. आदेश का पक्षकारों को संसूचित किया जाना—अधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और अधिकरण के प्रत्येक अंतिम आदेश की प्रति, जो रजिस्ट्रार द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गई हो, पक्षकारों को, यथासंभव शीघ्र, निःशुल्क दी जायेगी।

18. आदेशों पर हस्ताक्षर —(1) यदि विनिश्चय पर अधिकरण के सभी सदस्य सहमत हों तो अधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा एक ही आदेश पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(2) जहां राय भिन्न हों, वहां विनिश्चय अधिकरण के सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

(3) जो सदस्य बहुमत के विनिश्चय से सहमत नहीं है वह असहमति का आदेश पृथक दे सकेगा।

(4) बहुमत का विनिश्चय लिखित रूप में दिया जायेगा और उस पर सभी सदस्यों द्वारा, जिनमें असहमत सदस्य भी भी हैं, हस्ताक्षर किये जायेंगे।

19. आदेशों का प्रकाशन—अधिकरण के ऐसे आदेश जिन्हें किसी प्राधिकृत रिपोर्ट या समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिये उपयुक्त समझा जाता है, ऐसे प्रकाशन के लिये, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो अधिकरण अधिकथित करे, दिये जा सकेंगे।

20. कतिपय मामलों में आदेश और निदेश—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी अधिकरण अपने आदेशों को प्रभावी करने के लिये या अपनी आदेशिकाओं का दुरुपयोग निवारित करने के लिये या न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिये ऐसे आदेश या निदेश दे सकेगा जिसे वह आवश्यक या समीचीन समझें।

21. निरसन और व्यावृत्ति—(1) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण) नियम, 1977 निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपनियम (1) में निर्दिष्ट नियमों में से किसी के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

प्ररूप

(नियम 5 और 6 देखिए)

समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष

अपील का ज्ञापन

[तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 12]

---

19 का स०स०अ०सं०/प्र०अ०सं०

(अपील अधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

श्री/श्रीमती————————— अपीलार्थी

————————————

————————————

बनाम

(1) सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली/*बम्बई/कलकत्ता/मद्रास/अहमदाबाद —प्रत्यर्थी

(2) अन्य प्रत्यर्थी, यदि कोई हैं——————————

1. वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है। : सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली/*बम्बई/कलकत्ता/मद्रास/अहमदाबाद

2. आदेश की तारीख :

3. आदेश की तामील की तारीख :

4. विनिर्दिष्ट करें कि सुनवाई व्यक्तिगत रूप से वांछित है या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से। :

5. अपीलार्थी का रजिस्ट्रीकृत पता (जिसके अन्तर्गत फोन नं०, यदि कोई है) जिस पर सभी सूचनायें, आदेशिकायें और संसूचनायें तामील की जायेंगी। :

6. प्रत्यर्थी का पता : (1) सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली/*बम्बई/कलकत्ता/मद्रास/अहमदाबाद।

: (2) अन्य प्रत्यर्थी, यदि कोई हैं ——————

————————

————————

7. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की वह धारा या धारा की उपधारा जिसके अधीन सक्षम प्राधिकारी ने आदेश किये हैं और जिसके विरुद्ध अपील की गई है। :

8. वांछित अनुतोष :

(1) क्या पूरा आदेश विवादग्रस्त है

(2) यदि सम्पत्ति की केवल कुछ मदें विवादग्रस्त हैं तो उन्हें उपाबन्ध में दीजिये।

9. अपील के आधार (यदि स्थान पर्याप्त नहीं है तो प्रथम पृष्ठ लगाइये)

————————————

(हस्ताक्षर अपीलार्थी)

————————————

(हस्ताक्षर प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि कोई है)

सत्यापन

मैं,————————————————, अपीलार्थी/अपीलार्थी का प्राधिकृत प्रतिनिधि घोषित करता हूं कि ऊपर जो कुछ कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज तारीख————————को सत्यापित किया।

स्थान :——————————(अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि

तारीख :—————————— के हस्ताक्षर)

*जो लागू न होता हो उसको काट दीजिए।

टिप्पण : 1. अपील का ज्ञापन चार प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिये और उसके साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, चार प्रतियां होंगी (जिनमें से एक उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है अपीलार्थी पर तामील की गई मूल प्रति या उसकी प्रमाणित प्रति होगी)। सभी संलग्नक भी चार प्रतियों में होंगे।

2. अपील का ज्ञापन अंग्रेजी या हिन्दी में लिखा जाना चाहिये और उसमें अपील के आधार संक्षिप्त और भिन्न शीर्षों के अधीन दिये जाने चाहिये तथा उसमें कोई तर्क या विवरण नहीं दिये जाने चाहिए और ऐसे आधारों को क्रमानुसार संख्यांकित किया जाना चाहिये।

3. अन्य ब्यौरों के लिये कृपया समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 देखें।

[फा०सं० 91/सामान्य/ससमअ/86]

समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण के आदेश से,

बी० चक्रवर्ती, रजिस्ट्रार

APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED PROPERTY

New Delhi, the 14th April, 1986

S.O. 1547.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Appellate Tribunal for Forfeited Property hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Procedure) Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976);

(b) "appeal" means an appeal filed under sub-section (4) of section 12;

(c) "appellant" means a person who, being aggrieved by an order made by the competent authority, prefers an appeal to the Tribunal, and includes the authorised representative of the appellant;

(d) "authorised representative" means—

(i) in relation to an appellant,

(A) any person being a relative of, or a person who is, or was, regularly employed by the appellant and authorised in writing by the appellant to attend before the Tribunal; or

(B) a legal practitioner entitled to practise in any civil court in India, who is authorised in writing by the appellant to attend before the Tribunal; or

(C) an accountant, being a member of the Institute of Chartered Accountants of India constituted under section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) or the Institute of Cost and Works Accountants of India constituted under section 3 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), who is authorised in writing by the appellant to attend before the Tribunal, or

(ii) in relation to a competent authority who is a party to any proceedings before the Tribunal:

(A) a Law Officer of the Central Government;

(B) a Government Pleader or Standing Counsel to the Central Government by whatever name called;

(C) any Officer of the Central Government notified in this behalf by the Central Government by notification in the Official Gazette;

(D) any legal practitioner or Officer of the Central Government authorised in this behalf by the Central Government or the competent authority;

(E) any other legal practitioner or Officer of the Central Government acting on behalf of the person so notified or authorised;

(e) "Bench" means a Bench of the Tribunal constituted under sub-section (6) or (6A) of section 12;

(f) "Chairman" means the Chairman of the Tribunal;

(g) "competent authority" means a competent authority as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 3;

(h) "legal representative" means a person who in law represents the estate of a deceased person, and includes any person treated by the Tribunal as representing the deceased person in the proceedings pending before the Tribunal;

(i) "member" means a member of the Tribunal and includes the Chairman;

(j) "party" in relation to an appeal, means an appellant or the respondent and the expression "parties" shall be construed to mean the appellant and the respondent;

(k) "registrar" means the registrar of the Tribunal and includes such other officer who is authorised by the Chairman to perform the functions of the registrar;

(l) "section" means a section of the Act;

(m) "Tribunal" means the Appellate Tribunal for Forfeited Property, constituted by the Central Government under sub-section (1) of section 12.

3. Language of the Tribunal.—(1) The pleadings before the Tribunal may, at the option of the respective parties, be in English or in Hindi.

(2) All orders and other proceedings of the Tribunal may, at the option of the Tribunal, be in English or in Hindi.

4. Headquarters of the Tribunal, etc.—(1) The headquarters of the Tribunal shall be at New Delhi.

(2) Appeals and petitions may be heard at the headquarters or at the discretion of the Chairman at Bombay, Madras, Calcutta, Ahmedabad, or any other place.

(3) The office of the Tribunal shall observe such public and other holidays as are observed by the offices of the Central Government.

5. Procedure for filing appeals and petitions.—(1) Any person aggrieved by an order of the competent authority made under section 7 or sub-section (1) of section 9 or section 10 of the Act may prefer an appeal to the Tribunal and every memorandum of appeal shall be in the form annexed to these rules.

(2) A memorandum of appeal shall be in English or in Hindi and shall set forth concisely and under distinct heads the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds shall be numbered consecutively.

(3) Every memorandum of appeal or petition shall be in quadruplicate and in the case of a memorandum of appeal it shall be accompanied by four copies of the order appealed against and one of such copies shall be a certified copy of such order, or the order served on the appellant.

(4) The address given at serial number 5 of the form appended to these rules as referred to in sub-rule (1) shall be called the "registered address" of the appellant and shall until duly changed by an application to the Tribunal be deemed to be the address of the appellant for the purpose of the service of all notices, processes and other communications in the appeal and other connected proceedings till the final determination of the appeal and a period of two years thereafter.

(5) In every appeal, the competent authority which passed the order appealed against, shall be impleaded as one of the respondents.

(6) A memorandum of appeal shall be presented by the appellant in person or when there are more appellants than one by any one of them or by his authorised representative to the registrar or such other officer as may be authorised in this behalf by the Chairman or may be sent by registered post addressed to the registrar.

Explanation.—In this sub-rule, the expression "authorised representative" shall include any person in the employment of a legal practitioner or an accountant who is authorised to appear on behalf of the appellant.

(7) When a memorandum of appeal is sent by registered post, the date of receipt of the said memorandum at the office of the Tribunal shall be the date of filing of the appeal and the registrar shall on every memorandum of appeal, endorse the date on which it is presented or received at the office of the Tribunal and shall sign the endorsement.

(8) When an appeal is presented after the expiry of forty-five days of the receipt of the order served upon the appellant but not after sixty days, it shall be accompanied by an application supported by an affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the Tribunal that he had sufficient cause for not preferring the appeal within forty-five days.

(9) Every petition presented to the Tribunal including a petition for stay other than petitions of a formal or routine character, shall be accompanied by an affidavit as also copies of such documents as are relied on in support of the petition.

6. Procedure for registration of appeals.—(1) Every memorandum of appeal filed within forty-five days of service of the order of the competent authority, being in the form annexed to these rules and otherwise in order, shall be registered in a book kept for the purpose called the Register of Appeals and the registrar shall intimate the appellant or his authorised representative accordingly.

(2) If a memorandum of appeal filed under sub-rule (1) is defective, but the defects are minor or technical in character, the registrar may register the appeal provisionally and call upon the appellant to remove the defects within such time as may be specified and upon the defects being removed within such specified time, the registration shall cease to be provisional and the appeal shall be deemed to have been regularly registered under sub-rule (1).

(3) When the memorandum of appeal is presented after the expiry of forty-five days but within a period of sixty days after the date of service of the order of the competent authority, and is otherwise in order, and is accompanied by a petition for condonation of delay, it shall be numbered and registered provisionally subject to the delay being condoned by the Tribunal after notice to the respondent and after hearing the parties, if the Tribunal considers that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time and condones the delay, the registration shall cease to be provisional and the appeal dealt with as though it had been registered under sub-rule (1).

(4) When the memorandum of appeal is presented after the expiry of forty-five days but within a period of sixty days after the date of service of the order of the competent authority, and is not accompanied by a petition for condonation of delay, the registrar may register the appeal provisionally and call upon the appellant to file a petition for condonation of delay within such time as may be specified and in the event of such a petition being received, it shall be treated as having been received alongwith the memorandum of appeal and the appeal dealt with in the manner prescribed in sub-rule (3).

(5) When the defects are not removed or a petition for condonation of delay is not filed within the time specified in that behalf, the matter shall be placed before the Tribunal for its orders.

(6) Where a memorandum of appeal is defective in material particulars, the registrar may specify the defects and return it for being amended and represented after remedying them and when the memorandum of appeal is represented, it shall be dealt with in accordance with these rules.

(7) When a memorandum of appeal on the face of it appears to have been filed more than sixty days after the date of service of the order of the competent authority on the appellant, the appeal shall not be registered but the appellant shall be called upon by the registrar to show cause why the appeal should not be dismissed as being out of time.

8. Every petition for condonation of delay and every memorandum of appeal filed out of time shall be placed before the Chairman who may direct the petition/appeal to be posted before the Tribunal for its orders.

7. Procedure after registration of appeal.—(1) After an appeal is registered, one copy of the memorandum of appeal and annexures thereto shall be served, as soon as possible, on the competent authority either by registered post acknowledgement due, or through a messenger and the parties shall be called upon to file their paper-books within a period of thirty days from the date of receipt of the notice or such further time as may be allowed.

(2) Each party shall file four copies of his paper-book which shall—

(i) be legibly typed or otherwise reproduced by mechanical means;

(ii) contain all documents upon which a party proposes to rely during the course of hearing;

(iii) contain only such documents and material as have been referred to, produced or relied upon before the competent authority;

(iv) have pages numbered serially; and

(v) contain a full index or table of contents.

(3) If the paper-book referred to in sub-rule (2) contains any document in a language other than English or Hindi, a true translation thereof in English or Hindi shall be added.

(4) The parties shall be informed of the date and place of hearing of the appeal either by registered post acknowledgement due or by notice served on them through messenger:

Provided that where the parties are present before the Tribunal, it may inform them orally of the date and place of hearing of the appeal.

(5) Any petition for summoning witnesses or documents filed by a party may be heard, if necessary, after giving notice to the other party.

(6) Every requisition, direction, letter, authorisation, or written notice to be issued by the Tribunal shall be signed by the registrar and shall be sent by registered post acknowledgement due or through a messenger.

8. Joint hearing and disposal of appeals.—The Tribunal may, whenever it considers necessary or expedient to do so, hear one or more appeals together and dispose of them by a common order.

9. Grounds which may be taken in appeal.—The appellant shall not, except with the leave of the Tribunal, urge or be heard in support of any ground not set forth in the memorandum of appeal but the Tribunal, in deciding the appeal, shall not be confined to the grounds set forth in the memorandum of appeal or taken with the leave of the Tribunal under this rule:

Provided that the Tribunal shall not rest its decision on any ground other than the grounds set forth in the memorandum of appeal unless the party which may be affected thereby has had a reasonable opportunity of being heard on that ground.

10. Adjournment.—The Tribunal may adjourn the hearing of any case to any other date and inform the parties of the next date and place of hearing of the case.

11. Dismissal of appeal for appellant's default.—Where on the day fixed for hearing or on any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called on for hearing, the Tribunal may either dismiss the appeal for default or proceed ex-parte:

Provided that where the appeal has been dismissed for default or proceeded with ex-parte and the appellant appears thereafter and satisfies the Tribunal that there was sufficient cause for his non-appearance when the appeal was called on for hearing, the Tribunal shall, after giving notice to the respondent, make an order setting aside the dismissal order or the ex-parte proceedings and restoring the appeal to its original number.

12. Effect of death, insolvency, etc. on appeal.—(1) An appeal shall not abate by reason only of the death of an appellant or on his adjudication as an isolvent.

(2) The Tribunal may on an application made in this behalf by the legal representative of the deceased appellant make him a party and proceed with the appeal.

(3) When no application is made within ninety days of the death of an appellant or within such further time as the Tribunal may allow for bringing his legal representative on record, the appeal shall abate.

(4) On the insolvency of an appellant, the appeal may be continued by the assignee or the receiver for the benefit of creditors and if the assignee or the receiver fails to continue the appeal, the Tribunal may on its own motion or on the application of the respondent, dismiss the appeal.

13. Remand of case by the Tribunal.—(1) The Tribunal may, whenever it considers it necessary, set aside an order of the competent authority and remand the case to the competent authority for fresh determination in the light of such directions as it may give.

(2) The Tribunal may if it considers necessary at any stage of the proceedings call for a report or finding from the competent authority on such matters as it may specify.

(3) A copy of any such report or finding referred to under sub-rule (2) shall be furnished to the parties and they shall be heard thereon before the Tribunal pronounces final orders.

14. Production of additional evidence before the Tribunal.—(1) The parties to an appeal shall not be entitled to

produce additional evidence, whether oral or documentary, before the Tribunal, but, however, where—

(a) the competent authority from whose order the appeal is preferred has refused to admit evidence which ought to have been admitted, or

(b) the party seeking to produce additional evidence, establishes that notwithstanding the exercise of due diligence, such evidence was not within his knowledge or could not, after the exercise of due diligence, be produced by him at the time when the order appealed against was passed, or

(c) the Tribunal requires any document to be produced or any witness tools be examined to enable it to pronounce orders, or for any other substantial cause, or

(d) the Tribunal is satisfied that the competent authority has decided the case without giving a reasonable opportunity to the appellant to adduce evidence on any point,

it may allow such evidence or document to be produced, or witness to be examined.

(2) Wherever additional evidence is allowed to be produced by the Tribunal, it shall record the reason for its admission.

15. Hearing of appeals.—The places in which the Tribunal sits for the purpose of hearing appeals shall be deemed to be an open court, to which the public generally may have access so far as the same can conveniently contain them :

Provided that the Tribunal may, if it thinks fit, order at any stage of the hearing of an appeal, that the public generally, or any particular person, shall not have access to, or be or remain in, the room or building used by the Tribunal.

16. Pronouncement of order.—After the hearing is over, the Tribunal may pronounce its orders forthwith, or it may reserve its orders and if the orders are reserve, the Tribunal may at any time before final orders are pronounced either on its own motion or on the application of a party order that the appeal or petition be re-heard.

17. Order to be communicated to parties.—Every order of the Tribunal shall be in writing and a copy of every final order of the Tribunal certified as a true copy by the registrar shall be supplied free of cost to the parties as early as possible.

18. Signing of orders.—(1) Where the decision of the Tribunal is unanimous, a common order shall be signed by all the members of the Tribunal.

(2) Where there is a difference of opinion, the decision shall be in accordance with the decision of the majority of the members of the Tribunal.

(3) A member who does not concur with the decision of the majority may deliver a dissenting order.

(4) The decision of the majority shall be reduced to writing and signed by all the members including the dissenting member.

19. Publication of orders.—Such of the orders of the Tribunal as are deemed fit for publication in any authoritative report or the press may be released for such publication on such terms and conditions as the Tribunal may lay down.

20. Orders and directions in certain cases.—Notwithstanding anything contained in these rules, the Tribunal may make such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to its orders or to prevent abuse of its process or to secure the end of justice.

21. Repeal and saving.—(1) The Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Appellate Tribunal for Forfeited Property) Rules, 1977, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of any of the rules referred to in sub-rule (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Procedure) Rules, 1986.

FORM

(See rules 5 and 6)

BEFORE THE APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED PROPERTY, NEW DELHI

MEMORANDUM OF APPEAL

[Section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976]

F.P.A.No./M.P.No. of 19

To be filled up by the office of the Appellate Tribunal

IN THE MATTER OF

Shri/Smt. _____ APPELLANT.

Vs.

(i) The Competent Authority, New Delhi*/Bomnay/Calcutta/Madras/Ahmedabad. RESPONDENTS.

(ii) Other respondents, if any _____

1. Authority passing the order appealed against. : Competent Authority, New Delhi*/Bombay/Calcutta/Madras/Ahmedabad.
2. Date of the order.
3. Date of service of the order.
4. Specify whether a hearing in person or through an authorised representative is desired.
5. Registered address of the appellant (including telephone No., if any) for the service of all notices, processes and communications:
6. Address of the Respondent. (i) The Competent Authority, New Delhi*/Bombay/Calcutta/Madras/Ahmedabad.
   (ii) Other respondents, if any.
7. Section or sub-section of the section of the Smugglers & Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976, under which the Competent Authority passed the order and which is appealed against:

8. Relief claimed:

(i) Specify whether the entire order is disputed:

(ii) If only certain items of properties are disputed, enumerate them in an annexure:

9. Ground of appeal (Annex a separate sheet if space is not sufficient):

(Signature of Appellant)

(Signature of Authorised Representative, if any)

VERIFICATION

I,————————————————————, the appellant/authorised representative of the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge, information and belief.

Verified to-day the————————————day of————————————19 .

Place: ————————

Date: ————————

(Signature of the appellant or his authorised representative)

*Strike out whatever is inapplicable.

Notes: 1. The memorandum of appeal should be filed in quadruplicate accompanied by four copies of orders appealed against (one of which shall be a certified copy of the order appealed against or the original copy of it served on the appellant). Any enclosure will also be in quadruplicate.

2. The memorandum of appeal should be written in English or in Hindi and should set forth concisely and under distinct heads the grounds of appeal and should be without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.

3. It is enough if the memorandum of appeal is signed either by the appellant or the authorised representative. Where it is signed by the authorised representative, it should be accompanied by an authorisation of the appellant in his favour.

4. For further details see the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Procedure) Rules, 1986.

[F.No.91/Genl/ATFP/86]

By Order of the Appellate Tribunal for Forfeited Property

B. CHAKRAVARTY, Registrar

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1986

का.आ. 1548:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) के अनुसरण में, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (पहला संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 के उपनियम (2) में "यात्रा भत्ता" से संबंधित क्रम सं. 4 की प्रविष्टि के पश्चात् "4क वैज्ञानिकों की विदेश में प्रतिनियुक्ति या विदेश यात्रा" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी।

3. उक्त नियमों में नियम 10 में उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(7) संसद द्वारा यथा अनुमोदित बजट में उपबंधित निधियों से अधिक निधियां विनियोग की प्रायमिक यूनिट "वैज्ञानिक की विदेश में प्रतिनियुक्ति या विदेश यात्रा" से या को विनियोजित या पुनर्विनियोजित नहीं की जाएंगी"।

4. उक्त नियमों की अनुसूची 5 के उपबंध में क्रम सं. 26(क) के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"26(क)	(1) सभी कार्यालय उपस्कर जिसके अन्तर्गत टाइपराइटर, अन्तरासंचार उपस्कर, गणक, इलैक्ट्रानिक स्टेन्सिल कटर, डिक्टाफोन, टेपरिकार्डर, फोटो कापियर, कोपीइंग मशीन, फैंकिंग मशीन, ऐड्रेसोग्राफ, संचिकायन और सूचीकरण प्रणालियां, आदि भी हैं किन्तु किसी भी प्रकार के कम्प्यूटर सम्मिलित नहीं हैं।	पूरी शक्तियां	(1) ऐसी मशीनों के क्रय करने, भाड़े पर लेने, रखरखाव करने, और मरम्मत करने पर होने वाले व्यय वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए उपगत किए जाएंगे। (2) कार्यालयों के प्रधान भी निम्नलिखित सीमाओं तक इस संबंध में अधिकथित साधारण शर्तों के पालन करने के अधीन रहते हुए इस संबंध में व्यय उपगत कर सकते हैं:— आवर्ती 500 रुपए अनावर्ती 5,000 रुपए
	(2) व्यक्तिगत कम्प्यूटर	10,000 रु.	मंत्रालय/विभाग को 5 लाख रुपए की अधिकतम वित्तीय सीमा तक व्यक्तिगत संगणक क्रय करने की शक्ति होगी जिससे अधिक व्यय के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग से आदेश लेना आवश्यक होगा।"

5. उक्त नियमों की अनुसूची 6 में, टिप्पणी के नीचे टिप्पणी में "एक रुपया और पचास पैसे" शब्दों और "500 रुपए" "अंकों और शब्दों के स्थान पर क्रमशः "2.50 रुपए" और "10,000 रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

टिप्पणी : वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 अधिसूचना सं. का.आ. 2131 तारीख 22 जुलाई, 1978 के अधीन प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् उनके निम्नलिखित संशोधन किए गए :--

(1) अधिसूचना सं. का.आ. 1887, तारीख 9-6-1979
(2) " सं. का.आ. 2942, तारीख 1-9-1979
(3) " सं. का.आ. 2611, तारीख 4-10-1980
(4) " सं. का.आ. 2164, तारीख 15-8-1981
(5) " सं. का.आ. 2304, तारीख 5-9-1981
(6) " सं. का.आ. 3073, तारीख 4-9-1982
(7) " सं. का.आ. 4171, तारीख 11-12-1982
(8) " सं. का.आ. 1314, तारीख 26-2-1983
(9) " सं. का.आ. 2502, तारीख 4-8-1984
(10) " सं. का.आ. 22, तारीख 5-1-1985
(11) शुद्धिपत्र सं. का.आ. 1958, तारीख 11-5-1985
(12) अधिसूचना सं. का.आ. 3082, तारीख 6-7-1985
(13) " सं. का.आ. 3974, तारीख 24-8-1985
(14) " सं. का.आ. 5641, तारीख 21-12-1985

[सं. एफ. 1(11)-ई-2 (ए) /85]

आर.एल. चौधरी, अवर सचिव

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 4th April, 1986

S.O. 1548.—In pursuance of clause (3) of article 77 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules further to amend the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, namely:—

1. (1) These rules may be called the Delegation of Financial Powers (First Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 8 of the Delegation of Financial Powers Rules 1978 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2) after entry at serial No. 4 relating to "Travel Expenses" the entry "4A. Deputation or Travel abroad of Scientists" shall be inserted.

3. In rule 10 of the said rules, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(7) Funds shall not be appropriated or re-appropriated from or to the primary unit appropriation "Deputation or Travel abroad of Scientists" over and above the funds provided for in the budget as approved by Parliament".

4. In Schedule V to the said rules, in the Annexure, for Serial No. 26(a), the following Serial No. shall be substituted namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"26(a)	(1) All office equipments including typewriters, intercom equipments, calculators, electronic stencil cutters, dictaphones, tape recorders, photo copiers, copying machines, franking machines, addressographs, filling and indexing systems, etc. excluding computers of all kinds.	Full powers.	(1) The expenditure on the purchase, hire, upkeep of and repairs to such machines shall be incurred subject to general or special orders issued by the Ministry of Finance or Department of Supply from time to time in this behalf. (2) Heads of Offices may also incur expenditure in this regard subject to the observance of general conditions laid down in this regard upto the following limits:— Recurring Rs. 500 Non-recurring Rs. 5,000
	(ii) Personal computers	Rs. 10,000/-	Ministry/-Department shall have power for purchase of personal computers upto the monetary ceiling of Rs. 5 lakhs beyond which clearance from Department of Electronics shall be necessary".

5. In Schedule VI to the said rules, in the Note below the Table, for the words "rupees one and paise fifty" and the word and figures "Rs. 500", the words and figures "Rs. 2,50" and "Rs. 10,000" shall, respectively, be substituted.

Note: The Delegation of Financial Powers Rules, 1978 published *vide* Notification No. SO. 2131, dated July 22 1978 have subsequently been amended by:—

(i) Notification No. SO. 1887, dated 9-6-1979.
(ii) ,, No. SO. 2942, dated 1-9-1979.
(iii) ,, No. SO. 2611, dated 4-10-1980.
(iv) ,, No. SO. 2164, dated 15-8-1981.
(v) ,, No. SO. 2304, dated 5-9-1981.
(vi) ,, No. SO. 3073, dated 4-9-1982.
(vii) ,, No. SO. 4171, dated 11-12-1982.
(viii) ,, No. SO. 1314, dated 26-2-1983.
(ix) ,, No. SO. 2502, dated 4-8-1984.
(x) ,, No. SO. 22, dated 5-1-1985.

(xi) Corrigendum No. SO. 1958, dated 11-5-1985
(xii) Notification No. SO. 3082, dated 6-7-1985.
(xiii) ,, No. SO. 3974, dated 24-8-1985.
(xiv) ,, No. SO. 5641, dated 21-12-1985.

[No. F. 1(ii)E II (A)/85]

R.L. CHAUDHRY, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1986

का. आ. 1549.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10-ख की उपधारा (1) और (2) के उपबंध जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड, श्रीनगर पर 6 मार्च, 1986 से 5 जून, 1986 तक की तीन महीने की अवधि के वास्ते, अथवा जब तक इस बैंक के लिए नियमित पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती, इनमें से जो भी पहले हो, लागू नहीं होंगे ।

[संख्या 15/4/85-बी. ओ. -3(1)]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 1st April, 1986

S.O. 1549.—In exercise of the powers, conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of sub-section (1) and (2) of section 10-B of the said Act, shall not apply to the Jammu and Kashmir Bank Ltd., Srinagar for a period of 3 months from 6th March, 1986 to 5th June, 1986 or till the appointment of a regular whole-time Chairman for that Bank, whichever is earlier.

[No. 15/4/85-B.O.III(i)]

का. आ. 1550.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10-ख की उपधारा (9) के उपबन्ध, जहां तक उनका सम्बन्ध अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए बैंक द्वारा चार महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने की मनाही से है, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड, श्रीनगर पर 5 जून, 1986 तक लागू नहीं होंगे ।

[संख्या 15/4/85-बी. ओ. -3(2)]

S.O. 1550.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of sub-section (9) of Section 10-B of the said Act shall not, to the extent they preclude the bank from appointing a person to carry out the duties of a Chairman beyond a period exceeding four months, apply to the Jammu and Kashmir Bank Ltd., Srinagar, upto the 5th June, 1986.

[No. 15/4/85-B.O.III(ii)]

नई दिल्ली, 17/31 मार्च, 1986

का. आ. 1551.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंध 8 जून, 1987 तक की और अवधि तक यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि इनका संबंध मैसर्स लुज इलैक्ट्रिकल्स प्रा. लि. के शेयरों की इसकी धारिता से है ।

[संख्या 15/23/84-बी. ओ. -3]

एम. एस. सीतारामन, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 1986

S.O. 1551.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to the United Bank of India, Calcutta for a further period till 8th June, 1987 insofar as they relate to its holding of the shares in the Luz Electricals Private Ltd.

[No. 15/23/84-BO.III]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1986

का० आ० 1552.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स दिल्ली टेस्ट हाऊस, सोनू इन्डस्ट्रीयल एस्टेट जी० टी० करनाल रोड़, दिल्ली-110033 इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार खनिज तथा अयस्कों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए अभिकरण के रूप में 5 अप्रैल, 1986 से एक और वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है ।

अनुसूची

1. फैरोमैंगनीज के धातु मल सहित फैरोमैंगनीज
2. निस्तप्त बॉक्साइड सहित बॉक्साईट
3. मैंगनीज डायक्साइड
4. कायनाइट
5. सिलीमेनाइट
6. संकेन्द्रित जिंक सहित कच्चा जिंक
7. परिष्कृत और निस्तप्त मैंगनेसाइट सहित मैंगनेसाइट
8. बैराइटिस
9. लाल ऑक्साइड
10. पीला गैरिक
11. सेलखंडी
12. स्पतीय (फैल्डस्पार)

[फा० सं० 5/10/83-ईआई एण्ड ईपी]

एन० एन० हरिहरन, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 19th April, 1986

S.O. 1552.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 5th April, 1986 M/s. Delhi Test House, Sohna Industrial Estate, G.T. Karnal Road, Delhi-110033 as an agency for the inspection of Minerals & Ores as specified in schedule annexed hereto prior to export.

SCHEDULE

1. Ferromanganese, including ferromanganese slag
2. Bauxite, including calcined bauxite

3. Manganese Dioxide
4. Kyenite
5. Sillimanite
6. Zinc Ores, including zinc concentrates
7. Magnasite, including dead burnt and calcined magnesite
8. Barytes
9. Red Oxide
10. Yellow Ochre
11. Steatite
12. Feldsper.

[F. No. 5/10/83-EI&EP]
N. S. HARIHARAN, Director

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1986

का. आ. 1553.—द दून स्कूल, देहरादून को अंबिका चैरिटेबल फाऊंडेशन, लंदन द्वारा उपहार प्राप्त होने पर 60 सं. के सिंक्लेयर माइक्रो-कम्प्यूटर माडल 2×81 के आयात के लिए 49,500/- रु. का एक सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3052529/एन/एम एन/96/एच/85/एम. एल. एस. दिनांक 25-9-1985 इसके जारी करने की तारीख से 9 महीने की वैधता की अवधी के लिए दिया गया था । अब स्कूल ने उक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रायोजन प्रति जारी करने का इस आधार पर आवेदन किया है कि सीमाशुल्क निकासी परमिट की मूल प्रति खो गई है । लाइसेंसधारक ने आवश्यक शपथपत्र दाखिल किया है जिसके अनुसार उक्त सीमा शुल्क निकासी परमिट का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है तथा सीमाशुल्क निकासी परमिट का शेष 49,500/- रु. है । शपथपत्र में इस बारे में भी घोषणा की गई है कि यदि बाद में उक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट मिल जाता है तो इसे जारी करने वाले प्राधिकारी को लोटा दिया जाएगा । इस बारे में संतुष्ट होने पर कि उक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की मूल प्रति खो गई है, अधोहस्ताक्षरी यह आदेश देता है कि आवेदक को सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रायोजन प्रति जारी की जाए । मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 की उप-धारा 9(घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क निकासी परमिट की मूल सीमाशुल्क प्रायोजन प्रति को एतद्द्वारा रद्द करता हूं ।

[फा. सं. 3/14/85-86/एम.एल.एस./3]
एन. एस. कृष्णामूर्ति, उप मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 2nd April, 1986

S.O. 1553.—The Doon School, Dehra Dun, was granted a CCP No. P|J|3052529|N|MN|96|H|85|MLS, dated 25-9-1985 for import of 60 Nos. Sinclair Micro-Computers Model 2×81 being gifted to them by Ambika Charitable Foundation, London, valuing Rs. 49,500 with a validity period of Nine months from the date of issue. Now the School have applied for grant of a Duplicate Copy of the Customs Purposes Copy of aforesaid CCP on the ground that the subject copy of the CCP has been lost. The licensee has furnished necessary Affidavit according to which the aforesaid CCP has not been utilised at all and the balance against the CCP is Rs. 49,500. A declaration has also been incorporated in the affidavit to the effect that if the said CCP is traced or found later on, it will be returned to the issuing authority. On being satisfied that the original Customs Purposes Copy of the aforesaid CCP has been lost, the undersigned directs that a Duplicate Customs Purposes Copy of the CCP should be issued to the applicant. I also in exercise of the powers conferred in Sub-Clause (d) of Clause 9 of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the original Customs Purposes Copy of the above CCP.

[F. No. 3|14|85-86|MLS|3]
N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
For Chief Controller of Imports & Exports

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

मद्रास, 17 फरवरी, 1986

विषय :—सर्वश्री हनिफा टैक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, संख्या 14 सर त्यागराय रोड, टी० नगर, मद्रास-600017 को जारी किये गये रुपये 7,06,063/- के अग्रिम लाइसेंस संख्या पी/एल/0435187 दिनांक 21-6-85 का रद्दीकरण ।

का०आ० 1554.—सर्वश्री हनिफा टैक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, 14 सर त्यागराय रोड, टी० नगर, मद्रास-17 को रुपये 7,06,063/- तक पालीस्टर फिलमेंट यार्न का आयात करने के लिये अग्रिम लाइसेंस संख्या पी/एल/0435187 दिनांक 21-6-85 जारी किया गया था ।

लाइसेंसधारी ने उपर्युक्त अग्रिम लाइसेंस की मुद्रा विनियम प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिये इसलिये आवेदन किया है कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी या बैंक से पंजीकृत किये बिना या तो उपयोग में लाये बिना अस्थानस्थ हो गयी है ।

मूल लाइसेंस का पूरा मूल्य रुपये 7,06,063/- के लिये अब मुद्रा विनियम प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिये आवेदन किया गया है ।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने शपथ कमिश्नर द्वारा साक्ष्यांकित एक शपथ-पत्र दाखिल किया है ।

अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि अग्रिम लाइसेंस संख्या पी/एल/0435187/सी/एक्स एक्स/95/ए/85 दिनांक 21-6-85 की मुद्रा विनियम नियंत्रण की मूल प्रति अस्थानस्थ हो गयी है । आवेदक के आवेदन पर विचार करते हुए, रुपये 7,06,063/- के अग्रिम लाइसेंस संख्या पी/एल/0435187 दिनांक 21-6-85 की मुद्रा विनियम नियंत्रण की मूल प्रति एसद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

लाइसेंस का विवरण

(1) लाइसेंस संख्या तथा दिनांक : पी/एल/0435187/सी/एक्स एक्स/95/एम/85 दिनांक 21-6-85
(2) लाइसेंसिंग अधिकारी : संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात मद्रास ।
(3) माल का विवरण : पालीस्टर फिलमेंट यार्न
(4) लाइसेंस की अवधि : ए एम 86
(5) मुद्रा क्षेत्र : जी०सी०ए०
(6) उपयोग में लाये गये माल का मूल्य : कुछ नहीं ।
(7) उपयोग न किये गये माल का मूल्य : रुपये 7,06,063/-

यदि रुपये 7,06,063/- के अग्रिम लाइसेंस संख्या पी/एल/0435187 दिनांक 21-6-85 की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की मूल प्रति का पता लग जाये तो उसको उपयोग किये बिना इस कार्यालय को भेज देना चाहिये । मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति संख्या डी/2464765 अलग जारी किया जाता है ।

[आदेश सं० ए डी बी एस आई सी/163/ए एम-84/ए एल ई ओ]
के० के० धार० कुमार, उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात,
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात ।

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)
Madras, the 17th February, 1986

Subject :—Order for cancellation of Advance Licence No. P/L/0435187 dated 21-6-85 for Rs. 7,06,063/- issued in favour of M/s. Haniffa Textiles Pvt. Ltd., No. 14, Sir Thyagaraya Road, T. Nagar, Madras-600017.

S.O. 1554 :—M/s. Haniffa Textiles Pvt. Ltd., 14, Sir Thyagaraya Road, T. Nagar, Madras-17 were granted an Advance Licence No. P/L/0435187 dated 21-6-85 for Rs. 7,06,063/- for import of Polyester Filament Yarn.

They have applied for a duplicate copy of Exchange Control copy of the above advance licence stating that the original have been misplaced without having been registered with any Custom authority or Banks and utilised at all. The total amount for which the duplicate Exchange Control copy is required to cover the entire amount of Rs. 7,06,063/-.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit on stamp paper duly attested by Commissioner of Oath.

I am satisfied that the original Exchange Control copy of the Advance Licence No. P/L/0435187 /C/XX/95/M/85 dated 21-6-85 has been misplaced. Having considered the party's request for issue of duplicate Exchange Control copy of the Licence the original Exchange Control copy of licence No. P/L/0435187 dated 21-6-85 for Rs. 7,06,063/- is hereby cancelled.

PARTICULARS OF LICENCE

1. Licence No. & Date	P/L/0435187/C/XX/95/M/85 dt. 21-6-85
2. Issuing authority	JCCI & E., Madras.
3. Description of goods	Polyester Filament Yarn
4. Period	AM. 86
5. Currency Area	G.C.A.
6. Value utilised	Nil
7. Value un utilised	Rs. 7,06,063/-

The original Exchange Control copy of the Advance Licence No. P/L/0435187 dt. 21-6-85 for Rs. 7,06,063/-, if traced out later, should be surrended to this office unutilised.

Duplicate Exchange Control Copy No. D/2464765 issued separately.

[Order No. Adv. Lic. 163/AM. 84/ALEO]
K.K.R. KUMAR, Dy. Chief Controller of Imports & Exports for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 17/31 मार्च, 1986

का. आ. 1555.—राजनयिक एवं कोंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 2 के खंड (क) की अनुपालना में केन्द्र सरकार इसके द्वारा, टोक्यो स्थित भारतीय राजदूतावास में सहायक श्री उमेश कुमार को 25-11-85 से कोंसली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[टी. 4330/1/85]
आर. दयाकर, उप सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 17/31st March, 1986

S.O. 1555.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri Umesh Kumar, Assistant in the Embassy of India, Tokyo with effect from 25-11-85 to perform the duties of Consular Agent.

[T. 4330/1/85]
R. DAYAKAR, Dy. Secy.

उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1986

का. आ. 1556.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लघु उद्योग संगठन (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लघु उद्योग संगठन (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लघु उद्योग संगठन (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1960 की अनुसूची में —

(1) अधीक्षक के पद के सामने स्तम्भ 9 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"लागू नहीं होता" ।

(2) उच्च श्रेणी लिपिक के पद के सामने स्तंभ 9 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"लागू नहीं होता" ।

[सं. ए-12018/1/85-ए(एन जी)]
बचन पाल सिंह, उप-निदेशक (प्रशा.)

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना का. नि. आ. 982 तारीख 12-4-60 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात् का. आ. 2929 तारीख 4-12-61, का. नि. आ. 2144 तारीख 26-2-1963, का. नि. आ. 3656 तारीख 18-11-1966, सा. का. नि. 2476 तारीख 17-9-1974 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Office of the Development Commissioner)

(Small Scale Industries)

New Delhi, the 24th February, 1986

S.O. 1556.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Small Scale Industries Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Small Scale Industries Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Small Scale Industries Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1960,—

(i) against the post of Superintendent in column 9, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—
"Not applicable".

(ii) against the post of Upper Division Clerk in column 9, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—
"Not applicable".

[No. A-12018/1/85-A(NG)]
B. P. SINGH, Dy. Director (Admn.)

NOTE : Principal rules published vide notification S.R.O. 982 dated 12-4-60 subsequently amended vide S.O. 2929 dated 4-12-1961, S.R.O. 2144 dated 26-7-1963, S.R.O. 3656 dated 18-11-1966, G.S.R. 2476 dated 17-9-1974.

(सरकारी उद्यम विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1986

आदेश

का.आ. 1557.—विकास परिषद (कार्यविधिक) नियम, 1952 के नियम, 2,4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल और गैस अन्वेषण तथा उत्पादन उद्योग के लिए उपकरणों हेतु विकास परिषद् की संरचना में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

क्रम संख्या-1. विकास परिषद के अध्यक्ष "सचिव, भारी उद्योग विभाग" के स्थान पर "सचिव, औद्योगिक विकास विभाग" होंगे।

क्रम संख्या-2. सदस्य का पदनाम "महानिदेशक, तकनीकी विकास महानिदेशालय" के बजाय "सचिव और महानिदेशक (तकनीकी विकास)" होगा।

क्रम संख्या-7. सलाहकार (तकनीकी) और पदेन संयुक्त सचिव "भारी उद्योग विभाग" के बजाय "औद्योगिक विकास विभाग" का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे।

बाकी संरचना, विचारार्थ विषय और शर्तें आदि अपरिवर्तित रहेंगी।

[फा.सं. 1(9)-2/84-टी.एस.डब्ल्यू.]
एस.सी. ढींगरा, सलाहकार (तकनीकी) एवं पदेन संयुक्त सचिव

(Department of Public Enterprises)

New Delhi, the 31st March, 1986

ORDER

S.O. 1557.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules 1952, the Central Government hereby amends the composition of the Development Council for Equipment for Oil and Gas Exploration and Production Industry to the following effect :—

S. No. 1 : Chairman of the Development Council shall be "Secretary, Industrial Development" in place of "Secretary, Department of Heavy Industry".

S. No. 2 : The designation of the Member shall be "Secretary and Director General (Technical Development)" instead of "Director General, Directorate General of Technical Development".

S. No. 7 : Adviser (Technical) & Ex-officio Joint Secretary shall be the Member representing the "Department of Industrial Development" instead of "Department of Heavy Industry".

The rest of the composition, terms of reference and term etc., shall remain the same.

[F. No. 1(9)-2/84-TSW]
S. C. DHINGRA, Adviser (Technical) &
Ex-Officio Joint Secretary

खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1986

का०आ० 1558.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन मुहर) नियम और विनियम 1955 के नियम 3 के उपनियम (2) और विनियम 3 के उपविनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि भारतीय मानक विशिष्टि संख्या IS : 10908—1984 तरल पेट्रोलियम गैस के लिये रबड़ की नम्य नलिकाओं की विशिष्ट 1984-08-31 से निर्धारित की गई है।

[संख्या सीएमडी/13 : 2]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 21st March, 1986

S.O. 1558:—In pursuance of sub-rule (2) of Rule 3 and sub-regulations (2) and (3) of Regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby notifies that the Indian Standard Specification number IS : 10908—1984 Specification for flexible rubber tubing for liquefied petroleum gas has been established with effect from 1984-08-31.

[No. CMD/13:2]

का०आ० 1559.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के नियम 4 के उपनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जो मानक चिह्न उनके डिजाइन, शाब्दिक विवरण तथा तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिये गये है वे निर्धारित कर दिये गये हैं। ये भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 और इसके अधीन बने नियमों तथा विनियमों के निमित्त प्रत्येक के आगे दी गई तारीखों से लागू होंगे।

अनुसूची

क्रम सं	मानक चिह्न डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मानक चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		सोडियम बाइक्रोमेट, तकनीकी	IS : 249—1979 सोडियम बाइक्रोमेट तकनीकी की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें "ISI" अक्षर होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई निश्चित शैली और परस्पर संबद्ध अनुपात में बनाया गया, डिजाइन में निर्देशन के अनुसार मोनोग्राम के ऊपर भारतीय मानक संख्या अंकित है।	1985-01-16
2.		सरसों का तेल	IS : 546—1975 सरसों के तेल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	"	1985-07-11
3.		बोरैक्स, तकनीकी	IS : 1109—1980 बोरैक्स की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	"	1984-10-16
4.		निर्जर्मक उपकरण (टेबल मॉडल)	IS : 5022—1979 निर्जर्मक उपस्कर (टेबल मॉडल) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें "ISI" अक्षर होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई निश्चित शैली और परस्पर सम्बद्ध अनुपात में बनाया गया, डिजाइन में निदेशन के अनुसार मोनोग्राम के ऊपर भारतीय मानक संख्या अंकित है।	1985-03-01
5.		पलंग चौखटे, अस्पताली सामान्य प्रयोजी	IS : 5029—1979 पलंग चौखटे सामान्य प्रयोजी की विशिष्टि	"	1985-05-01
6.		कृत्रिम दांतों के लिए आधारभूत पोलीमर सामग्री	IS : 6887—1973 कृत्रिम दांतों के लिए पोलीमर सामग्री	"	1985-02-01

[सं० सीएमडी/13 : 9]

S.O. 1559.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark(s), design (s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the date shown against each :—

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the design of the Standard Mark	Date of effect
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(6)
1.		Sodium bichromate, technical.	IS : 249—1979 Specification for sodium bichromate technical (Third Revision).	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1985-01-16
2.		Mustard Oil	IS : 546—1975 Specification for mustard oil. (Second Revision).	The monogram of the Indian Stanards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1985-07-16
3.		Borax, technical.	IS : 1109—1980 Specification for borax (Second Revision).	-do-	1984-10-16
4.		Sterilizer, instruments (table model)	IS : 5022—1979 Specification for sterilizer, instruments (table model) (Second Revision)	-do-	1985-03-01
5.		Bedsteads hospital, general purposes.	IS : 5029—1979 Specification for bedsteads hospital, general purposes.	-do-	1985-05-01
6.		Denture base polymer	IS : 6887—1973 Specification for denture base polymer.	-do-	1985-02-01

[No. CMD/13 : 9]

का.आ. 1560.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई मुहर लगने की फीस अनुसूची में दिये गये ब्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई है। यह फीस प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से लागू होंगी।

अनुसूची

क्रम सं.	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्ष	प्रति इकाई	मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सोडियम बाइक्रोमेट तकनीकी	IS : 249—1979 सोडियम बाइक्रोमेट तकनीकी की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	एक टन	1. पहली 500 इकाइयों के लिए रु. 10.00 प्रति इकाई, और 2. 501वीं और उससे अधिक इकाइयों के लिए रु. 7.50 प्रति इकाई	1985-01-16
2.	सरसों का तेल	IS : 546—1975 सरसों के तेल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक टन	1. पहली 1000 इकाइयों के लिए रु. 20.00 प्रति इकाई, 2. 1001वीं से 2000 तक इकाइयों के लिए रु. 10.00 प्रति इकाई, और 3. 2001वीं और इससे अधिक इकाइयों के लिए रु. 5.00 प्रति इकाई	1985-07-16
3.	बोरैक्स तकनीकी	IS : 1109—1980 बोरैक्स की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक टन	रु. 20.00	1984-10-16
4.	निर्जर्मक उपस्कर (टेबल मॉडल)	IS : 5022—1979 निर्जर्मक उपस्करों (टेबल मॉडल) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक निर्जर्मक	50 पैसे	1985-03-01
5.	पलंग चौखट अस्पताली सामान्य प्रयोजी	IS : 5029—1979 पलंग चौखट अस्पताली, सामान्य प्रयोजी की विशिष्टि	एक मद	1. पहली 500 इकाइयों के लिए रु. 10.00 प्रति इकाई, और 2. 501वीं और उससे अधिक इकाइयों के लिए रु. 5.00 प्रति इकाई	1985-05-01
6.	कृत्रिम दांतों के लिए आधारभूत पोलीमर सामग्री	IS : 6887—1973 कृत्रिम दांतों के लिए आधारभूत पोलीमर सामग्री की विशिष्टि	एक किग्रा.	1. पहली 1000 इकाइयों के लिए 50 पैसे प्रति इकाई, और 2. 1001वीं और उससे अधिक इकाइयों के लिए 25 पैसे प्रति इकाई।	1985-02-01

[सं. सीएमडी/13 : 10]

बी. एन. सिंह, अपर महानिदेशक

S.O. 1560:—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each:

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of product	No. and Title of Relevant Indian Standard.	Unit	Marking fee per unit	Date of effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sodium bichromate, technical	IS : 249—1979 Specification for sodium bichromate, technical (Third Revision).	One Tonne	(i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units and (ii) Rs. 7.50 per unit for the 501st unit and above.	1985-01-16
2.	Mustard Oil	IS : 546—1975 Specification for Mustard Oil. (Second Revision).	One Tonne	(i) Rs. 20.00 per unit for the first 1000 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the next 1001st to 2000 units and (iii) Rs. 5.00 per unit for the 2001st unit and above.	1985-07-16
3.	Borax, technical	IS : 1109—1980 Specification for borax (Second Revision).	One Tonne	Rs. 20.00	1984-10-16
4.	Sterilizer, instruments (table model.).	IS : 5022—1979 Specification for sterilizer instruments (table model) (Second Revision).	One Sterilizer	50 Paise.	1985-03-01
5.	Bedsteads hospital, general purposes.	IS : 5029—1979 Specification for bedsteads hospital, general purposes.	One Piece	(i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units and (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st unit and above.	1985-05-01
6.	Denture base polymer	IS : 6887—1973 Specification for denture base polymer	One Kg.	(i) 50 Paise per unit for the first 1000 units and (ii) 25 paise per unit for the 10001st unit and above.	1985-02-01

[No. CMD/13 : 10]
B.N. SINGH, Addl. Director General

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1986

का. आ. 1561.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948 के पैरा 7 और 9 के साथ पठित, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 2723 तारीख 8 अगस्त, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 23 के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"श्री आई. बी. पाण्डेय, अध्यक्ष
भारतीय कोयला खान अधिकारी संगम
डाकघर सिंगरौली, जिला सिधि (मध्य प्रदेश)

[सं. 7(3)/80-प्रशा.-1(पी.एफ.) जिल्द 2]
रमेश कुमार, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 31st March, 1986

S.O. 1561.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), read with paragraphs 7 and 9 of the Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 2723, dated 8th August, 1984, namely :—

In the said notification, against serial number 23, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri I. B. Pandey, President,
Coal Mines Officers Association of India,
P.O. Singrauli, District Sidhi (Madhya Pradesh)"

[No. 7(3)/80-Adm.I(PF) (Vol. II)]
RAMESH KUMAR, Director

नई दिल्ली, 11 अप्रैल 1986

का.आ. 1562—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 194 (अ) तारीख 16 मार्च, 1985 द्वारा जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 16 मार्च, 1985 में प्रकाशित किया गया था, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में भूमि और अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी, और पूर्वोक्त परिक्षेत्र में भूमि और अधिकारों के अर्जन के प्रति कोई आक्षेप नहीं किया गया था,

और केन्द्रीय सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 1701.363 हैक्टर (लगभग) या 4204.25 एकड़ (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 1701.363 हैक्टर (लगभग) या 4204.25 एकड़ (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाता है;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी-1(ई)/III/डोआर/304-1035 तारीख 25 अक्तूबर, 1985 का निरीक्षण कलक्टर, बिलासपुर, (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग), कोयला एस्टेट, सिविल लाइंस, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

कुसमुंडा-III ब्लाक

कोरबा कोलफील्डस

जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश)

क्रम सं.	ग्राम	पटवारी सर्किल सं.	खेवट सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टरों में	टिप्पणियां
1.	दिपका	49	3	कटघोरा	बिलासपुर	7.453	भाग
2.	डाबर	49	4	,,	,,	64.372	,,
3.	मालगांव	49	37	,,	,,	157.148	,,
4.	झिगतपुर	49	39	,,	,,	126.935	,,
5.	बेलटिकरी	49	5	,,	,,	194.391	,,
6.	सिरकी	46	30	,,	,,	375.678	,,
7.	रेणकी	55	55	,,	,,	26.971	,,
8.	सुवाभंडा	55	38	—	,,	164.040	,,
9.	चैनपुर	55	40	,,	,,	535.526	,,
10.	रतीजा	56	61	,,	,,	48.844	,,
					कुल क्षेत्र	1701.363 हैक्टर (लगभग) या 4204.25 एकड़ (लगभग)	

दिपका ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट सं.

627 (भाग), 628 (भाग), 629 (भाग), 630 (भाग), 634 (भाग), 635 से 638, 639 (भाग), 640, 641 (भाग), 642 (भाग), 644 से 652 और 653 (भाग)।

डाबर ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट सं.

39–40 (भाग), 41 (भाग), 42, 43, 44/1, (भाग), 44/2, 44/3, 45 से 94, 95 (भाग), 96 (भाग), 97, (भाग), 127 (भाग), 129 (भाग), 130 (भाग), 131 से 135, 136 (भाग), 137 (भाग), 138 से 164, 165 (भाग), 166 भाग 167 (भाग), 168 (भाग), 176 (भाग), 178 (भाग), 179 (भाग), 180 (भाग), 274, (भाग), 275 (भाग) और 281 (भाग)।

मालगांव ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट सं.

1 से 129, 130, (भाग), 131, 132, 133 (भाग), 134 (भाग), 135 (भाग), 137 (भाग), 138 से 160, से 161 (भाग), 162, 163 (भाग), 164/1 (भाग), 164/2 (भाग), 204 (भाग), 205 (भाग), 206 (भाग), 207 (भाग), 210 (भाग) 211, (भाग), 212 से 247, 248 (भाग), 249 (भाग), 250 (भाग), 252 (भाग), 253, 254, (भाग), 256 (भाग), 257 (भाग), 258 (भाग), 259 (भाग), 266 (भाग), 267 (भाग, 268 से 532, 533 (भाग), 534, 535, 536 (भाग), 537 (भाग), 538 (भाग), 544 (भाग), 545 (भाग), 546 (भाग), 547 (भाग) और 559 (भाग)।

झिगतपुर ग्राम में अंजित किए गए प्लाट सं

1 से 137, 138 (भाग), 139 से 211

बेलटिकरी ग्राम में अंजित किए गए प्लाट सं.

1 से 323, 324, (भाग), 325 से 334, 335 (भाग), 339 (भाग), 353 (भाग), 356 (भाग), 357 (भाग), 358, 359 (भाग), 360 (भाग), 362 (भाग), 363, 364 (भाग), 365 से 372 (भाग), 373 (भाग), 374, 375 (भाग), 378 (भाग), 379 से 405, 406 (भाग), 407 से 485, 486 (भाग), 487 से 523, 524 (भाग), 525 (भाग), 526 (भाग), 527 (भाग), 529 से 531, 532 (भाग), 533 से 559, 560 (भाग), 561 मे 567, 568 (भाग), 570 (भाग), 571 (भाग), 615 (भाग), 616 (भाग), 617 मे 630, 631 (भाग), 632 (भाग), 633 (भाग), 634 (भाग), 635 (भाग), 642 (भाग) और 676 (भाग)।

सिरकी ग्राम में अंजित कए गए प्लाट सं.

67 (भाग), 69, 70, 71 (भाग), 73 (भाग), 74 से 78, 79 (भाग), 80 से 148, 149 (भाग)), 154 (भाग), 155 (भाग), 156 से 443 (भाग)।

रेणकी ग्राम में अंजित किए गए प्लाट सं.

1 (भाग), 2/1 (भाग), 5 (भाग), 56 (भाग), 57 (भाग), 59 (भाग), 60 (भाग), 674 (भाग), 675 (भाग), और 679 (भाग)।

सुवामंडी ग्राम में अंजित किए गए प्लाट सं.

1 से 287, 288 (भाग), 289 से 307, 308 (भाग), 309 (भाग), 311 (भाग), 314 (भाग), 315, 316 (भाग), 317 (भाग) 318 से 344, 345 (भाग), 346 (भाग), 348 (भाग), 350 (भाग), 354 (भाग), 355 (भाग), 356 (भाग), 357 (भाग), और 359 (भाग)।

चैनपुर ग्राम में अंजित किए गए प्लाट सं.

1 से 12, 13 (भाग), 14 से 19, 20 (भाग), 21 से 962, 963 (भाग), 964 से 1063

रतीजा ग्राम में अंजित किए गए प्लाट सं.

433 (भाग), 564 (भाग), 566 (भाग), 567 (भाग), 568 (भाग), 570 (भाग, 582 (भाग), 583 (भाग), 584 से 591, 592 (भाग), 593 (भाग), 594/1 (भाग), 594/2, 611 (भाग), 616/1 (भाग), 616/2, 617 से 620, 621 (भाग), 832 (भाग), और 833 (भाग)।

हैं सीमा वर्णन :

क—ख	रेखा, बिन्दु 'क' से प्रारम्भ होती है और विपक्षा ग्राम में प्लाट सं. 627, 628, 630 , 634, 639, 641, 642 से होकर जाती है, फिर झाबर ग्राम में प्लाट सं. 281, 275, 274 में से होकर जाती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है।
ख—ग	रेखा, झाबर और बेलटिकरी ग्राम की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ग' पर मिलती है।
ग—घ	रेखा झाबर ग्राम में प्लाट सं. 180 , 179, 178, 176, 165, 166, 167, 168, 137, 136, 127, 130, 129, 97, 96, 95, 39-40, 41 से 44/1 से होकर जाती है। और झाबर और सिरकी ग्रामों की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
घ—ङ	रेखा सिरकी ग्राम में प्लाट सं. 155, 154, 149, 73, 79, 71, 67 से होकर जाती है, तब रतीजा ग्राम में प्लाट सं. 564, 566, 567, 568, 570 में से होकर जाती है और प्लाट सं. 570 में बिन्दु ङ पर मिलती है।
ङ—च	रेखा रतीजा ग्राम में प्लाट सं. 570, 582, 583, 592, 593, 594/1, 433, 611, 616/1, 621, 332, 833 में से होकर जाती है तब चैनपुर, ग्राम में प्लाट सं. 13, 20, 963 से होकर जाती है और फिर रेणकी के प्लाट सं. 57, 1 में से जाती है और प्लाट सं. 1 में बिन्दु 'च' पर मिलती है।
च—छ	रेखा, रेणकी ग्राम में प्लाट सं. 1, 2/1, 5, 56, 59, 60, 674, 675, 679, 57 में से होकर जाती है और चैनपुर, रेणकी और सुवामंडी ग्रामों के त्रिसंगम बिन्दु 'छ' पर मिलती है ।
छ—ज—झ	रेखा सुवामंडी ग्राम में प्लाट सं. 359, 357, 356, 355, 354, 345, 350, 348, 346, 317, 316, 314, 288, 311, 309, 308, में से होकर जाती है, तब सुवामंडी और बरदी बाजार की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'झ' पर मिलती है ।
झ—ञ	रेखा मालगाँव ग्राम में प्लाट सं. 538, 536, 537, 544, 533 545, 546, 547, 558, 267, 266, 259, 258, 257 256, 254, 252, 250, 248, 249, 210, 211, 207, 206, 204, 205, 161, 164/2, 164/1, 163, 137, 133 135, 134, 130 से होकर जाती है और मालगाँव और ग्राम गाँव ग्रामों की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु "ट" पर मिलती है।
ञ—ट	रेखा, मालगाँव और आमगाँव की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ट' पर मिलती है।
ट—ठ	रेखा, बरेली और मालगाँव ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (1) के अधीन स. का. आ. 3068 तारीख 19 अक्तूबर, 1981 द्वारा अधिसूचित कुसमुंडा-11 ब्लाक की सम्मिलित सीमा भी है और बिन्दु 'ठ' पर मिलती है।
ठ—ड—ढ	रेखा, ग्राम झिगतपुर में प्लाट सं. 138 में से होकर जाती है फिर झिगतपुर और बेलटिकरी ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन का.आ. सं. 3068 तारीख 19 अक्तूबर, 1981 द्वारा अधिसूचित कुसमुंडा-11 ब्लाक की सम्मिलित सीमा है, और बिन्दु 'ढ' पर मिलती है।

ख—क रेखा, प्लाट सं. 557, 558, 559 और प्लाट सं. 560, 571, 570 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बेलटिकरी ग्राम से प्लाट सं. 567 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और फिर प्लाट सं. 568, 532, 527, 526, 525, 524, 486, 615, 616, 631, 632, 633, 642 634, 635, 676, 406, 378, 373, 375, 356, 357, 353, 359, 360, 364, 362, 339, 324, 335 से होकर जाती है और फिर विपका ग्राम में प्लाट सं. 653, 629, 628, 627 से होकर आरम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[सं. 43015/28/86-सी पी]
समय सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 1986

S.O.1562:—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal).

No. S.O. 194(E)—dated the 16th March, 1985 under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and published in Part II, section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary dated the 16th March, 1985, the Central Government gave notice of its intention to acquire land and rights in the locality specified in the schedule appended to that notification;

And whereas no objection was made to the acquisition of lands and rights in the locality aforesaid;

And whereas, the Central Government after consulting the Government of Madhya Pradesh is satisfied that the land measuring 1701.363 hectares (approximately) or 4204.25 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby declares that the lands measuring 1701.363 hectares (approximately) or 4204.25 acres (approximately) described in the said schedule are hereby acquired.

The plan No. C-1(E)/III/DR/304—1085 dated the 25th October, 1985 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Bilaspur (Madhya Pradesh) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur (Maharashtra).

THE SCHEDULE
KUSMUNDA-III BLOCK
KORBA COALFIELDS
DISTRICT BILASPUR (MADHYA PRADESH)

ALL RIGHTS

Serial No.	Village	Patwari Circle Number	Khewat No.	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	2	3	4	5		6	7
1.	Dipka	49	3	Katghora	Bilaspur	7.458	Part
2.	Jhabar	49	4	Katghora	Bilaspur	64.372	Part
3.	Malgaon	49	37	Katghora	Bilaspur	157.148	Part
4.	Jhingatpur	49	39	Katghora	Bilaspur	126.935	Part
5.	Beltikri	49	5	Katghora	Bilaspur	194.391	Part
6.	Sirki	46	30	Katghora	Bilaspur	375.678	Part
7.	Renki	55	55	Katghora	Bilaspur	26.971	Part
8.	Suwabhandi	55	38	Katghora	Bilaspur	164.040	Part
9.	Chainpur	55	40	Katghora	Bilaspur	535.526	Part
10.	Ratija	56	61	Katghora	Bilaspur	48.844	Part

Total Area :		1701.563 hectares (approximately)
	Or	
		4204.25 acres (approximately)

Plot numbers acquired in village Dipka :

627 (Part), 628 (Part), 629 (Part), 630 (Part), 634 (Part), 635 to 638, 639 (Part), 640, 641 (Part), 642 (Part), 446 to 652 and 653 (Part).

Plot numbers acquired in village Jhabar :

39—40 (Part), 41 (Part), 42, 43, 44/1 (Part), 44/2, 44/3, 45 to 94, 95 (Part), 96 (Part), 97 (Part), 127 (Part), 129 (Part), 130 (Part), 131 to 135, 136 (Part), 137 (Part), 138 to 164, 165 (Part), 166 (Part), 167 (Part), 168 (Part), 176 (Part) 178 (Part), 179 (Part), 180 (Part), 274 (Part), 275 (Part) and 281 (Part).

Plot numbers acquired in village Malgaon :

1 to 129, 130, (Part), 131, 132, 133 (Part), 134 (Part), 135 (Part), 137 (Part), 138 to 160, 161 (Part), 162, 163 (Part), 164/1 (Part), 164/2 (Part), 204 (Part), 205 (Part), 206 (Part), 207 (Part), 210 (Part), 211 (Part), 212 to 247, 248 (Part), 249 (Part), 250 (Part), 252 (Part), 253, 254 (Part), 256 (Part), 257 (Part), 258 (Part), 259 (Part), 266 (Part), 267 (Part), 268 to 532, 533 (Part), 534, 535, 536 (Part), 537 (Part), 538 (Part) 544 (Part), 545 (Part), 546, (Part), 547 (Part) and 558 (Part).

Plot numbers acquired in village Jhingatpur :

1 to 137, 138 (Part), 139 to 211.

Plot numbers acquired in village Beltikri :

1 to 323, 324 (Part), 325 to 334, 335 (Part), 339 (Part), 353 (Part), 356 (Part), 357 (Part), 358, 359 (Part), 360 (Part), 362 (Part), 363, 364 (Part), 365 to 372, 373 (Part), 374, 375 (Part), 378 (Part), 379 to 405, 406 (Part), 407 to 485, 486 (Part), 487 to 523, 524 (Part), 525 (Part), 526 (Part), 527 (Part), 528 to 531, 532 (Part), 533 to 559, 560 (Part), 561 to 567 , 568 (Part), 570 (Part), 571 (Part), 615 (Part), 616 (Part), 617 to 630, 631 (Part), 632 (Part), 633 (Part), 634 (Part), 635 (Part), 642 (Part), and 676 (Part).

Plot numbers acquired in village Sirki :

67 (Part), 69, 70, 71 (Part), 73 (Part), 74 to 78, 79 (Part), 80 to 148 (149 (Part), 154 (Part), 155 (Part), 156 to 443.

Plot numbers acquired in village Renki :

1 (Part), 2/1, (Part) 5 (Part), 56 (Part), 57 (Part), 59 (Part), 60 (Part), 674 (Part), 675 (Part) and 679 (Part).

Plot numbers acquired in village Suwabhandi :

1 to 287, 288 (Part), 289 to 307, 308 (Part), 309 (Part), 311 (Part), 314 (Part), 315, 316 (Part), 317 (Part), 318 to 344, 345 (Part) 346 (Part), 348 (Part), 350 (Part), 354 (Part), 355 (Part), 356 (Part), 357 (Part), and 359 (Part).

Plot numbers acquired in village Chainpur :

1 to 12, 13 (Part), 14 to 19, 20 (Part), 21 to 962, 963 (Part), 964 to 1065.

Plot numbers acquired in village Ratija :

433 (Part), 564 (Part), 566 (Part), 567 (Part), 570 (Part), 582 (Part), 583 (Part), 584 to 591 592 (Part), 593 (Part), 594/1 (Part), 594/2, 611 (Part), 616/1 (Part), 616/2, 617 to 620, 621 (Part) 832 (Part) and 833 (Part).

Boundary description :

A—B Line starts from point 'A' and passes through village Dipka in plot numbers 627, 628, 630, 634, 639, 641, 642, then proceeds through village Jhabar in plot numbers 281, 275, 274 and meets at point 'B'.

B—C Line passes along the common boundary of villages Jhabar and Beltikri and meets at point 'C'.

C—D Line passes through village Jhabar in plot numbers 180, 179, 178, 176, 165, 166, 167, 168, 137, 136, 127, 130, 129, 97, 96, 95, 39—40, 41 and 44/1 and meets in the common boundary of villages Jhabar and Sirki at point 'D'.

D—E Line passes through village Sirki in plot numbers 155, 154, 149, 73, 79, 71, 67, then proceeds through village Ratija in plot numbers 564, 566, 567, 568, 570 and meets in plot number 570 at point 'E'.

E—F Line passes through village Ratija in plot numbers 570, 582, 583, 592, 593, 594/1 433, 611 616/1, 621, 832, 833 then proceeds through village Chainpur in plot numbers 13, 20, 963, then in plot numbers 57, 1 of village Renki and meets in plot number 1 at point 'F'.

F—G Line passes through village Renki in plot numbers 1, 2/1, 5, 56, 59, 60, 674, 675, 679, 57, and meets in the trijunction point of villages Chainpur, Renki and Suwabhandi at point 'G'.

G-H-I Line passes through village Suwabhandi in plot numbers 359, 357, 356, 355, 354, 345, 350, 348, 346, 317, 316, 314, 288, 311, 309, 308 then passes along the common boundary of villages Suwabhandi and Bardibazar and meets at point 'I'.

I—J Line passes through village Malgaon in plot numbers 538, 536, 537, 544, 533, 545, 546, 547, 558, 267, 266, 259, 258, 257, 256, 254, 252, 250, 248, 249, 210, 211, 207, 206, 204, 205, 161, 164/2, 164/1, 163, 137, 133, 135, 134, 130 and meets on the common boundary of villages Malgaon and Amgaon at point 'J'.

J—K Line passes along the common boundary of villages Malgaon and Amgaon and meets at point 'K'.

K—L Line passes along the common boundary of villages Bareli and Malgaon, which is also the common boundary of Kusmunda-II Block notified under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 vide notification No. S.O. 3068 dated the 19th October, 1981 and meets at point 'L'.

L-M-N Line passes through village Jhingatpur in plot number 138, then proceeds along the common boundary of villages Jhingatpur and Beltikri, which is also the common boundary of Kusmunda-II Block notified under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 vide S.O. No. 3068 dated 19-10-1981 and meets at point 'N'.

N—A Line passes through village Beltikri along the eastern boundary of plot numbers 557, 558, 559 and in plot numbers 560, 571, 570, along the eastern boundary of plot number 567, then in plot numbers 568, 532, 527, 526, 525, 524, 486, 615 616, 631, 632, 633, 642, 634, 635, 676, 406, 378, 373, 375, 356, 357, 353, 359, 360, 364, 362, 339, 324, 335 and then proceeds through village Dipka in plot numbers 563, 629, 628, 627 and meets at the starting point 'A'.

[No. 43015/28/85—CA]
SAMAY SINGH, Under Secy.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1986

का. आ. 1563.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइपलाईन प्रोजेक्ट

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा	लिया गया रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	औरैय्या	औरैय्या	बसंतपुर	158	0 02	

[सं० O-14016/79/84-जी० पी०]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 9th April, 1986

S.O. 1563.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

SCHEDULE

Distt.	Pargana	Tehsil	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawah	Auriya	Auriya	Basantpur	158	0-02

[No. O-14016/79/84-GP]

का. आ. 1564.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	हरबंश-पुर	392	001	

[सं० O-14016/394/84-जी०पी०]

S.O. 1564.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Harbansh-pur	392	0-01

[No. O-14016/394/84-GP]

का. आ. 1565.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
इटावा	बिधुना	बिधुना	बहादुर-पुर महार	74	025	

[सं० O-14016/399/84-जी० पी०]

S.O. 1565.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal pracitioner.

Supplimentary ase (Schedule)
H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acers
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Bahadar pur Sahar	74	0-25

[No. O-14016/399/84-GP]

का. आ. 1566.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक वाद अनुसूची
एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	धरमगद पुर	1180	0 07	
				435	0 31	

[सं० O-14016/1/85-जी०पी०]

S.O. 1566.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Dharma-gad pur)	1180	0-07
				435	0-31

[No. O-14016/1/85-GP]

का. आ. 1567.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक वाद अनुसूची
एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	लखुनों	1575	0 52	
				1197	0 02	

[सं० O-14016/2/85-जी० पी०]

S.O. 1567.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Luckhno	1575	0-52
				1197	0-02

[No. O-14016/2/85-GP]

का. आ. 1568.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम, 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	कैथावा	1055	0— 22	
				1131	0— 02	
				1110	0— 04	
				1159	0— 02	
				291	0— 30	
				295	0— 14	
				1135	0— 09	
				1127	0— 04	
				984	0— 04	
				164	0— 05	
				276	0— 02	

[सं० O-14016/3/85-जी०पी०]

S.O. 1568.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Kaithawa	1055	0-22
				1131	0-02
				1110	0-04
				1159	0-02
				291	0-30
				295	0-14
				1135	0-09
				1127	0-04
				984	0-04
				164	0-05
				276	0-02

[No. O-14016/3/85-GP]

का. आ. 1569.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच०बी०जे० गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	असैनी	956	0	50

[सं० O-14016/7/85-जी०पी०]

S.O. 1569.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case Schedule

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawha	Bidhuna	Bidhuna	Asainey	956	0-50

[No. O-14016/7/85-GP]

का. आ. 1570.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम, 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच०बी०जे० गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बदायूं	बिसौली	बिसौली	साहनपुर	37	0-1-05	
				128	0-1-0	

[सं० जी-14016/214/85-जी०पी०]

S.O. 1570.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Badaun	Besouli	Besouli	Sahanpur	37	0-1-05
				128	0-1-0

[No. O-14016/214/85-GP]

का. आ. 1571.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम, 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच०बी०जे० गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बदायूं	बिसौली	सतासी	सिरौरी	108	0-0-10	
				114	0-18-0	
				393	0-0-10	
				394	0-0-10	

[सं० ओ-14016/219/85-जी०पी०]

S.O. 1571.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd.; H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
Badaun	Besouli	Satasi	Serouri	108	0-0-10	
				114	0-18-0	
				393	0-0-10	
				394	0-0-10	

[No. O-14016/219/85GP]

का. आ. 1572 :—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप-लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि., द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यत:, प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच बी.जे. गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बदायूं	बिसोली	बिसौली	खजुरिया	1	2-0-0	

[सं ओ-14016/224/85-जी पी]

S.O. 1572.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd.; H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acers
1	2	3	4	5	6
Badown	Besouly	Besouly	Khajuriya	1	2-0-0

[No. O-14016/224/85-GP]

का. आ. 1573 :—यत; केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप-लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि., द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यत:, प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बदायूं	बिसौली	सेतासी	अगेई	58	0-7-0	
				191	0-0-5	
				306	0-4-0	
				420	0-5-0	
				414	0-0-5	
				412	0-1-0	
				434	0-1-10	
				461	0-5-0	

[सं ओ-14016/228/85-जी पी]

S.O. 1573.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd.; H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Badaun	Besoaly	Satasi	Agai	58	0-7-0
				191	0-0-5
				306	0-4-0
				420	0-5-0
				414	0-0-5
				412	0-1-0
				435	0-1-10
				461	0-5-04

[No. O-14016/228/85-GP]

का. आ. 1574 :—यत; केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप-लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि., द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यत:, प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	गढ़गांव	562	1-0-0

[सं. 14016/229/85-जी. पी.]

S.O. 1574.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd.; H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Badaun	Besouly	Besouly	Gorhganak	562	1-0-0

[No. O-14016/229/85-GP]

का. आ. 1575 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप-लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि., द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम नगर	करनपुर	769	0-3-16
				772	0-11-10
				765	0-8-0

[सं. 0 14016/262/85-जी. पी.]

S.O. 1575.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd.; H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Badaun	Besouly	Islam Nagar	Karanpur	769	0-3-16
				772	0-11-10
				765	0-8-0

[No. O-14016/262/85-GP]

का. आ. 1576 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप-लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि., द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद् पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम नगर	दजराम पुर	67	1-0-0

[सं. 14016/264/85-जी. पी.]

S.O. 1576.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd.; H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisouli	Islam Nagar	Dajram-pur	67	1-0-0

[No. O-14016/264/85-GP]

का. आ. 1577 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप-लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि., द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
बदायु	बिसौली	इस्लाम नगर	मोहसन पुर	303	0-7-15

[सं. 14016/269/85-जी. पी.]

S.O. 1577.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd.; H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

District	Tahsil	Pargna	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisouli	Islam Nagar	Mohsan pur	303	0-7-15

[No.O—14016/269/65-GP]

का. आ. 1578 :—यत; केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम, 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 (यू. पी.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

हाजिरा, बरेली, से जगदीशपुर तक पाइपलाइन प्रोजेक्ट

अनुसूची

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
इटावा	औरैय्या	औरैय्या	सीहापुर	121	0—0—1

[सं. O 14017/337/84-जी. पी.]

S.O. 1578.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal pdactitioner.

Hajira-Bareilly to Jagdishpur Pipeline Project

SCHEDULE

District	Pargana	Tahsil	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawa	Auriya	Auriya	Sheehapur	121	0-0-1

[No. O-14016/337/84-GP]

का. आ. 1579.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 (यू. पी.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइपलाईन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिलग्राम	कटियारी	गोमिया मीगाला	399	0—1—07

[सं. O 14016/365/85-जी. पी.]

S.O. 1579.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd. ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this Notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	
1	2	3	4	5	6	7
Hardoi	Bilgram	Katiyari	G[illegible]miya Sisala	399	0-1-07	

[No. O-14016/365/85-GP]

का.आ. 1580.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुपूरक वाद अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	आंवला	गुलेली	495	0–2–0

[सं. O–14016/370/85–जी पी]

S.O. 1580.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Barriely	Awala	Awala	Gulely	495	0-2-0	

[No. O-14016/370/85-GP]

का.आ. 1581 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा बरेली–जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप-लाइन बिछाने भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी–58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच.बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
बदायू	दातागंज	सलेमपुर	सेरहा पोख्ता	312	0–6–0
				18	1–0–0
				168	0–4–13

[सं. O–14018/372/85–जी पी]

S.O. 1581.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to

the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Badaun	Dataganj	Salempur	Serha-Pokhta	312	0-6-0-
				18	1-0-0
				168	0-4-13

[No. O-14016/372/85-GP]

का.आ. 1582.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी–58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच०बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेफफल
1	2	3	4	5	6
बदायू	बिसौली	बिसौली	नौगवा	238	0–2–0
				165	0–1–10

[सं. O–14016/279/85–जी पी]

S.O. 1582.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Badaun	Besouli	Besouli	Naugauwa	238	0–2–0
				165	0–1–10

[No. O-14016/279/85-GP]

का.आ. 1583.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ–226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः भी यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच०बी०जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	सतहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेफफल
1	2	3	4	5	6
बदायूं	गन्नौर	असदपुर	कल्हा	749	0–2–10
				750	0–0–5

[सं. O–14016/453/85-जी पी]

S.O. 1583.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this Notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Badaun	Gunnour	Asadpur	Kalha	749	0-2-10
				750	0-0-05

[No. O-14016/453/85-GP]

का.आ. 1584 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी–58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
बदायू	गुन्नौर	असदपुर	जयराम	595 ...	0–1–0
			नगर	329	0–0–10

[स. O–14016/464/85–जी पी]

S.O. 1584.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares it intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this Notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
					B. B. B.
Badaun	Gunnoor	Asadpur	Jairam Nagar	595 329	0-1-0 0-0-10

[No. O—14016/464/85—GP]

का०आ० 1585 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
बदायूं	गुन्नौर	गुन्नौर	सहजना	783	0–0–5
			अहिरान	214	0–0–5
				329	0–1–10

[सं० O–14016/485/85-जीपी]

S.O. 1585.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares it intention to acquire the right ofuser therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this Notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Bad-aun	Gun-noor	Gun-noor	Sah-jana	783	0-0-5	
				214	0-0-5	
			Ahiran	329	0-1-10	

[No. O—14016/485/85—GP]

का०आ० 1586.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी-58 बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटासं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बदायूं	गुन्नौर	गुन्नौर	सुनवर सराय	1176	1–16–15	

[सं० O-14016/487/85-जीपी]

S.O. 1586.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Porvided the any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this Notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acers	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Bad-aun	Gun-noor	Gun-noor	Sunver Sariy	1176	1-16-15	

[No. O—14016/487/85–G.P.]

का०आ० 1587.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी गैस आयोग बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईपलाईन बिछाने के लिये ।

राज्य : गुजरात जिला–पंचमहल तालुका–हालोल

गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	आरे	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
धानसर	169	0	03	00
	175	0	30	18
	177	0	42	50
	181	0	01	25

1	2	3	4	5
धानसर—जारी	180	0	18	25
	183	0	16	23
	कोटर	0	16	50
	25/3/पी	0	08	50
	24	0	05	25
	23	0	10	73
	22/2	0	00	60
	21	0	01	10

[सं० O-14016/547/86-जीपी]

S.O. 1587.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Alka Puri;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira—Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Dhansar . . .	169	0	03	00
	175	0	30	18
	177	0	42	50
	181	0	01	25
	180	0	18	25
	183	0	16	23
	Kotar	0	16	50
	25/3/p	0	08	50
	24	0	05	25
	23	0	10	73
	22/2	0	00	60
	21	0	01	10

[No. O—14016/547/86—GP]

का०आ० 1588.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है:

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० 45 सुभाषनगर सांवेर रोड, उज्जैन (म०प्र०) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम—मसूरिया तहसील—आबुआ जिला—आबुआ राज्य (मध्यप्रदेश)

अनुसूची

अनु० क्र०	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	144	0.024
2.	151	0.004
3.	145	0.581
4.	137/1	0.024
5.	136	0.032
6.	135	0.495
7.	146	0.008
8.	148	0.040
9.	150/1	0.024
10.	149/2	0.425
11.	149/1	0.162
12.	140	0.146
13.	138/5	0.041
14.	137/2	0.057
15.	158/5	0.237
16.	138/6	0.008
17.	139/2	0.016
18.	139/1	0.033
19.	155/1	0.048
20.	155/2	0.041
21.	159/1	0.064
22.	159/2	0.121
23.	160	0.122
कुल योग		2.753

[सं० O-14016/548/86-जीपी]

S.O. 1588.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd, H.B.J. Pipeline 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Masuriya Tehsil : Jhabua Dist. : Jahbua (M.P.)

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1.	144	0.024
2.	151	0.004
3.	145	0.581
4.	137/1	0.024
5.	136	0.032
6.	135	0.495
7.	146	0.008
8.	148	0.040
9.	150/1	0.024
10.	149/2	0.425
11.	149/1	0.162
12.	140	0.146
13.	138/3	0.041
14.	137/2	0.057
15.	158/3	0.237
16.	138/6	0.008
17.	139/2	0.016
18.	139/1	0.033
19.	155/1	0.048
20.	155/2	0.041
21.	159/1	0.064
22.	159/2	0.121
23.	160	0.122
	Total Area	2.753

[No. O—14016/548/86—G.P.]

का० आ० 1589:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य मे हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० 45 सुभाषनगर सांवेर रोड़, उज्जैन, (म० प्र०) (456001) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम मेलर कला : तहसील झाबुआ : जिला झाबुआ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु० क्र०	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	34	0.242
2.	32	0.405
3.	31/1	0.200
4.	31/2	0.241
5.	39	0.289
6.	41	0.025
7.	42	0.243
8.	43	0.591
9.	45	0.024
10.	46	0.008
11.	133	0.333
12.	132	0.016
13.	126	0.032
14.	129	0.380
15.	130/368	0.005
16.	128	0.170
17.	121/2मीसें	0.567
18.	121/2 मीसें	0.041
19.	114मीसें	1.021
20.	111	0.048
21.	113	0.234
22.	106	0.129
23.	107/1	0.010
24.	114मीसें	0.251
25.	115	0.004
26.	108/1	0.186
27.	103	0.008
28.	104	0.631
29.	103	0.014
30.	102	0.056
कुल योग		5.504

[सं० O—14016/549/86—जी पी]

S.O. 1589.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares it intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Gas Pipeline 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hbj Gas Pipeline Project

Village : Ghelar Kanla Tehsil : Jhabua Dist. : Jabua (M.P.)

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectares
1.	34	0.242
2.	32	0.405
3.	31/1	0.200
4.	31/2	0.241
5.	39	0.239
6.	41	0.025
7.	42	0.243
8.	43	0.591
9.	45	0.024
10.	46	0.008
11.	133	0.333
12.	132	0.016
13.	135	0.032
14.	129	0.380
15.	130/468	0.003
16.	128	0.170
17.	121/2 M.	0.567
18.	121/2 M.	0.041
19.	114 M.	0.121
20.	111	0.048
21.	113	0.234
22.	106	0.129
23.	107/1	0.010
24.	114 M.	0.251
25.	115	0.004
26.	102/1	0.136
27.	103	0.008
28.	104	0.631
29.	101	0.014
30.	102	0.056
	Total Area	5.504

[No. O-14016/549/86-G.P.]

का०आ० 1590—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब, पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि०, 45 सुभाषनगर सांवेर रोड, उज्जैन, (म० प्र० 456001) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एच. बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : मोद तहसील : झाबुआ जिला : झाबुआ राज्य (मध्य प्रदेश)

क्र० सं०	खसरा नं	उपयोग का अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	76	0.225
2.	77	0.072
3.	87	0.128
4.	91	0.418
5.	92	0.005
6.	94/1	0.845
7.	97	0.008
8.	98	0.024
9.	99	0.056
10.	53	0.016
11.	55	0.267
12.	54/	1.330
13.	69/1	0.756
14.	29/	1.116
15.	31	0.037
16.	43	0.360
17.	44	0.254
18.	45	0.096
19.	33	0.328
	कुल योग	6.341

[सं० O-14016/550/86-जीपी]

S.O. 1590.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Gas Pipeline 45 Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project

Village : Mod. Tehsil : Juabua Dist. : Jhabua (M.P.)

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectares
1.	76	0.225
2.	77	0.072
3.	87	0.128
4.	91	0.418
5.	92	0.005
6.	94/1	0.845
7.	97	0.008
8.	98	0.024
9.	99	0.056
10.	53	0.016
11.	55	0.267
12.	54/1	1.330
13.	69/1	0.756
14.	29/1	1.116
15.	31	0.037
16.	43	0.360
17.	44	0.254
18.	45	0.096
19.	38	0.328
	Total area	6.341

[No. O-14016/550/86-G.P.]

का० आ० 1591 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर .... तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने यह उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226 020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा बी	बि	बि.
1	2	3	4	5		6	7
बदायूं	गुन्नौर	रजपुरा	कैल	17	—	—	2
				16	—	19	12
				15	—	—	1
				14	—	16	7
				13	—	4	9
				12	—	6	16
				11	1	10	11
				9	—	15	18
				10	—	—	3
				42	—	1	1
				61	1	17	2
				71	—	—	14
				73	—	8	5
				72	1	3	13
				88	—	—	3
				60	—	-	18
				53	—	1	11
				56	—	6	10
				59	—	4	14

[सं. O-14016/551/86-जी पी]

S.O. 1591.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the such schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by lagal practitioner.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in B-B-B
1	2	3	4	5	6
Bad-aun	Gun-naur	Raj-pura	Kail	17	— — 2
				16	— 19 12
				15	— — 8
				14	— 16 7
				13	— 4 9
				12	— 6 16
				11	1 10 11
				9	— 15 18
				10	— — 3
				42	— 1 1
				61	1 17 2

1	2	3	4	5	6
				71	— — 14
				73	— 8 5
				72	1 3 13
				88	— — 3
				60	— — 18
				53	— 1 11
				56	— 6 10
				59	— 4 14

[No. O—14016/551/86—G.P.]

का० आ० 1592 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर .....तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी 58/बी, अलीगंज, लखनऊ 226 020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा, बरेली, जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल		
					बी	बिस्वा	बिस्वान्सी
1	2	3	4	5	6		
बदायूं	गुन्नौर	रजपुरा	भकरौली	543	0	6	10
				546	0	0	1
				545	0	1	1
				544	0	2	0
				537	0	8	10
				538	0	6	0
				535	1	5	15
				534	0	3	10
				533	0	2	15
				532	0	0	10
				417	0	0	5
				435	0	0	1
				436	0	3	5
				520	0	1	15
				438	0	7	5
				438	0	6	15
				440	0	13	10
				441	0	17	15
				442	0	3	0
				443	0	1	10
				444	0	2	0
				445	0	3	5
				453	1	2	0
				446	0	1	5
				452	0	15	5
				449	0	9	15
				450	0	4	5
				470	0	0	15
				475	0	3	5
				473	1	3	10
				484	0	0	15
				483	0	0	10
				485	2	6	0
				493	0	5	0
				492	0	9	15
				489	1	18	0
				490	0	1	5
				501	0	8	15
				343	0	6	0
				338	0	2	5
				339	1	8	0
				340	0	6	10
				341	0	2	5
				502	0	0	5
				344	0	4	5

[सं. O-14016/552/86-जी पी]

एम. एस. श्रीनिवासन, निदेशक(एन जी)

S.O. 1592.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And, whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58-B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No	Area in B-B-B
1	2	3	4	5	6
Bad-aun	Gun-naur	Raj-pura	Bhak-rauli	543	0-6-10
				546	0-0-1
				545	0-1-1
				544	0-2-0
				537	0-8-10
				538	0-6-0
				535	1-5-15
				534	0-3-10
				533	0-2-15
				532	0-0-10
				417	0-0-5
				435	0-0-1
				436	0-3-5
				520	0-1-15
				438	0-7-5
				429	0-6-15
				440	0-13-10
				441	0-17-15
				442	0-3-0
				443	0-1-10
				444	0-2-0
				445	0-3-5
				453	1-2-0
				446	0-1-5
				452	0-15-5
				449	0-9-15
				450	0-4-5
				470	0-0-15
				475	0-3-5
				476	1-3-10
				484	0-0-15
				483	0 0-10
				485	2-6-0
				493	0-5-0
				492	0-9-15
				489	1-18-0
				490	0-1-5
				501	0-9-15
				343	0-6-0
				338	0-2-5
				339	1-8-0
				340	0-6-10
				341	0-2-5
				502	0-0-5
				344	0-4-5

[No. O-14016/552/86-G.P.]

M. S. SRINIVASAN, Director (NG)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अप्रैल 1986

का.आ. 1593—आयुर्विज्ञान परिषद नियम 1957 के नियम 2 के खण्ड (घ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा डा० बी. पी. चक्रावर्ती, रजिस्ट्रार, उड़ीसा कांउसिल आफ मैडिकल रजिस्ट्रेशन, भुवनेश्वर को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड ग के अधीन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के एक सदस्य का उड़ीसा राज्य में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. वी. 11013/4/86—एम. ई. (पी)]

चन्द्र भान, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 3rd April, 1986

S.O. 1593.—In pursuance of clause (d) of rule 2 of the Medical Council Rules 1957, the Central Government hereby appoints Dr. B. P. Chakravarty, Registrar, Orissa Council of Medical Registration, Bhubaneshwar, as Returning Officer for the conduct of election of a member to the Medical Council of India under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) in the State of Orissa.

[No. V. 11013/4/86-ME(P)]

CHANDER BHAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1986

आदेश

—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस. ओ. 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिनियम के उपबंध के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई

फिल्मों को, उनके सभी भारतीय भाषाओं के रुपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है:—

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1.	अर्नेस्ट दि फरेस्ट	595	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-400026	भारतसरकार	डाकुमेन्ट्री फिल्म। सामान्य प्रदर्शन के लिए।
2.	महिती चित्र संख्या 404	298.70	सूचना सहायक निदेशक (फिल्म) गुजरात सरकार 77 डा० ऐनीबसेंट रोड, वर्ली, बम्बई-400018	सूचना निदेशक गुजरात सरकार सचिवालय, ब्लाक 7, गांधी नगर-382010	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए।
3.	महिती चित्र संख्या 405	265.70	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
4.	देखो समझो मानो	422.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-400026	भारत सरकार	डाकुमेन्ट्री फिल्म। सामान्य प्रदर्शन के लिए।
5.	काफद् घरकु	437	—तदैव—		—तदैव—
6.	मंजिल हवे न दूर	349.91	सूचना सहायक, निदेशक फिल्म, गुजरात सरकार, रामनार्ड रिसर्च लेबोरेट्री लि., 77 डा० ऐनीबेसेंट, रोड, वर्ली, बम्बई-400018	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, सचिवालय, ब्लाक 7, गांधी नगर-382010	डाकुमेन्ट्री फिल्म। गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए।
7.	गुईनिया वार्म	281.64	बालराम जोगलेकर 7/6 शिवाजी नगर, लैक्सो के सामने, वर्ली, बम्बई-400018		डाकुमेन्ट्री फिल्म। सामान्य प्रदर्शन के लिए।
8.	वार्तासंचिका	360.00	आन्ध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11-5-423/1, जफरबाग लकड़ी का पुल हैदराबाद-500004		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। आंध्र प्रदेश सर्कट में प्रदर्शन के लिए।
9.	वार्तातरंगिनी संख्या 50	268.00	—तदैव—		—तदैव—
10.	मां का प्यार	27.75	यूनिसेफ, रविन्द्र मेंनसन, डी, बछा रोड, बम्बई-20	सुकृति फिल्म्स कवि आर्टस, वर्ली सी फेस, बम्बई-400018	डाकुमन्ट्री" फिल्म। सामान्य प्रदर्शन के लिए।
11.	डू. यू. नो.	27.75	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
12.	गेरी	435.86	सहायक निदेशक, सूचना (फिल्म) गुजरात सरकार रामनार्ड रिसर्च लेबोरेट्री लि., 77 डा० ऐनीबेसट रोड, वर्ली, बम्बई-400018	निदेशक सूचना, गुजरात सरकार, सचिवालय, ब्लाक 7, गांधीनगर-382010	डाकुमेन्ट्री फिल्म। गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए।

1	2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र न्यूज नं. 395	299.00	सूचना और जनसम्पर्क, महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, 68, तारादेव रोड़, बम्बई	फिल्म केन्द्र, बम्बई	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। महाराष्ट्र सर्कट में प्रदर्शन के लिए ।
14.	पोरट्रैट आफ ए पेन्टर	576.99	देब व्रत राय 189/1, रीजेंट ग्रोव, कलकत्ता 700040	देबव्रत राय, प्रोडक्शन्स 189/1, रीजेंट, ग्राव, कलकत्ता-700040	"डाकुमेंन्ट्री" फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए ।
15.	इन्डियन नेवी टुडे	492.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24 पैडर रोड	बम्बई-400026	—तदैव—
16.	महिती चित्र संख्या 406	289.56	सहायक निदेशक सूचना (फिल्म), गुजरात सरकार, रामनार्ड, रिसर्च लेबोरेट्री लि. 77, डा० ऐनीबेसेंट रोड, वर्ली बम्बई-400018	निदेशक, सूचना गुजरात सरकार, सचिवालय, ब्लाक 7 गांधीनगर, 382010	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए ।
17.	बिहार समाचार चित्र संख्या 24	265.48	एम झा, फिल्म सम्पादक बिहार सरकार सूचना और जनसम्पर्क विभाग, पटना	निदेशक, सूचना और जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार, पटना	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। बिहार सर्कट में प्रदर्शन के लिए।
18.	बिहार समाचार चित्र संख्या 25	274.02	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
19.	सरल हैल्थ	94.00	फिल्म प्रभाग, 24, पैडर रोड, बम्बई-400026	भारत सरकार,	"डाकुमेंट्री" फिल्म। सामान्य प्रदर्शन के लिए ।
20.	महिती चित्र संख्या 407	288.70	सहायक निदेशक, सूचना (फिल्म), गुजरात सरकार, रामनार्ड रिसर्च लोबोट्री लि., 77. डा. ऐनीबेसेंट रोड, यर्ली, बम्बई-400018	निदेशक, सूचना गुजरात सरकार, सचिवालय, ब्लाक-7, गांधीनगर-382010	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए ।
21.	गायकवाड़	324.00	दिलीप जगदर, एम-7/16, भानूमति, बंगुर नगर, गोरेगांव (पं०) बम्बई-400090		डाकुमेंन्ट्री फिल्म। सामान्य प्रदर्शन के लिए ।
22.	बिहार समाचार चित्र संख्या 26	257.56	एम. झा फिल्म सम्पादक, सूचना और जनसम्पर्क विभाग, बिहार सरकार, पटना	निदेशक, सूचना और जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार, पटना	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। बिहार सर्कट में प्रदर्शन के लिए ।
23.	बिहार समाचार चित्र संख्या 27	293.58	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
24.	सेवामूर्ति रविशंकर महाराज	599.85	सहायक निदेशक, सूचना (फिल्म) गुजरात सरकार, रामनार्ड रिसर्च लेबोरेट्री लि., 77, डा० ऐनीव सेंट रोड, वर्ली, बम्बई ।	निदेशक सूचना, गुजरात सरकार, सचिवालय ब्लाक-7, गांधीनगर-382010	डाकुमेंन्ट्री फिल्म। गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए ।

1	2	3	4	5	6
25.	पिन कोडआन योर मेल	276.00	के. वैकुण्ठ 12-ए, विमोदविला, बी. जी. खैर रोड, वर्ली, बम्बई-400018		डाकुमेंन्ट्री फिल्म, । सामान्य प्रदर्शन के लिए।
26.	वार्तातरंगिनी संख्या 51	278.04	आन्ध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11-5-423 1, जफरबाग लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004.		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म । आन्ध्र प्रदेश सर्कट में प्रदर्शन के लिए।
27.	वार्तातरंगिनी संख्या 52	277.74	—तदैव—		—तदैव—
28.	सर्प	470.00	सहायक निदेशक सूचना, गुजरात सरकार, रामनार्ड रिसर्च लेबोरेट्री लि., 77, डा. ऐनी-बेसेंट रोड, वर्ली, बम्बई 400018	निदेशक सूचना, गुजरात सरकार सचिवालय ब्लाक-7, गांधीनगर-382010	डाकुमेंन्ट्री फिल्म । गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए।
29.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय	472.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24, पैडर रोड, बम्बई-400026		डाकुमेंन्ट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए
30.	वार्तातरंगिनी संख्या 53	286.58	आन्ध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11-5-423/1, जफरबाग, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म । आन्ध्र प्रदेश सर्कट में प्रदर्शन के लिए ।
31.	बिजी हैण्डस, बेटर होम्स	301.75	पुरुषोत्तम बाओकर, 12, जे० पुरजा साहित्य, सहधास, बान्द्रा (पू.) बम्बई-400051	खादी एंव ग्राम उद्योग आयोग, ग्रामोदय विलापार्ले, बम्बई-400056	डाकुमेंन्ट्री फिल्म सामान्य । प्रदर्शन के लिए।
32.	मिट्टी के फूल	426.72	टी. हुसैन, 9 चिन्च पोकली रोड, बन्द्रा, बम्बई-400050	एल. आर. शैख, 51, हैनेसरोड़, महालक्ष्मी बम्बई-400034	"डाकुमेंन्ट्री" फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिए।
33.	पढ़कर	335.28	सहायक निदेशक सूचना (फिल्म) गुजरात सरकार, रामनार्ड रिसर्च लेबोरेट्री लि., 77, डा. ऐनीबेसेट रोड वर्ली, बम्बई-400018	निदेशक, सूचना गुजरात सरकार सचिवालय ब्लाक-7, गांधीनगर 382010	डाकुमेंन्ट्री फिल्म। गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए ।
34.	उत्तर प्रदेश समाचार संख्या 113	284.38	धीरेन्द्र पाण्डे, मार्फत, मैसर्स बम्बई फिल्म लेबोरेट्री प्राइवेट लि., बम्बई	धीरेन्द्र पाण्डे, न्यूजरील निर्माता, सूचना और जनसंपर्क निदेशालय, उ. प्र. सरकार लखनऊ	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म । उत्तर प्रदेश सर्कट में प्रर्दशन के लिए ।
35.	उत्तर प्रदेश समाचार संख्या 114	289.86	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

1	2	3	4	5	6
36.	क्रान्तिगुरु दयानन्द	599.95	सहायक निदेशक, सूचना (फिल्म) गुजरात सरकार, रामनाईं रिसर्च लेबोरेट्री लि० 77, डा० एनीबेसेंट रोड वर्ली, बम्बई-400018	निदेशक सूचना, गुजरात सरकार, सचिवालय, ब्लाक-7, गांधी नगर-382010	डाकुमेंन्ट्री फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिए।
37.	जीव साथी	88.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24 पैडर रोड़, बम्बई-400026		डाकुमेंन्ट्री फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिए।
38.	दी ऐलिफेंट मोटिफ इन इन्डियन स्कल्पचर्स	458.73	टी.एस.नरसिंहम, मैसर्स कोमल प्रोडक्शन्स, 4/54, फर्स्टमैन रोड़, टाटा-सिल्क-फार्म, बसवानागुड़ी, बंगलौर-560004		डाकुमेंन्ट्री फिल्म। सामान्य प्रदर्शन के लिए।
39.	लैदर पपेट्री आफ कर्नाटक	336.80	—तदैव—		—तदैव—
40.	दि हाथसला, एण्ड चालुक्यमान आर्किटक्चर आफ कर्नाटक	493.78	—तदैव—		—तदैव—
41.	महिती चित्र संख्या 409	268.22	सहायक निदेशक, सूचना (फिल्म), गुजरात सरकार रामनाईं रिसर्च लेबोरेट्री लि., 77, डा. ऐनी-बेसंट रोड़, वर्ली, बम्बई-400018	निदेशक सूचना गुजरात सरकार सचिवालय, ब्लाक 7, गांधीनगर-382010	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए।

[फाइल सं. 315/2/86-एफ (पी)]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 3rd April, 1986

ORDER

S.O. 1594.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the Order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated 2nd December, 1966 the Central Government after considering recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto

in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length of the film in metres.	Name of the Applicant	Name of the Producer	Brief synopsis whether a scientific film or for educational purpose or a film deals with news & current events or documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Against the Current	595	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		'Documentary' General release.
2.	Mahiti Chitra No. 404	298.70	Asstt. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block 7, Gandhinagar-382010.	'News and Current Events' Release in Gujarat circuit.
3.	Mahiti Chitra No. 405	265.90	—do—	—do—	—do—
4.	Dekho Samjho Mano	442.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		'Documentary' General release.
5.	Craft Charakku	437		—do—	—do—
6.	Manzil Have Na Dur	439.91	Asstt. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd. 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block-7, Candhinagar-382010.	'Documentary' Release in Gujarat circuit.
7.	Guinea Worm	291.64	Shri Bal M. Jogleker, 7/6, Shivaji Nagar, Opposite Glaxo, Worli, Bombay-400 018.		'Documentary' General release.
8.	Varta Sanchika	360.00	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Limited, 11-5-423/1, Zafarbag, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004.		'News and Current Events' Release in Andhra Pradesh circuit.
9.	Varta Tarangini No. 50	268.00		—do—	—do—
10.	Maa Ka Pyar	27.45	UNICEF, Ravindra Mansion, D. Vachha Road, Bombay-400 020.	SUKRITI FILMS Kavi Arts, Worli Sea Face Bombay-400 018.	'Documentary' General release.
11.	Do You Know	27.75	—do—	—do—	—do—
12.	Geri	435.86	Asstt. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd., 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block 7, Gandhinagar-382010.	'Documentary' Release in Gujarat circuit.

1	2	3	4	5	6
13.	Maharashtra News No. 395	299.00	Directorate General of Information & Public Relations, Govt. of Maharashtra Film Centre, 68-Tardoo Road, Bombay.		'News and Current Events' Release in Maharashtra circuit.
14.	Portrait of a Painter.	576.99	Debebrata Roy 189/1, Regent Grove, Calcutta-700040.	Debabrata Roy Productions, 189/1, Regent Grove, Calcutta-700 040.	'Documentary' General release.
15.	Indian Navy Today	492.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-400026.		—do—
16.	Mahiti Chitra No. 406.	289.56	Asstt. Director of Information (Films), Govt of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd. Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block 7, Gandhinagar-382 010.	'News and Current Events' Release in Gujarat circuit.
17.	Bihar Samachar Chitr. No. 24	268.48	M. Jha, Film Editor, Govt. of Bihar, Information & Public Relations Department, Patna-1.	Director of Information & Public Relations Department, Govt. of Bihar, Patna.	'News and Current Events' Release in Bihar circuit.
18.	Bihar Samachar Chitra No. 25	274.02	—do—	—do—	—do—
19.	Rural Health	94.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		'Documentary' General release.
20.	Mahiti Chitra No. 407.	298.70	Asstt. Director of Information (Films) Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd., 77- Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block 7, Gandhinagar-382 010.	'News and Current Events' Release in Gujarat circuit.
21.	Dadasaheb Gaikwad	364.00	Shri Dilip Jamdar, M-7/16, Bhanumati, Bangur Nagar, Goregaon (W) Bombay-400 090.		'Documentary' General release.
22.	Bihar Samachar Chitra N.26	257.56	M. Jha, Film Editor, Information & Public Relations Department, Govt. of Bihar, Patna.	Director of Information & Public Relations, Govt. of Bihar, Patna.	'News and current Events' Release in Bihar circuit.
23.	Vihar Samachar Chitra No. 27	293.58	-do-	-do-	-do-
24.	Sevamurti Ravi Shankar Maharaj	599.85	Asstt. Director of Information (Films) Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd. 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block 7, Gandhinagar-382010.	'Documentary' Release in Gujarat circuit.
25.	Pin Code On Your Mail	276.00	K. Vaikunth, 12A, Vinod Villa, B.G. Kher Road, Worli, Bombay-400018.		'Documentary' General release.

1	2	3	4	5	6
26.	Varta Trangini No. 51	278.04	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/1, Zafarbagh, Lakdi-Ka-Pool, Hyderabad-500004.		'News and Current Events' Release in Andhra Pradesh circuit.
27.	Varta Tarangini No. 52	277.74	—do—		-do-
28.	Sarp	470.00	Asstt. Director of Information, Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd., 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-18.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block-7, Gandhinagar-382010	'Documentary' Release in Gujarat circuit.
29.	Rashtriya Natya Vidyalaya	472.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-400026.		'Documentary' General Release.
30.	Varta Tarangni No. 53	286.58	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd. 11-5-423/1, Zafar bagh, Lakdi-ka-pool, Hyderabad- 500004.		'News and Current Events' Release in Andhra Pradesh circuit.
31.	Busy Hands Better Homes	301.75	Purshottam Baokar, 12, Zapurza, Sahitaya Sahawas, Bandra (E) Bombay-400051.	Khadi & Village Industries Commission, Gramodya-Vile Parle, Bombay-400056.	'Documentary' General release.
32.	Mitti Ke Phool	426.72	T. Hussain 9, Chinch Pokli Road, Bandra, Bombay-400050	L.R. Shaikh 51, Haines Road, Mahalaxmi, Bombay 400034.	'Documentary' General release.
33.	Padkar	335.28	Asst. Director of Information (Films) Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd. 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block-7, Gandhinagar-382010.	'Documentary' Release in Gujarat circuit.
34.	Uttar Pradesh Samachar No. 113	284.38	Dhirendra Pande, C/o C/o. M/s. Bombay Film Laboratory (P) Ltd., Bombay.	Dhirendra Pande Producer Newsreel Directorate of Information & Public Relations, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.	'News and Current Events' Release in Uttar Pradesh Circuit.
35.	Uttar Pradesh Samachar No. 114	289.86	-do-	-do-	-do-
36	Krantiguru Dayanand	599.95	Asstt. Director of Information (Films) Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd., 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block-7, Gandhinagar-382010.	'Documentary' General release.

1	2	3	4	5	6
37.	Jivan Saathi	88.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-400026.		'Documentary' General release.
38.	The Elephant Motif in Indian Sculptures	458.73	T.S. Narasimhan, M/s. Komal Productions, 4/54, First Main Road, Tata-Silk Farm Basananagtidi, Bangalore-560004.		'Documentary' General release.
39.	Leather Puppetary of Karnataka	336.80	—do-	-do-	-do-
40.	The Hoysala and Chalukyan Architecture of Karnataka	493.78	-do-	-do-	-do-
41.	Mahiti Chitra No. 409	268.22	Asstt. Director of Information (Films) Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd., 77, Dr. Annie Besant Road, Worli Bombay-400018.	Director of Information, Govt. of Gujarat Sachivalaya, Block-7, Gandhinagar.	'News and Current Events' Release in Gujarat circuit.

[File No. 315/2/86-F(P)]

आदेश

का.आ. 1595.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस.ओ. 3762, दिनांक 2 दिसम्बर, 1986 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिनियम के उपबंध के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को, उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है:—

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लंबाई	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंन्ट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1.	नर्मदे योजना मतें नानी बचत	335.26	सहायक निदेशक सूचना (फिल्म), गुजरात सरकार, रामनार्ड शोध लेबोरेट्रीज, 77, डा. ऐनी बेसेंट रोड वर्ली, बम्बई-400018	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचिवालय ब्लाक 7, गांधी नगर-382010	डाकुमेंट्री फिल्म गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए
2.	संकल्प	548.84	असेन्द्र कुमार, मार्फत मधुनायक, बम्बई फिल्म लेबोरेट्री, दादारा, बम्बई 400028	असेन्द्र कुमार 223, कार्लटन होटल, लखनऊ-226001	डाकुमेंन्ट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए

1	2	3	4	5	6
3.	जागे भविष्य के अधिकारी	380.20	श्रीनिवास जोशी, लिमाये बंगलों, 40/13, भोंडे कालोनी, इरण्वाह, पुणे-4		डाकुमेंन्ट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए
4.	मध्य प्रदेश समाचार दर्शन-48	262.12	आनन्द हतवल्ने मार्फत निदेशक सूचना और प्रचार मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	निदेशक, सूचना और प्रचार . मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म, मध्य प्रदेश सर्कट में प्रदर्शन के लिए
5.	महिती चित्र संख्या 408	298.70	सहायक निदेशक, सूचना (फिल्म), गुजरात सरकार रामनार्ड शो लेबोरेट्रीज लि. डा. ऐनीबेंसेट रोड़, वर्ली, बम्बई-400018	निदेशक सूचना गुजरात सरकार सचिवालय, ब्लाक 7 गांधी नगर	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए
6.	वृक्ष कल्पवृक्ष	300.00	निदेशक, सूचना और जनसम्पर्क, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68, तारदेव रोड़, बम्बई-400034		डाकुमेंट्री फिल्म महाराष्ट्र सर्कट में प्रदर्शन के लिए
7.	बुक्सफार चिलड्रन	347.47	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24, पैडर रोड, बम्बई-400026		डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए
8.	सुख साधन	190.00	फिल्म प्रभाग भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-400026		डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए
9.	इट इज वेरी सिम्पल	77.00	—तथैव—	—तथैव—	तथैव—
1	2	3	4	5	6
10.	अधर	427.94	सहायक निदेशक, सूचना (फिल्म), गुजरात सरकार, रामानार्ड शो लेबोरेट्रीज लि० डा. ऐनी बेंसंट रोड़, वर्ली, बम्बई-400018	निदेशक सूचना गुजरात सरकार सचिवालय ब्लाक-7, गांधी नगर-382010	डाकुमेंट्री फिल्म गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए
11.	वार्ता तरंगिनी संख्या 54	264.94	आन्ध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11-5-423/1, जफरबाग, लकड़ी का पुल हैदराबाद-500004		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म आन्ध्र प्रदेश सर्कट में प्रदर्शन के लिए
12.	वार्ता तरंगिनी संख्या-55	239.02	तथैव		तथैव
13.	उत्तर प्रदेश समाचार संख्या—115	281.94	धीरेन्द्र पाण्डे, न्यूजरील फिल्म, निर्माता उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ	निदेशक सूचना और जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ	समाचार और सामाकिक घटनाओं की फिल्म उत्तर प्रदेश सर्कट में प्रदर्शन के लिए
14.	उत्तर प्रदेश समाचार संख्या—116	275.85	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—

1 2	3	4	5	6
15. मध्य प्रदेश समाचार दर्शन 49	255.42	एस.जी.फिड़वा ड़कर, संयुक्त निदेशक सूचना और प्रचार मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	निदेशक, सूचना और प्रचार, मध्य प्रदेश सरकार भोपाल	समाचार और सामायिक घटनाओं की फिल्म मध्य प्रदेश सर्कट में प्रदर्शन के लिए
16. कलमकारी	251.16	होमी एस सेठना, 72, अशोका एपार्टमेंन्टस, रूंगतालेन, कार्यालय एल. जगमोहन दास मार्ग, बम्बई-400006		डाकुमेन्ट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए
17. नारद अनाद	491.34	सहायक निदेशक, सूचना गुजरात सरकार, रामनार्ड शोध लेबोरेट्रीज लि., 77, डा. ऐनी बेंसेट रोड़, वर्ली, बम्बई-400018	निदेशक सूचना, गुजरात सरकार सचिवालय, गांधी नगर-382010	डाकुमेन्ट्री फिल्म गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए
18. बाल रंग भूमि	268.40	सूचना और जनसम्पर्क महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, 68, तारदेव रोड़, बम्बई-400034	फिल्म सेंन्टर	डाकुमेन्ट्री फिल्म महाराष्ट्र सर्कट में प्रदर्शन के लिए
16. व्हेयर इज दी हरी	80.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड़, बम्बई-400026	फिल्म प्रभाग भारत सरकार 4—टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली	डाकुमेंन्ट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए
20. टाइम आफ हैप्पीनैस.	75.00	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
21. राजा राम मोहन राय	556.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26	फिल्म प्रभाग, सरकार, 24, पैडर रोड़, बम्बई-26	—तदैव—
22. दी लांग आफ ला	550.00	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
23. पोलीसाची दिवाली	201.00	सूचना और जनसम्पर्क महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार फिल्म सेंन्टर, 68, तारदेव रोड, बम्बई-400034		डाकुमेन्ट्री फिल्म महाराष्ट्र सर्कट में प्रदर्शन के लिए
26. सिम्बल आफ होप	301.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24, पैडर रोड, बम्बई-400026		डाकुमेंन्ट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए
25. ईजी वे	86.00	फिल्म प्रभाग 24, पैडर रोड, बम्बई-400026	फिल्म प्रभाग भारत सपकार, 4, टालस्टाय मार्ग, बम्बई-400026	—तथैव—
26. कन्ट्रोलिंग लेपरोसी	548.64	श्री दहियाँ भाई भक्त 1/13, गुरु नगर फोर बंगलोज वसँवा रोड, अंधेरी (प) बम्बई-400058	गांधी मैमेरियल लेपरोसी फाउडेशन डाकखाना हिन्दी नगर वर्धा, महाराष्ट्र	डाकुमेंन्ट्री फिल्म के लिए
27. ऐनीटास्क, ऐनीटाइम ऐनीव्हेयर	477.00	फिल्म प्रभाग भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-400026		—तथैव—

1	2	3	4	5	6
28.	बंडर गिफ्ट	146.00	फिल्म प्रभाग भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26	फिल्म प्रभाग भारत सरकार 4—टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली	—तथैव— समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म
26.	महाराष्ट्र न्यूज नं. 366	300.00	सूचना और जनसम्पर्क महानिदेशालय, महाराष्ट्र, सरकार फिल्म सेंटर 68, तारदेव रोड, बम्बई-400034		महाराष्ट्र सर्कट में प्रदर्शन के लिए ।

[फाइल संख्या 315/2/86—एफ (पी)]

सुकुमार मण्डल, डैस्क अधिकारी

ORDER

S.O.1595.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the Order of the Government of India in the-Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated 2nd December,1966 the Central Government after considering recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length of the film in metres	Name of the Applicant	Name of the Producer	Brief synops whether a scientific film or for educational purpose or a film dealing with news & current event or documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Narmade Yojana Mate Nani Bachat	335.26	Asstt. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratories, 77-Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block-7, Gandhinagar-382 010.	'Documentary Release in Gujarat circuit.
2.	Sankalp	548.84	Asendra Kumar, C/o Sri Madhu Naik, Bombay Film Laboratory, Dadar, Bombay-400028.	Asendra Kumar, 223, Carlton Hotel, Lucknow 226 001.	'Documentary' General releare.
3.	Jago Bhavishya Ke Adhikari	380.20	Shrinivas Joshi, Limaye Colony, Erandwanh-Pune.-4	Bungalow, 40/13, Bhonde Colony, Pune-4	—do—
4.	Madhya Pradesh Samachar Darshan-48	262.12	Anand Hatvalne C/o Director Information & Publicity Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.	Director of Information & Publicity Govt. of Madhya Pradesh Bhopal.	'News & Current Events' Release in Madhya Pradesh circuit.
5.	Mahiti Chitra No. 408	298.70	Assit. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratories Ltd. Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block-7, Gandhinagar.	'News and Current Events Release in Gujarat circuit.

1	2	3	4	5	6
6.	Vriksha, Kalpavriksha	300.00	Directorate General of Information and Public Relations, Govt. of Maharashtra Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-400 034.		'Documentary' Release in Maharashtra circuit.
7.	Books for Children	347.47	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		'Documentary' General release.
8.	Sukh Sadhan	190.00	—do—		—do—
9.	It is Very Simple	77.00	—do—		—do—
10.	Adhar	427.94	Asstt. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratories Ltd., Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block-7, Gandhinagar-382 010.	'Documentary' Release in Gujarat circuit.
11.	Varta Tarangini No. 54	264.94	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/1 Zafaragh, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500004.		'News and Current Events' Release in Andhra Pradesh circuit.
12.	Varta Tarangini No. 55.	239.02	—do—		—do—
13.	Uttar Pradesh Samachar No. 115	281.94	Dhirendra Pande, Newsreel Film Producer, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.	The Director of Information and Public Relations, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.	'News and Current Events' Release in Uttar Pradesh circuit.
14.	Uttar Pradesh Samachar No. 116	275.85	—do—	—do—	—do—
15.	Madhya Pradesh Samachar Darshan–49	255.42	Shri S. G. Krishnadhar Jt. Director, Information & Publicity, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.	Director of Information & Publcity, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.	'News and Current Events' Release in Madhya Pradesh circuit.
16.	Kalamkari	251.16	Homi S. Sethna, 72, Ashoka Apartments, Rungta Lane, Off. L. Jagmohandas Marg, Bombay-400 006		'Documentary' General release.
17.	Narad Anarad	491.34	Asstt. Director of Information, Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd., 77, Dr. Anni Beseant Road, Worli, Bombay-400 018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachaivalaya, Gandhinagar, 382010.	'Documentary' release in Gujarat circuit.
18.	Bal Rang Bhoomi	298.40	Directorate General of Information and Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-400 034.		'Documentary' Release in Maharashtra circuit.
19.	Where is the Hurry ?	80.00	Films Division, Govt. of India, 24-Pedder Road, Bombay-400 026.	Films Division Govt. of India 4-Tolstoy Marg, New Delhi.	'Documentary' General release.
20.	Time of Happiness	75.00	—do—	—do—	—do—
21.	Raja Rammohan Roy.	559.00	Film Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		'Documentary' General release.
22.	The Long Arm Of Law.	550.00	—do—		—do—

23. Polisanchi Diwali	201.00	Directorate General of Information and Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-400 034.		'Documentary' Release in Maharashtra circuit.
24. Symbol Of Hope	301.00	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-400026.		'Documentary' General release.
25. Easy Way	86.00	—do—	Film Division Govt. of India, 4-Tolstoy Marg, New Delhi.	—do—
26. Controlling Leprosy	548.64	Dahyabhai Bhakta, 1/13, Guru Nagar, Four Bungalows, Versova Road, Andheri (W) Bombay-400058	Gandhi Memorial Leprosy Foundation P.O. Hindi Nagar, Wardha, Maharashtra.	—do—
27. Any Task, Any Time, Any where	477.00	Films Division, Govt. of India, 24 Peddar Road, Bombay-400 026.		—do—
28. Wonder Gift	146.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.	Films Division, Govt. of India, 4-Tolstoy Marg, New Delhi-110 001.	—do—
29. Maharashtra News No. 396	300.00	Directorate General of Information & Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-400 034.		'News and Current Event' Release in Maharashtra circuit.'

[File No.315/2/86-F(P)]

SUKUMAR MANDAL, Desk Officer

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1986

का.आ. 1596:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने कुगालुर, ठकानई केनपालायम तथा नांबियुर टेलीफोन केन्द्रों, तमिल नाडु, में दिनांक 21-4-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं. 5-26/86-पी. एच. बी.]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Deptt. of Telecommunications)

New Delhi, the 7th April, 1986

S.O. 1596.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Department of Telecommunications, hereby specifies 21-4-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kugalur, Thuckanaickenpalayam and Nambiyar Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-26/86-PHB]

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1986

का.आ. 1597:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने अजागप्पापुरम, कुरुक्कलपट्टी तथा वीरावानल्लूर टेलीफोन केन्द्रों, तमिलनाडु, में दिनांक 28-4-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं. 5-25/86-पी. एच. बी.]

New Delhi, the 8th April, 1986

S.O. 1597.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 28-4-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Azhagappapuram, Kurukkalpatti and Veeravanallur Telephone Exchanges, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-25/86-PHB]

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1986

का. आ. 1598:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूर संचार विभाग ने गंगापुर सिटी टेलीफोन केन्द्र, राजस्थान में दिनांक 25-4-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-31/86-पी. एच. बी.]

के. पी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (पी.एच.बी.)

New Delhi, the 14th April, 1986

S.O. 1598.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 25-4-1986 as the date on which the Measured System will be introduced in Gangapur City Telephone Exchanges, Rajasthan Circle.

[No. 5-31|86-PHB]

K P. SHARMA, Assistant Director General (PHB)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1986

का. आ. 1599.—मैसर्स विजयानगर स्टील लिमिटिड, रजिस्टर्ड आफिस शंकरानारायम बिलिडंग-25, एम. जी. रोड, बंगलौर (के. एन./10381) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2 क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी खर्चों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम की नियमों की एक प्रति और जब कभी अनमों संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/139/86-एस. एस.-II]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 31st March, 1986

S.O. 1599.—Whereas Messrs Vijayanagar Steel Limited Regd. Office, Shankaranarayana Building, 25, Mahatma Gandhi Road, Bangalore-I (KN/10381) (hereinafter referred to as the said establishment have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bangalore maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses invloved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme, be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bangalore and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grent of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case wihin one month from the receipt of the claim complete all respects.

[No. S-35014/139/86-SS-II]

का. आ. 1600.—मैसर्स अरकोट टेक्सटाईल मिल्ज़ लि., पो.बो. नं. 1 कलाक्करीची-606202 एस.ए. जिला तमिलनाडु (टी.एन./6091) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थान के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(140)/86-एस.एस.-2]

S.O. 1600.—Whereas Messrs Arcot Textile Mill Limited, Post Box No. 1, Kalla Kuridhi-606202, South Arcot, Tamil Nadu (TN/6091) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. The employer involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on that Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme, be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund

Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(140)/86-SS II]

का. आ. 1601.—मैसर्स दि मालवा को. ओ. मिल्क प्रोड्यूसरज यूनियन लिमिटेड, संगरूर पंजाब (पी. एन./4635) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (ख) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(143)/86-एस.एस.-2]

S.O. 1601.—Whereas Messrs. The Malwa Co-operative Milk Producres Union Limited, Sangrur (Punjab) (PN/4635) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme, be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(143)/86-S-II]

का. आ. 1602.—मैसर्स राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड, भगवान दास रोड, जयपुर-302005 (आर. जे./1564) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सामंजस्य रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(125)/86-एस.एस.-2]

S.O. 1602.—Whereas Messrs Rajasthan Housing Board, Bhagwan Das Road, Jaipur 302005 (RJ/1564) (hercinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Secton 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submisson of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme, be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(125)/86-SS-II]

का. आ. 1603.—मैसर्स सुनील टेक्सटाइल मिल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड, हमीरगढ़ रोड, पो. बाक्स नं. 27, भिलवाड़ा (आर. जे./3550) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (19 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसके बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी की विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(129)/86-एस.एस.-2]

S.O. 1603.—Whereas Messrs. Suneel Textile Mills (Private) Limited, Hamirgarh Road, P. B. No. 27, Bilwara-311001, (RJ|3550), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provides such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. Shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith, a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir| nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(129)|86-SS-II]

का. आ. 1604.—मैसर्स कैटल फिडप्लांट, नदबाई, भरतपुर (ए यनिट आफ राजस्थान को. आ. डेरी फेडरेशन लिमिटेड नजदीक गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर आर. जे/2798) (जिसे इसमें पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है (की धारा 17 की उपधारा 2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत खाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उस के स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित् करेगा ।

[संख्या एस-35014(131)/86-एस एस-2]

S.O. 1604.—Whereas Messrs. Cattle Feed Plant, Nabbal, Bharatpur (A Unit of Rajasthan Cooperative Dairy Federation Limited, Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur) (RJ|2798) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Com-

missioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Goveernment and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir| nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case with one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(131)|86-SS-II]

का. आ. 1605.—राजस्थान को-आपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड, नजदीक गांधी नगर रेलवे स्टेशन, जयपुर (आर. जे./2406) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों तो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय

होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/147-86-एस. एस.-2]

S.O. 1605.—Whereas Messrs. Rajasthan Co-operative Dairy Federation Limited, Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur (RJ|2406) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir| nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(147)|86-SS-II]

का. आ. 1606 :—राजस्थान राज्य सहकार भूमि विकास बैंक लिमिटेड, पो. बा. 55, नेहरू बाजार, जयपुर (आर. जे./931), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया

है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/14?/86-एस. एस.-2]

S.O. 1606.—Whereas Messrs. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd, P. B. 55, Nehru Bazar, Jaipur, (BJ/931) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case with one month from the receipt of claims complete in all respect.

[No. S-35014(145)|86-SS-II]

का. आ. 1607 :—मैसर्स अलवर डेरी प्लांट, (अलवर) राजस्थान को-आपरेटिव डेरी फैडरेशन लि. को एक शाखा गांधी नगर रेलवे स्टेशन के निकट जयपुर (आर. जे./2722), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के

सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनु- के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को पूर्व अनुमोदन कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/124/86-एस. एस.-2]

S.O. 1607.—Whereas Messrs. Alwar Dairy Plant Alwar (A Unit of Rai, Co-operative Dairy Federation Ltd., Near Gandhi Nagar, Railway Station, Jaipur) (RJ|2722) (hereinafter) referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) 'hereafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direction from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. Shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life

Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(124)/86-SS-II]

का. आ. 1608 :—मैसर्स कैटेल फीड प्लांट जोधपुर (राजस्थान कोऑपरेटिव डेरी फैडरेशन लि. जयपुर की एक शाखा) (आर. जे./3242), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संबंधी आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपबन्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/130/86-एस. एस.-2]

S.O. 1608.—Whereas Messrs. Cattle Feed Plant, Jodhpur (A Unit of Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd., Jaipur) (RJ|3242) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case with one month from the receipt of claims complete in all respect.

[No. S-35014(130)|86-SS-II]

का. आ. 1609.—मैसर्स अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटिड "दुग्ध भवन" नियर सरकल हाऊस, अलवर, राजस्थान (आर. जे./2445) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2 क के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय

आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पॉलिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(127)/86-एस. एस.-2]

S.O. 1609.—Whereas Messers. Alwar Zila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Limited, Dugdh Bhawan Near circuit House Alwar-301001 Rajasthan (RJ|2445) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. Shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan

and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(127)/86-SS-II]

का. आ. 1610 :—मैसर्स जयपुर डेरी प्लांट जयपुर [ए यूनिट आफ राजस्थान को. ओ. डेरीफैडरेशन लिमिटिड, नियर गांधी नगर रेलवे स्टेशन जयपुर] (आर. जे./2952) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2 क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एकप्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पॉलिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/128/85-एस. एस.-2]

S.O. 1610.—Whereas Messrs Jaipur Dairy Plant, Jaipur (A Unit of Rajasthan Co-Op. Dairy Fedn. Ltd., near Gandhi Nagar, Railway Station, Jaipur-7) (RJ-2952) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(128)86-SS-II]

का. आ. 1611.—जोधपुर डेरी प्लांट (ए यूनिट आफ राजस्थान को-आपरेटिव डेरी फैडरेशन लि., जयपुर) जोधपुर (आर. जे./2672) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे

लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पॉलिसी का व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[एस-35014/144/86-एस. एस.-2]

S.O. 1611.—Whereas Messrs. Jodhpur Dairy Plant, (A Unit of Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd., Jaipur) Jodhpur (RJ|2672) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are

more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(144)/86-SS-II]

का. आ. 1612.—मैसर्स नवीन इन्डस्ट्रीज, 18-ए करोस चिनमाया मिशन अस्पताल रोड, लक्ष्मीपुरम, ऊलसूर, बंगलौर (के. एन./8494) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एकप्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(132)/86-एस.एस.-2]

S.O. 1612.—Whereas Messrs Naveen Industries, 18A Cross, Chinmaya Mission Hospital Road, Lakshmipuram, Ulsoor, Bangalore-8. (KN|8494) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(132)/86-SS-II]

का. आ. 1613.—मैसर्स जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कैरियर (रजिस्टर्ड) कालूपुर कोरिपिठा, टेलियमिल्ज कैम्प, अहमदाबाद (जि. जे./3775) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर की रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/142/86-एस. एस -2]

S.O. 1613.—Whereas Messrs Jaipur Golden Transport Carriers (Regd.) Kalnpur Keripitha, Teliya Mills Compound, Ahmedabad (GJ|3775) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Gujarat maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(142)/86-SS-II]

का. आ. 1614.—मैसर्स प्रीसिशन टेलकम प्रोडक्ट्स नं. बी-17, आई. टी. आई. एनसिलरी इंडस्ट्रीयल एस्टेट महादेवपुरी, बंगलौर-48 (के. एन.-6369) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बंगलौर को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम की नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बंगलौर के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(136)/86-एस. एस.-II]

S.O. 1614.—Whereas Messrs Precision Telecom Products, No. B-17, ITI Ancillary Industrial Estate, Mahadevapura, Bangalore-18 (KN|6369) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bangalore maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bangalore and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(136)/86-SS-II]

का. आ. 1615.—मैसर्स मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि., 225 एफ, ए.जी.सी. बोस रोड, कलकत्ता-700020 (डब्ल्यू. बी./12726) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976

(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 330 तारीख 6-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 8-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 7-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/396/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1615.—Whereas Messrs Metal Scrap Trade Corporation Limited, 225-F, AJC, Bose Road, Calcutta-700020 (WB/12526) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 330 dated the 6-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 8-1-1986 upto and inclusive of 7-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thedeof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where, any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner. the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/396/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1616.—मैसर्स टैक्लोमिट इन्डिया लिमिटिड, गोपालपुर, बज रोड, पो.आ. सरकारपुल जिला 24 परगना (वेस्ट बंगाल/7767) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 608 तारीख 11-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 22-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/397/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1616.—Whereas Messrs Tecalemit India Limited, Gopalpur, Budge Road, P.O. Sarkarpool, District 24 Parganas (WB/7767) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 608 dated the 11-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-1-1986 upto and inclusive of 21-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where, any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/397/82-PF-II(SS II)]

का. आ. 1617.—मैसर्स नेमको हैड्रॉलिक्स लि., उद्यमबाग कनपुर रोड, बेलगांव-59008 (के. एन./168) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,

1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 607 तारीख 11-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 22-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3 क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमादित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक स्कीम के कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/398/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1617.—Whereas Messrs Bemco Hydraulics Limited, Udyambag Khanepur Road, Belgaum-590008 (KN/168) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 607 dated the 11-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-1-1986 upto and inclusive of 21-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the sallent features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where, any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/398/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1618 :—मैसर्स, एस. एण्ड एच. गियर्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टेशन रोड, दिवास, मध्य प्रदेश (एम. पी./2766) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 397 तारीख 9-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 15-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 14-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाय, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों को लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिति/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/377/86-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1618.—Whereas Messrs S. and H. Private Limited, Station Road, Dewas, MP (MP/2766) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 397 dated the 9-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 15-1-1986 upto and inclusive of 14-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee, the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where, any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/377/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1619 :—मैसर्स इण्डिया पैकेजिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 24895 मील, बेलरी रोड बंगलौर 24 (के. एन./3657) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा

गया है (ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 37 तारीख 9-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 31-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एकप्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी लागू अंशदायक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों को लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन सब सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती-विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/379/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1619.—Whereas Messrs India Packaging Products Private Limited, P.B. No. 2480, 5th Mile, Bellary Road, Bangalore-24 (KN/3657) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 37 dated the 9-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-1-1986 upto and inclusive of 31-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka and where, any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employee in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/379/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1620 :—मैसर्स ग्रीव्स कौन किलियमग लिमिटेड, स्कीप एण्ड फास्टनर्स डिविजन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, भानडुप, बम्बई-400028 (एम एच./9074) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 732 तारीख 17-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 29-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 28-1-1939 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के

किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां (i) भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उस मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/307/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1620.—Whereas Messrs. Guest Kean Williams Limited, Screws and Fasteners Division, Lal Bahadur Shastri Marg, Bhandup, Bombay-400078 (MH|9074) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 732 dated the 17-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 29-1-1986 upto and inclusive of 28-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where, any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employee in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the

Legal heirs of the deceased entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/307/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1621.—मैसर्स गाजरा बिवेल गियरस लिमिटेड, इण्डस्ट्रियल एरिया, ए. बी. रोड, देवास—मध्य प्रदेश (एम. पी./3424), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 613 तारीख 13-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 22-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन की सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिति/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/366/82-पी. एफ.-2/एस. एस.-2]

S.O. 1621.—Whereas Messrs Gajra Bavel Gears Limited, Area, AB Road, Dewas-MP-455001 (MP/3424) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 613 dated the 13-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-1-1986 upto and inclusive of 21-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/366/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1622.—मैसर्स किरलोसकर ब्रदर्स लिमिटेड, कोथरूड, पूणे-411029 (एम.एच./7063), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 612 तारीख 13-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 22-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य

निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थान में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात की होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/367/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1622.—Whereas Messrs Kirloskar Commins Limited, Kathrud, Poona-411029 (MH/7063) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 612 dated the 13-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-1-1986 upto and inclusive of 21-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life

Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/367/82-PF-II (SS-II)]

का.आ. 1623.—मैसर्स दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, 8 क्लाइवरो, कलकत्ता-700001 (डब्ल्यू.बी/634 और डब्ल्यू., बी./637), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 898 तारीख 18-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 12-2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 11-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, शिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति से एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/371/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1623.—Whereas Messrs Dishergarh Power Supply Company Limited, 8, Clive Row, Calcutta-700001, (WB/634 & WB/637) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 898 dated the 18-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12-2-1986 upto and inclusive of 11-2-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to employees under the scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/371/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1624.—मैसर्स सूबील फैब्रीकेटर्स, 33-ए., इण्डस्ट्रियल एरिया, गोविन्द पुरा-462023, भोपाल (एम. पी./2055), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 34 तारीख 6-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 31-12-1982 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन की सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिति/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/375/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1624.—Whereas Messrs Sushil Fabricators 33-A, Industrial Area, Govindpur-462023, Bhopal (MP/2055) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 34 dated the 6-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-1-1986 upto and inclusive of 31-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language or the maiority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/375/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1625.—मैसर्स डाबर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, 70 लक्ष्मी इन्शोरेंस बिल्डिंग सर पी. राम रोड, बम्बई (एम. एच./6797)- (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 408 तारीख 10-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 15-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 14-1-1986 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्रा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात की होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्रा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त

स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिति/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/404/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1625.—Whereas Messrs Daver Engineering Private Limited, 70, Lakshmi Insurance Building, Sir P.M. Road, Bombay (MH/6797) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 408 dated the 10-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 15-1-1986 upto and inclusive of 14-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/404/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1626.—मैसर्स अमर निटिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड, इन्डस्ट्रियल एरिया, तानसेन रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश (एम.पी./1800) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 20 तारीख 6-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 31-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम की सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/289/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1626.—Whereas Messrs Amar Knitting Works Private Limited, Industrial Area, Tansen Road, Gwalior-MP (MP/1809) (hereinafter referred to as the said establishment(have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 20 dated the 6-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-1-1986 upto and inclusive of 31-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount apayable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premia the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/289/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1627.—मैसर्स अम्बर कार्पोरेशन, तानसेन रोड, ग्वालियर-474002 (एम.पी./2261) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसकी पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4075 तारीख 12-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 3-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति की 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम की अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/248/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1627.—Whereas Messrs Amber Corporation, Tansen Road, Gwalior-474002 (MP/2261) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hreinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4075 dated the 12-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-12-1985 upto and inclusive of 3-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/248/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1628.—मैसर्स एम. जी. ई. एफ. लिमिटिड सेल्स आफिस बाम्बे रियसकिनोन हाऊस, ई. मोसिस रोड, महालक्ष्मी बम्बई-400011 (एम. एच./17509) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4068 तारीख 12-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 3-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निदेशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/207/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1628.—Whereas Messrs NGEF Limited, Sales Office Bombay Tiecicon House, E Moses Road, Mahalaxmi, Bombay-400011 (MH/17509) (hereinafter referred to as the said establishment(have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Eployees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter refered to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hreinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4068 dated the 12-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-12-1985 upto and inclusive of 3-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/207/82-PF-II (SS-II)]

का.आ. 1629.—मैसर्स मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम प्लाट नं. 18, मालवीया नगर, भोपाल-462003 (एम.पी./3583), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और, ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 907 तारीख 21-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 12-2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 11-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि

का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/361/82-पी० एफ० 2/एस. एस. II]

S.O. 1629.—Whereas Messrs Madhya Pradesh Rajya Bhoomi Vilkas Nigam Plot No. 18, Malviya Nagar, Bhopal-462003 (MP)/3583) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment, are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and incontinuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 907 dated the 21-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto to the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12-2-1986 upto and inclusive of 11-2-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient, features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No. amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/361/82-PF.II(SS.II)]

का.आ. 1630 :—मसर्स किनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड डी-1, ब्लाक प्लाट नं. 18/2, चिनाचिंचवाड, पूणे-411019 (एम.एच/14219), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध (बीमा स्कीम 1976) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 737 तारीख 17-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 29-1-1986 से तीन वर्ष की

अवधि के लिए जिसमें 28-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर, इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्यों की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय, तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(358)/82पी.एफ.-2/एस. एस-2]

S.O. 1630.—Whereas Messrs Kinetic Engineering Limited D-1 Block, Plot No. 18/2, Chinchwad, Pune-411019(MH/14219) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and incontinuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 737 dated the 17-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 29-1-1986 upto and inclusive of 28-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintainance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient, features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No. amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of able opportunity to the employees to explain their point of deceased members who would have covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|358|82-PF. II(SS II)]

का.आ. 1631:—मैसर्स श्री वेंकटेसा पेपर एन्ड बोर्ड (प्राइवेट) लिमिटिड, स्वामीनाथापुरम, महाथकुलमपोस्ट, 642113, उदुमुटपट तालुक (टी.एन/11266), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4134 तारीख 22-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापना को, 11-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 10-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक, बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन, मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/318/82-पी० एफ०-2-एस.एस-2]

S.O. 1631.—Whereas Messrs Sri Venkatesa Paper and Boards (Private) Limited, Swaminathapuram, Madathukulam Post 642113, Udumalpet Taluk, (TN|11266) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment, are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4134 dated the 22-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto to the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 11-12-1985 upto and inclusive of 10-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient, features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount

payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No. amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/318/82-PF. II(SS.II)]

का.आ. 1632.—मैसर्स जय हिन्द सायकी लिमिटिड, डी-1 ब्लाक, फ्लाट नं. 18/1, चिमाचिवाड, पूना-411018 (एम.एच/14766), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वह ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4267 तारीख 26-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की, 18-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014 (314)/82 पी० एफ० 2-एस. एस-2]

S.O. 1632.—Whereas Messrs Jay-Hind Sciaky Limited D1 Block, Plot No. 18/1, Chinchwad, Pune-411019(MH/14766) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment, are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and incontinuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4267 dated the 26-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto to the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of 17-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rule of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient, features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/314/82-PF.II(SS.II)]

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1986

का. आ. 1633.—मैसर्स सोमासुन्दाराम सुपर स्पीनिंग मिल्ज मुथानन्दल (पोस्ट-623602) (नजदीक) मानामदुराई रामानन्द जिला तमिलनाडु (टी. एन./5323), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण की लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययभार का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन की सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/148/86-एस. एस.-2]

S.O. 1633.—Whereas Messrs. Somasundaram Super Spinning Mills, Muthanendal (Post) 623602, (Near) Manamadural Ramnand Distt., Tamil Nadu (TN/5323) (hereinafter as referred to as the said establishment) have applied to exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on that Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme, be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case wihin one month from the receipt of the claim complete in all respects.

[No. S-35014(148)/86-SS-II]

का. आ. 1634.—मैसर्स श्री रानी मिल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड 2/38 चिनामप्लाम कोयम्बटूर (टी. एन.-11102) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त छूट के सम्बन्ध में **नियोजक इस स्कीम** के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/146/86-एस.एस.-2]

S.O. 1634.—Whereas Messrs. Sri Rani Mills (Private) Limited, 2/38, Chinniampalayam, Combatore-641062 (TN/11102) (hereinafter or referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on that Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme, be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(146)/86-SS. II]

का.आ. 1635.—मैसर्स देसीन (नई दिल्ली) प्राइवेट लिमिटिड देसीन हाऊस, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048 (डी.एल./3406) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3495 तारीख 18-9-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 2-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 1-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, जो प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि

के हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014 (192)/82-पी० एफ 2/एस. एस.-2]

S.O. 1635.—Whereas Messrs Desain (New Delhi) Private Limited Desain House, Greater Kailash II, New Delhi-110048 (DL/3406) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment, are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3495 dated the 18-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto to the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 2-10-1985 upto and inclusive of 1-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient, features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No. amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of dedeceased members who would have covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/192/82-PF. II(SS.II)]

का.आ. 1636:—मैसर्स किलोस्कर फिल्टरस प्राइवेट लिमिटिड "प्रतिभा" 758/104, दक्कन जिमखाना, पुणे-411004, (एम.एच/12280), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और वे ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 619 तारीख 13-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 22-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, जो प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा कृत राशि के हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/286/82 पी० फ० 2-एस.एस-II]

S.O. 1636.—Whereas Messrs Kirloskar, Filters Private Limtied 'Pratibha' 759/104, Deccan Gymkhana, Pune-411004 (MH/12280) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 619 dated the 13-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-1-1986 upto and inclusive of 21-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life insurance corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under hte said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|286|82-PF. II(SS. II)]

का. आ. 1637 :—मैसर्स व्यैय लैबोटरीज लिमिटिड, एल. बी. शास्त्री मार्ग, घाट कोपर, बम्बई-400086 (एम. एच. 6714), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 315 तारीख 26-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 8-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 7-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, उक्त नियोजक स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/347/82-पी. एफ./एस. एस-2]

S.O. 1637.—Whereas Messrs Wyeth Laboratories Limited, LB Shastri Marg, Ghatkapar, Bombay-4000086(MH|6714) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of the life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 315 dated the 26-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 8-1-1986 up to and inclusive of 7-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees, Pvroident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to he employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the

amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not reamin covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium, etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/39/82-PF. II(SS. II)]

का.आ. 1628 :—मैसर्स फूड स्पैशलिटीज लिमिटिड, एम-5ए, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 (डी.एल/4398), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम का सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3138 तारीख 17-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 3-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त,

अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014196/82-पी.एफ.-2 एस०एस०-2]

S.O. 1638.—Whereas Messrs Food Specialities Limited, M-5A, Connaught Circus, New Delhi-110001 (DL|4398) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3138 dated the 17-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-9-1985 up to and inclusive of 3-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendement of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/196/82-PF. II (SS. II)]

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1986

का.आ. 1639 :—मैसर्स पिनकार्ड इन्डस्ट्रीज, 3453/57, देहली गेट, नई देहली-110006)डी.एल./2654), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है !

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम का सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2803 तारीख 13-7-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 31-7-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 30-7-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली को ऐसे विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसके मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस–35014/77/82–पीएफ-2/एस. एस-2]

New Delhi, the 7th April, 1986

S.O. 1639.—Whereas Messrs Picord Industries, 3453|57, Delhi Gate, New Delhi-110006 (DL|2654) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2803 dated the 13-7-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 31-7-1985 upto and inclusive of the 30-7-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-secion (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insuranee Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the acount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insuracne Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable Opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|77|82-PF.II(SS-II)]

का. आ. 1640:- मैसर्स मोहन फूड इन्डस्ट्रीज (इन्डिया लि.) (जो पहले मोहन बेक्रीज (इन्डिया) लि., के नाम) से जाना जाता था (पुराना एम्बार्किशन ग्राउन्ड, ताराताला रोड, कलकत्ता-700088 (डब्ल्यू. बी/15281) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3607 तारीख 27-9-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 16-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 15-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(104)/82-पी.एफ.-2/एस. एस-2]

S.O. 1640.—Whereas Messrs Modern Food Industries (India) Limited (Formerly known as Modern Bakaries (India) Limited) Old Exhibition Ground, Taratala Road, Calcutta-700088 (WB)|15281) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Cenral Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976(hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefors, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3607 dated the 27-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 16-10-1985 upto and inclusve of the 15-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund

Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/104/82-PF. II (SS. II)]

का. आ. 1641.—मैसर्स कैटल फिजप्लाट (ए यूनिट आफ राजस्थान को. ओ. डेरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर) टोबोजी, अजमेर (आर. जे./2775) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी

स्थापन की भविष्यनिधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसके बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है के अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर निश्चित् करेगा ।

[संख्या एस-35014(126)/82-एस एस-4]

S.O. 1641.—Whereas Messrs Cattle Feed Plant (A Unit of Rajasthan Co-op. Diary Federation Limited Jaipur) Tabiji, Ajmer, (RJ|2775) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of this majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(126)/86-SS-II]

का. आ. 1642.—मैसर्स हिल्टन रबर्स प्राइवेट लिमिटिड, हिन्द हिल्टन हाऊस एफ-23, ग्रीन पार्क एक्सटेन्शन, नई दिल्ली 110016 (डी. एल/3141) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3401 तारीख 9-9-1682 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 25-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 24-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसके मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में यह उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014 (157) 82/86-एस.एस.-2]

S.O. 1642.—Whereas Messrs Hilton Rubbers Private Limited, Hilton House, S-23, Green Park Extension, New Delhi-110016 (DL|3741) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976(hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3401 dated the 9-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 25-9-1985 upto and inclusive of the 24-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely o affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure promot payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|157|82-PF. II(SS. II)]

का. आ.—1643मैसर्स नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, वन्दना बिल्डिंग, बसवीं मंजिल कमरा नं 11, टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 (डी. एल./2980) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 16) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त

अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को जो उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2952 तारीख 4-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 27-8-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 28-6-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(195)/82/पी.एफ. एस.-2

S.O. 1643.—Whereas Messrs National Textiles Corporation Limited Vandana Building, 10th Floor, Room No 4, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 (DL/2988), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under

sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2952 dated the 4-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 27-8-1985 upto and inclusive of the 26-8-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/195/82-PF.II(SS.II)]

का. आ० 1644.—मैसर्स इन्डियन आक्सीजन लिमिटेड, भास्कर भवन, भिमली रोड, विशाखापटनम-530013 (ए. पी./236) और मैसर्स इन्डियन आक्सीजन लिमि. फतेह मैदान रोड, हैदराबाद (ए. पी. 1951) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण पबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3538 तारीख 23-9-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 9-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 8-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा

(3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसका मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन या भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि का जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे इन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम से किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसा को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(202)/82-एस.एस-2 पी एफ -2]

S.O. 1644.—Whereas Messrs Indian Oxygen Limited, Bhaskar Bhavan, Bhimli Road, Vishakhapatnam-530013 (AP)236) and Messrs Indian Oxygen Limited, Fathemeidan Road, Hyderabad (AP)1951), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3538 dated the 23-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 9-10-1985 upto and inclusive of the 8-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the

salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/202/82-PF.II(SS.II)]

का. आ 1645— मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, 1, शेक्सपियर सरणी, आठवीं मंजिल, कलकत्ता-700007 (डब्ल्यू. बी. 12619) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1652 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3342 तारीख 27-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 18-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-9-1888 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/207/82-पी.एफ-2]

S.O. 1645.—Whereas Messrs Hindustan Steel Works Construction Limited, 1, Shakespeare Sarani (8th Floor) Calcutta-700071 (WB|12619), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3342 dated the 27-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-9-1985 upto and inclusive of the 17-9-1988.

SCHEDULE

1. The employers in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal maintain such accounts and provided such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any

case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/207/82-PF.II(SS.II)]

का. आ. 1646:—मैसर्स सैंडाबिक एशिया लि. वाम्बे-पूना रोड, पूना-411012 (एम. एच/5949) तथा इसकी बम्बई, बंगलौर, कलकत्ता, नई दिल्ली तथा मद्रास स्थित शाखाएं जो इसी कोड नम्बर के अन्तर्गत आती हैं। (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 328 तारीख 6-12-1986 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 8-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 7-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/251/82-एस.एस-2]

S.O. 1646.—Whereas Messrs Sandvik Asia Limited, Bombay Poone Road, Poone-411012 including its branches at Bombay, Bangalore, Calcutta, New Delhi and Madras covered under Code No. MH/5949 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 328 dated the 6-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 8-1-1986 upto and inclusive of the 7-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/251/82-PF.II(SS.II)]

का. आ 1647:—मैसर्स सुकुम कैमिकल्स, प्लाट नं. 10/3, जी. आई. डी. सी. एस्टेट बरवा, अहमदाबाद (जी. जे/9295) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4257 तारीख 26-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 18-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, यह इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(253)/82-पी.एफ.-2/एस. एस-2]

New Delhi, the 7th April, 1986

S.O. 1647.—Whereas Messrs Sukam Chemicals, Plot No. 10|3, GIDC Estate, Vatva, Ahmedabad (GJ|5295) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4257 dated the 26-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of the 17-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/258/82-PF.II(SS.II)]

का०आ० 1648 :—मैसर्स भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम (आ०प्रा०/3495) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 4260 तारीख 26-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 18-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आंध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजकों द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आंध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/262/82-पी.एफ-2-एस.एस-2]

S.O. 1648.—Whereas Messrs Bharat Heavy Plates and Vessels Limited, Vishakhapatnam (AP|3495) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4260 dated the 26-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of the 17-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employed been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu-

rance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/262/82-PF-II (SS-II)]

का०आ० 1649 मैसर्स दी तीरू चीरापल्ली जिला को-ओप्रेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, करूर, जिला त्रिची (टी० एन/5562) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 4261 तारीख 26-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 18-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित हैं, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्ययमत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमीयम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों, को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस– 35014/263/82–पीएफ-2 एस. एस–2]

S.O. 1649.—Whereas Messrs The Tiruchirappalli District Co-operative Spinning Mills Limited, Karur, Trichy District, (TN/5562) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4261 dated the 26-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of the 17-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/263/82-PF-II (SS-II)]

का०आ० 1650 मैसर्स टी०टी० इनवेस्टमेंटस एण्ड ट्रेडर्स प्राइवेट लि०, बालो बन रोड, तन्जौर-613005 (टी० एन०/6839) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 43 तारीख 9-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 31-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थान में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/283/82-पी.एफ-2 एस.एस-2]

New Delhi, the 7th April, 1986

S.O. 1650.—Whereas Messrs T. T. Investment and Traders Private Limited, Vallaw One Road, Tanjore-613005 (TN| 6839) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Governenment is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 43 dated the 9-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-1-1986 upto and inclusive of the 31-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submis-

sion of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provisions Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/283/82-PF-II (SS-II)]

का०आ० 1651:—मैसर्स जूपिटर रेडियो (रजि०) सी-46, ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली (डी०एल०/3424) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 4031 तारीख 8-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 3-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें,।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध

फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, या पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त रकम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/230/82 पी०एफ०-2-एस०एस०-2]

S.O. 1651.—Whereas Messrs Jupiter Radios (Regd.) C-46, Okhla Industrial Area, Phase-II New Delhi-87 (DL/3434) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4031 dated the 8-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-12-1985 upto and inclusive of the 3-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas on employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any, reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|230|82-PF-II (SS-II)]

का०आ० 1652.—मैसर्स श्री वैंकटेसा मिल लि०, उदमलपेट पो०आ०, 642128 उदमलपेट (टी०एन०/51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 320 तारीख 6-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 8-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 7-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का

संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014/400/82-पी. एफ.-2 एस.एस.-2]

S.O. 1652.—Whereas Messrs Shri Venkatesa Mills Limited, Udumalpet, P.O. 642128 Udumelpet (TN/51) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 320 dated the 6-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provision of the said Scheme for a further period of three years with effect from 8-1-1986 upto and inclusive of the 7-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any, reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/400/82-PF-II (SS-II)]

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1986

का.आ 1653 —मैसर्स दि महसाना जिला सैन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटिड, राजमहल रोड, महसाना (जी.जे./4654), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3335 तारीख 27-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 10-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों, का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/17/82-पी.एफ.-2/एम. एस-2]

New Delhi, the 8th April, 1986

S.O. 1653.—Whereas Messrs The Mahasana District Central Co-operative Bank Limited, Rajmahal Road, Mehsana-1 (GJ/4654) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3335 dated the 27-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishmnet from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-9-1985 upto and inclusive of the 17-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissoner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts,, clause (a) of sub-secion (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the account that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/17/82-PF.II(SS.II]

का.आ. 1654.—मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटिड (बंगलौर कम्पलैक्स) विमानपुरा, बंगलौर-17 (के.एन./24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4251 तारीख 26-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 18-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसा विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्म-

चारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकम के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों का जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस.-35014/29/82-पी.एफ-2 एस. एस.-2]

S.O. 1654.—Whereas Messrs Hindustan Aeronautics Limited, (Bangalore Complex) P.B. No. 1784, Vimanpura, Bangalore-17 (KN|24) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme or the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation India in the name of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 4251 dated the 26-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of the 17-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable oportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/29/82-PF. II (SS. II)]

का.आ. 1655.—मैसर्स मद्रास फोर्जिंग्स एन्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज लिमिटिड, (सी.बी. आई) कमेंदिरी, कोयम्बटूर-641104(टी.एन./5499), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3551 तारीख 23-9-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 9-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 8-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम-निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/48/82-पी.एफ-II एस.एस-II]

S.O. 1655.—Whereas Messrs Madras Forgins and Allied Industries, Kamoderi, Coimbatore-641104 (TN/5499) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exempton under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinfater referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable o such employees than the beefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3551 dated 23-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 9-10-1985 upto and inclusive of the 8-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissoner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-secion (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respec of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to effects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable Opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/48/82-PF.II(SS.II)]

का.आ. 1656.—मैसर्स सिमेन्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटीड 59, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (डी. एल/2227) ((जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उस स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना

संख्या का. आ. 3728 तारीख 11-10-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 30-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए, जिसमें 29-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, जिसे भारतीय जिवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसें स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या स्थापन के अधीन कर्मचारियों [illegible] फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/84/82—पी. एफ.-II]

S.O. 1656.—Whereas Messrs Cement Corporation of India Limited, 59, Nehru Place, New Delhi-110019 (DL/2227) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisons Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3728 dated the 11-10-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 30-10-1985 upto and inclusive of the 29-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and

provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-secion (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insuracne Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heir of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/84/82-PF.II(SS.II)]

का० आ 1657.—मैसर्स, एस. पी. आई. सी. नगर कोरा, टूरा कोटो-628005 (टो. एन/9540) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3501, तारीख 18-9-1982 में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 2-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए, जिसमें 1-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त-तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और

उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/81/82-पी एस-2 एस. एस.-2]

24 GI/86—20

S.O. 1657.—Whereas Messrs SPIC Nagar Council Tuticorin-628005 (TN/9540) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the sad Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3501 dated the 18-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 2-10-1985 upto and inclusive of the 1-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-secion (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act. is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insuracne Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Com-

missioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/86/82-PF.II(SS.II)]

का.आ. 1658.—मैसर्स इन्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड अनुपुरम पी. बी. नं.-30, कोलमलरी-683104—केरल (के. आर/35) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों की उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 907 तारीख 8-2-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 27-2-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 26-2-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, केरल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीम स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसके बारे में आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त केरल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के

जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/104/81-पी०एस० 2-एस०एस०-2]

S.O. 1658.—Whereas Messrs Indian Aluminium Company Limited, Alupuram, P.B. No. 30, Kalamasery-683104 (KR|35) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 907 dated the 8-2-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 27-2-1985 upto and inclusive of the 26-2-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala and where any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|104|81-PF. II(SS. II]

का.आ. 1659:—मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि., पिन्जोर, अम्बाला (हरियाणा) (पी. एन./34429) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा

निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1975 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2943 तारीख 4-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 21-8-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-8-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक जीवन बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/117/82-पी.एफ. 2-एस.एस.-2]

S.O. 1659.—Whereas Messrs Hindustan Machine Tools Limited, Pinjore, Ambala (Haryana) (PN|3429) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of

India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 19/6(hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2943 dated the 4-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-8-1985 upto and inclusive of the 20-8-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sums assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|117|82-PF.II(SS.II)]

का. आ. 1660.—मैसर्स, एलोडाक डिस्ट्रिब्यूटर्स, ईसानपुर अहमदाबाद-382443 (जी. जे./10832) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3051 तारीख 17-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 28-8-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 27-8-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/134/82-पी.एफ. 2-एस.एस-2]

S.O. 1660.—Whereas Messrs Alidac Distributors, Isonpur, Ahmedabad-382443 (GJ|10832) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976(hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3051 dated the 17-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 28-8-1985 upto and inclusive of the 27-8-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees

under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sums assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|134|82-PF. II(SS. U)]

का. आ. 1661:—मैसर्स टिटेनियम इक्युपमेन्ट एन्ड एनोडे मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बन्दालुर-मद्रास (टी एन/8597) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3400 तारीख 9-9-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 25-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 24-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि, यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/156/82-पी.एफ.-2 एस.एस-2]

S.O. 1661.—Whereas Messrs Titanium Equipment and Anode Manufacturing Company Limited. Vandalur, Madras-45 (TN|8597) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976(hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3400 dated the 9-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 25-9-1985 upto and inclusive of the 24-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|156|82-PF. II(SS. II)]

का. आ. 1662:—मैसर्स डी. सी. एम. इंजीनियरिंग प्रोडेक्टस, पी. बी.-5, रोपर-140001 (पंजाब) (पी. एन/5959) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा था है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4083 तारीख 13-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 3-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक, कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/245/82-पी.एफ.-2-एस०एस०-2]

S.O. 1662.—Whereas Messrs DCM Engineering Products, P.B. No. 5, Ropar—140001 Punjab (PN|5959), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exexemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4083 dated the 13-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 4-12-1985 upto and inclusive of the 3-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspecion as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsiiblity for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|245|82-PF.II(SS.II)]

का०आ० 1663:—मैसर्स श्रीराम रेमन्स, श्रीराम नगर कोटा-320004 (आर०जे०/1128) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 4070 तारीख 12-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 3-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/276/82 पी.एफ.-2-एस०एस०-2]

S.O. 1663.—Whereas Messrs Shriram Rayons, Shriram Nagar, Kota-4 (RJ/1128) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4070 dated the 12-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-12-1985 upto and inclusive of the 3-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance

Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employed been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/276/82-PF-II (SS-II)]

का.आ. 1664—मैसर्स पांडियान रोडवेज कार्पोरेशन लिमिटेड, मदुराई (टी०एन०/6882) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 4064 तारीख 11-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 3-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षक प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या इस भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(278)/82-पी.एफ-2-एस एस-2]

S.O. 1664.—Whereas Messrs Pandian Roadways Corporation Limited, Madurai (TN/6882) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Governenment is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4064 dated the 11-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-12-1985 upto and inclusive of the 3-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme; the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but, for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in

any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/278/82-PF-II (SS-II)]

का०आ० 1665—मैसर्स फैसिट एशिया लिमिटेड, पैरन-गुड्डी, मद्रास-600096 (टी०एन०/4805) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 44 तारीख 9-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 31-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में

हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/282/82-पी. एफ 2-एस.एस-2]

S.O. 1665.—Whereas Messrs Facit Asia Limited, Perungudi, Madras-600096 (TN/4805) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 44 dated the 9-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-1-1986 upto and inclusive of the 31-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/282/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1666.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स मैटिरियल प्रोटैक्शन एजैन्सी, रूम नं. 3, कोयप्पा बिल्डिंग, पो. नलयालम कालिकट नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019 (151)/86-एस.एस.-2]

S.O. 1666.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Material Protection Agency, Room No. 3, Koyappa Building, P.O. Nallalam, Calicut have agreed that the Provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(151)/86-SS-II]

का. आ. 1667.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कोन्टीनेन्टल ग्राटो एन. सी. लेरी लिमिटिड यूनिट ग्राईश्वर प्रोशीयन मशीन्स प्लाट नं. 75 सेक्टर 6, फरीदाबाद 121006, हरियाणा और इसका 16 आसफ अली रोड, नई दिल्ली, 110002 स्थित रजि. कार्यालयक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019 (149)/86-एस. एस.-2]

S.O. 1667.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Continental Auto Ancillary Limited, Unit-Eicher Precision Machines, Plot No. 75, Sector 6, Faridabad-121006, Haryana including its Regd. Office at 16 Asaf Ali Road, New Delhi-110002 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(149)/86-SS-II]

का. आ. 1668.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि फलोवैल प्लाम्बिंग एण्ड फिक्चर कम्पनी, ओल्ड नजफगढ़ रोड, गुड़गांव और इसकी जवाहर नगर दिल्ली-110007, स्थित शाखा । नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019 (148)/86-एस. एस-2]

S.O. 1668.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s Flowell Plumbing and Fixture Company, Old Najafgarh Road, Gurgaon, including its branch at Jawahar Nagar, Delhi-110007 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(148)/86-SS-II]

का. आ. 1669.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लैम्पस एण्ड लाइटिंग लिमिटिड उपत्सया इंडस्ट्रीयल एरिया, अलवर (राजस्थान) और इसका 1101, नई दिल्ली हाऊस 26, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019 (147)/86-एस. एस.-2]

S.O. 1669.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Lamps and Lighting Limited, 3, Matsya Industrial Area, Alwar (Raj.) including its Head Office at 1101, New Delhi House-27, Barakhamba Road, New Delhi, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(147)/86-SS-II]

का. आ. 1670.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रेश्मि टूरिस्ट होम, हिल पैलेस रोड, चाथारी, तिरूपुनीथुरा-682301, नदमा गांव, कन्यानूर ताल्लुक, अरनकुल्लाम कस्बा केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019 (150)/86- एस. एस.-2]

ए. के० भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 1670.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Reshmi Tourist Home, Hill Palace Road, Chathari, Tripunithura-682301, Nadama Village, Kanayannur Taluk, Ernakulam Distt. Kerala have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(150)/86-SS-II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1986

का. आ. 1671.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सलाल हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ को पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24 मार्च, 1986 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल 42012/57/83-डी-2(बी)]

New Delhi, the 4th April, 1986

S.O. 1671.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Salal Hydro Electric Project and their workmen which was received by the Central Government on the 24th March, 1986.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D. 27 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of Salal Hydro Electric Project

AND

Their Workman : Shingara Singh

APPEARANCES :

For the Employers : Shri J. N. Kochhar

For the Workman : Shri R. K. Singh

INDUSTRY : Hydro Electric Project STATE : J & K

AWARD

Dated the 19th of March, 1986

The Central Government, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, hereinafter referred to as the Act per their Order No. L-42012(57)|83-D.II(B), dated the 12th of July, 1984 referred the following dispute to this Tribunal for adiudication :—

"Whether the termination of employment of Shri Shingara Singh, Foreman by the Management of Salal Hydro Electric Project with effect from 27-5-83 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. The petitioner-workman Shingara Singh joined services at the Respdt. Salal Hydro Project as a Foreman Special on 10-7-1978 and worked there as such till 16-11-1981 when he proceeded on 15 days medical leave. According to the petitioner his illness got prolonged and therefore he sought extension of leave by sending periodical requests to the management but for the reasons better known to them, they did not respond to his correspondence. However, after recovery he reported for duty on 27-5-1983 and produced all the relevant medical certificates regarding his illness as well as subsequent Fitness but they did not re-act favourably and ultimately dispensed with his services under the impunged order dated 29-10-1983 even though the concerned Asstt. Engineer had recommended regularisation of his services on condoning the absence in view of their own requirements besides his satisfactory work and conduct. The petitioner thus complained that the management acted illegally in terminating his services without complying with the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act 1947 as neither any prior notice nor terminal benefits were given to him and that otherwise also they had no justification for disengaging him when some of his juniors were still working on the Project.

3. Contesting the petitioner's story, the management accused him of voluntarily abandining the job without intimating his intentions at any stage. It was averred that even though the petitioner had proceeded on sanctioned leave up to 30-11-1981 yet he never sought any extension and so much so that he did not even apprise them of his whereabouts till one fine morning when after a lapse of almost 1-1/2 year he appeared before them on 31-5-1983 seeking condonation of absence and regularisation of his services on the ground that during the meanwhile he had fallen sick. Elaborating their version the management submitted that on 2-7-1982 a memorandum, calling upon the petitioner to resume duty within 15 days, was sent on his home address under a registered cover but received back undelivered with the endorsement of the postal authorities that he had left his home without leaving behind any trace; thus forced by the circumstances they had no option but to dispense with his services under Model Standing Order No. 6(iii) applicable to the Project for doing away with the services of such employees who abstain themself for more than 10 days witout any prior intimation or permission.

4. The controversy between the parties could not be amicably settled despite the intervention of the A.L.C.(C) at the Conciliation stage and hence the reference.

5. In support of his case the petitioner examined himself whereas the management produced their Personnal Manager Shri J. N. Kochhar and one Gulshan Chaudhary, Liason Officer of M|s. Som Dutt Builders New Delhi; of course, both the parties filed a number of documents also whose authenticity was not disputed from either side.

6. On a careful scrutiny of the entire available data and hearing the parties I am inclined to sustain the Management's view point that the petitioner had voluntarily abandoned the job in search of green pastures. The pertinent point is that on his own showing he did not attend the Project after 15-11-1981 and even though his absence up to 30-11-1981 was on account of sanctioned medical leave yet no further Medical certificate was submitted by him during the period of this absence. Under the weight of oath, in his cross-examination, the petitioner admitted that he did not inform his employer about his Ludhiana address despite his assertion that during this period he was living there; of course he claimed having produced all the medical certificates in a bunch at the time of reporting for duty after recovery from sickness; but by necessary implication he conceded that at no stage of his absence, he had ever submitted any medical certificate to the management on the basis of which they could assum that he was realy down with some or the other disease, or that he was living away from his home where they could contact him.

7. Against such back drop their version projected in the evidence of Shri J. N. Kochhar that the registered memo dated 2-7-1982 calling upon the petitioner to resume duty within 15 days was returned by the Postal authorities undelivered from his home address with the remarks that the whereabouts of the addressee were not known gains credibility for the obvious reason.

8. The next chain of evidence is available in the deposition of Gulshan Chaudhary of M|s Som Dutt Builders who produced the documents Ex. M2 to M7 to show that as a matter of fact during all this while the petitioner was working abroad under them in Baghdad (Iraq). It was in response to the management's query Ex. M2 dated 8-5-1983 that they confirmed the proposition of his having left India on 22-11-1981 for Iraq with passport No. L-777449 on recruitment as a Mechanic Foreman. Letter Ex. M4/A dated 13-11-1981 shows that the petitioner was in clandestine correspondence with M|s. Som Dutt Builders for taking up a foreign assignment under them. Similarly from the documents Ex. M4, M5, M6 and M7 there remains no manner of doubt about the petitioner's recruitment by M|s. Som Dutt Builders and ultimate sojourn to Iraq. And it goes without saying that at no stage he cared to inform his existing employer i.e. Respdt. Project about his venture.

9. On behalf of the petitioner it was argued that the person Shingara Singh sent by M|s. Som Dutt Builders to Iraq

could be some other worker carrying the same name. But the submission is completely devoid of force because from the documents Exa M4|A; Ex. M6 and M7 it is abundantly clear that it was the same very Shingara Singh who is the petitioner in these proceedings before the Tribunal with whom M|s. Som Dutt Builders were dealing. It is besides the point that the documents Ex. M2 and M3 have a significance of their own in removing all the element of doubt regarding the identity of the petitioner Shingara Singh as the person who had actually taken the foreign assignment under M/s. Som Dutt Builders and proceeded to Iraq during the relevant period i.e. when the remained absent from the Salal Project.

10. I, therefore, find no impropriety in the Management's action in refusing to condone his absence from duty; and then terminating his services under Rule 6(iii) of the Model Standing Orders on the assumption of his having voluntarily abandoned the job regardless of their own requirements and his past conduct or credentials.

11. However, in so far as the terminal benefits are concerned I think the same should have been paid to the petitioner even though he had abandoned the job on his own notion after 30-11-1981 as meanwhile he had proceeded on the foreign assignment as mentioned hereinbefore. The primary consideration is that by then the petitioner had put in more than 240 days of continuous, service within the preceding 12 calendar months and by the time of passing of the formal orders of disengagement he had returned to India. I, therefore, direct the Management to accord him all the terminal benefits with in the next two months on the assumption that he had served them from 10-7-78 upto 30-11-81.

12. Award returned accordingly.

CHANDIGARH,
19-3-1986

I. P. VASISHTH, Presiding Officer
[No. L-42012|57|83-D.II(B)]
HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1986

का. आ. 1672:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर (यू. पी.) के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-3-86 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42011/6/82-एफ. सी. आई. डी. -IV (ए)]

New Delhi, the 9th April, 1986

S.O. 1672.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur (U.P.) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Lucknow, and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th March, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT KANPUR

PRESENTS :

Shri Shakeel representative—for Workman.

Shri R. R. Mansingh representative—for Management.

Industrial Dispute No. 5 of 1983

Reference No : L-42011(6)|82-FCI-DIV(A) dt. 17-9-82.
In the matter of dispute

BETWEEN

The President Bhartiya Khadya Mazdoor Sangh, 1 Abdul Aziz Road, Lucknow.

AND

The Senior Regional Manager Food Corporation of India 6|7 Haibibullah Estate, Lucknow.

AWARD

1. The Central Government Ministry of Labour, vide its notification no. L-42011(6)|82-FCI-D. IV(A) dt. 17th September, 1982, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal;

> Whether the action of the senior Regional Manager, Food Corporation of India, Lucknow in nor regularising the services of 54 workmen whose names are mentioned in the annexure, and not bringing them on regular scale of pay is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?

2. It is common ground that the 54 workmen mentioned in the reference orders annexure are working at the management the establishment of dal mill is a permanent Mill of working since 1976 atleast. According to the claim statement the establishment of dal mill is a permanent Mill of the management and the work of the establishment is also permanent in nature and the workman working without any break in service. All these workers are directly paid their wages by the management and the management has also paid them bonus in the past years. It is further averred that besides the workmen about 203 more workers are working in the said Dal Mill and have been declared regular after completion of 240 days of work w.e.f. 15th June, 1973, that the workmen in question here have all completed 240 days of continuous service in a calender year. That under the FCI Staff rules and regulation 1971 wherein it is laid down that no person will be employed on temporary basis after more than a years service in the corporation, that regularising service of other workmen from 15-6-73 and refusing the 54 workmen the same benefits and pay scales at the same place of work is discriminatory and in the end it is prayed that the workmen be declared regular and be allowed benefits of regular scale of pay and DA etc.

3. The management has contested the case of the applicants on the ground that the workmen are all daily rated casual workers and that the nature of the work at Dal Mill is that it is not warranted to be run continuously nor its working renders it possible to make services of its workers permanent and that those casual rated workers can not be equivated with departmental workers and that the processing plant of Dal Mill cannot be equivated with the depot handling food grains as the function in the later case are regular functions and that the working in Dal Mill does not make these casual workers a permanent workmen having regular status. It is also averred that the work in the Dal Mill is not of a continuous nature and is permanent on several factors. According to the management this Dal Mill workers are functioning within the frame work of factories Act workers and Dal Mill workers are being paid their legal wages under UP Minimum Wages Act. It is further averred that these 54 workmen are being paid weekly holiday wages, wages for national holiday etc. and that there is no question of overtime as their services are not utilised beyond working hours. It is consequently prayed that the claim be dismissed.

4. In the rejoinder it is averred on behalf of the workmen that in their identification card management has defined them only as daily rated worker and not as casual labour and that afteer completion of 240 days of work in a calender year they are entitled to get all benefits of regular employees. This being not given to them is discrimination on the part of the management.

5. In support of its contention a number of documents have been filed on behalf of the workmen. Annexure I dt. 6-7-84, is letter of the District Manager to the Asstt. Manager FSD Talkatora asking him to release payment of lay off to all eligible daily workers as per law who have put in 240 days service or more at the time they were laid off upto maximum of 45 days in a year counting from the day when the workman were first laid off. Annexure II leave record of workman Asharfii Lal showing that in the year 1979 he had put in 261 days of work and was paid for 21 days for lay off making the total 288 and

that he had asked 14 days leave, in year 1980 he had worked for 240 days and was laid off total 283 days and in all he earned 14 days leave raising the total due to 28 days. Similarly Annexure III is to leave account of Ram Autar II who had put in including the days of laid off 284 days work in 1979 and 289 days work in 80 raising his leave to 29 days and that in the year 1981 (March) he had put in 73 days of work. They have further filed wage slip IV A to IV-D of A Shri Ashrfi Lal, Sudhir Kumar, Santram and Man Bahadur, all of whom worked for full month in July 84 and paid basic pay Rs. 240-25 besides DA EF CPF were given to them and ESI EPF CPF and ESI were deducted from their total emoluments.

6. The workmen have further filed photo copies of their identification card annexure SI to SIII showing that Sudhir Kumar and Hanuman are working in Dal Mill Talkatora. It may be mentioned that Ram Autar II and Hanuman are not mentioned in the annexure of the reference order. The photo copy of the agreement annexure 6 between the management and Shri M. Shakeel President of the Worker's Union of Dal Mill whereby the management agreed to give compensation for lay off as well as annual leave with wages w.e.f. 1-1-79 and that lay off to be paid for actually laid off period subject to the maximum of 20 days in calender year. Annexure 8 is the letter dt. 5-7-84 of the Joint Manager addressed District Manager Food Corporation of India, Lucknow, wherein he intimated it has now have been decided to pay to pay laid off compensation to all eligible workers as per law who put in 240 or more in service at the time they were laid off i.e. upto the maximum of 45 days in a year counting from the date when the workmen were first laid off. Annexure 7-A to 7-D is the original wage slip for July 83 of workman Santram, Guru Prasad, Omkar Nath and M. B. Wasi, showing that they all worked for full 31 days and besides basic pay at the rate of Rs. 240 were paid, Annexure IX is the wage slip of Mewalal Sharafatullah, R. K. Dubey for the month of August, 1980. Annexure 10 and 11 are the office order labour Ram Sagar Savita and Hari and none of them were mentioned as workmen in the reference order, out of the workmen Uma Shanker Sudhir Kumar have filed their affidavit that they have worked for more than 240 days were same persons namely Bari Prasad Mohd. Wasi and Ram Sagar have filed their affidavit but their names does not appear in the reference order.

7. The management got its written statement amended by adding paragraph 14 A and took the plea that out of 54 workers mentioned in Annexure I it has been contended that S|Shri Raghai Saran (Sl. No. 30), Mohishwar (Sl. No. 33), Rajendra Prasad (Sl. No. 35) Pesh Raj (Sl. No. 37), Munauna (Sl. No. 42), Mohi Lal (Sl. No. 46) and Vinod Kumar (Sl. No. 50) were neither engaged by corporation in any capacity during the relevant period commencing from 76 and that Arun Kumar Singh (1) worked as daily rated worker for one year in 1976. The names of Shri Ram Sajeewan, Sant Ram, Pyare Lal, Vijai Kumar I and Rameshwar have been mentioned twice in the reference order.

8. The workman have further filed the pay slips of Kalloo annexure 13 whose name does not appear in the reference order, photo copy of the leave record of Rameshwar II showing that in the year 1979 including lay off he worked for 288 days, and in the year 1980 he worked for 248 days and lastly in 81 he worked for more than 240 days. Annexure 14B is the leave record of Shri R. P. Dwevedi showing that he worked for 285 days in 79, 289 days in 80 and about 240 days in 1981. Annexure 14 C is leave record of Sant Ram showing that in 79 he worked for 269 days in 80, 103 days and about 240 days in 81, Annexure 14D is recorded of one Melu Lal who too worked for more than 240 days in 79, similarly 1980 about 80 days in 81 233 days but his name does not appear in the reference order. Similarly leave record of Moneshwar have been filed who has worked almost in similar way since 1979 but his name does not appear in the reference order, and lastly annexure 14K is leave record of Radhey Shyam whose name also does not appear in the reference order though he worked since 1979. Annexure 16 is settlement for payment of wages with leave. Muneshwar and Radhey Shyam have filed their affidavit testifying that they are working in Dal Mill since 1976. but their names does not appeared in the reference order beside Sant Ram has filed his affidavit that he is working Dal Mill since 1979 and he had completed 240 days alongwith other workman and that they were all getting only leave bonus D. A. lay off compensation weekly holidays and CPF etc.

9. Workman has further filed annexure 18 showing that bonus was paid to the workmen of FCI Talkatora Dall Mill Lucknow. In this letter it was specifically mentioned by the General Manager to the Asstt. Labour Commissioner that he head office had issued instruction for payment of exgratia bonus at the rate of 8.33 per cent to the casual employee of the corporation for the year 1977-78, annexure 19 agreement showing that the management entered into agreement with the president of Dal Mill Workers Union regarding payment of bonus to casual workers and other workers of Dal Mills.

10. On the other hand the management have filed two document alongwith annexure and also alongwith the affidavit of Shri D. C. Gupta the District Manager of the management Corporation at Lucknow. He has filed the attendance cum pay sheet of the workers of Dall Mills for the month of July 80 which relates 75 workers, they were paid their wages on daily rate wages for the number of days worked by them, he has further filed the copy of bill regarding payments made to the respective 72 workers for the month end year 1981, showing that besides wages at the daily rate they were also paid DA at the rate of 60.90 per month. He stated in his statement that the functioning of the dall mill depends upon the availability of raw materials and it has it lean parts when most of the casual workers are not given any work. He however admits that since 1985 on account of stability of stocks the casual workers are being provided work daily. In cross examination Shri A. C. Gupta District Manager of the management corporation has admitted that all those workman whose photo copies of attendance register he has filed for the month of January 80 working in Dal Mill in 1978 also and that CPF deduction is made from them. He further admits that out of the 54 workmen only some one were distributed lay off compensation, he expressed his ignorance as to whether only leave with wages are given to the workmen or not and further admitted that we are giving weekly holidays to the workmen.

11. The workman had summoned some of the documents mentioned in the application from the management which they never produced ultimately Shri M. Shakeel filed his own affidavit testifying that he admitted the signatures of persons mentioned in the affidavit which names and signatures corroborated to the documents of agreement and orders copies of which he had filed.

12. On behalf of the workman three witnesses out of them several had given their affidavit appeared in the witness box one of them is Shri Santram WW-1. He has deposed in cross examination that he and one Badri Prasad worked for operating the machine beside it his work is to spread dal, get it dried and filling in bags and that both of them fifet bags also. He states that in the reference order Moheshwar wrongly written to Moneshwar and who is working in the Dal Mill. and that Rajendra Prasad Trivedi is also working there. If it was a fact and in view of the averments of the management that he never appeared after 1976 the union has filed the photo copy of his leave account annexure 14B which shows that he worked for 285 days in 79, 289 days in 80 and about 240 days in 80 and about 240 days in 1981. He has also stated that Pesh Raj is wrongly written in reference order for Desh Raj. He has however admitted that there is no Munauna or Munna or Vinod Kumar in the Dal Mill. He states that he is working in the Dal Mill since 1977 and that he is paid Rs. 240 as basic plus DA total Rs. 300 for the month. He has denied that his monthly payment is made to him after calculating daily wages. He however admits that the pay for the day or absence is deducted.

13. The other workman is Ram Sagar who gave affidavit and has been examined but his name does not appear in the reference order, he too deposes that he is working in the Dal Mill since 1977, but is not in the category of loader. He also gets the payment for the days he works besides holidays and Sundays and for sanctioned leave. He further states that Dal Mill is mill which works for the entire year dependent upon the availability of Dal. He denied management's suggestion that the mill is working on seasonal basis depending upon the availability of the Dal.

14. Mr. Shakeel was cross examineed. He stated that in his affidavit he has wrongly written A. K. Tewari instead of L. K. Tewari who was Dyputy Manager in the management. On the date of cross examination he filed some original documents two of which are identity card of workman Sudhir Kumar and Sant Ram showing that they are daily workers of Dal Mill and their original record regarding leave of Sant Ram, Sudhir Kumar, Radhey Shyam Muneshwar, Muneshwar as observed earlier is not mentioned in the reference order, though according to Sant Ram and document filed it appears that he is working since 79 and put in relevant years more than 240 days of work. Similarly Radhey Shyam's name is not in the reference order and it is alleged that his name has wrongly written as Raghai Saran.

15. On the point if Dal Mill is seasonal i.e. running only in some part of the year in some particular season and remain closed for the rest of the year, there is no evidence as to during which part of the season or year the mill was operative and for which part of the year it remains closed. It has come in evidence that its operation is dependent upon availability of Dal. Management witness has however, admitted that since 1981, the position has eased. Dal is a commodity which could be made available throughout the year depending on factors of storage, transportation etc. The availability can not be ruled out that for some time when the Dall is not available for operation of the mill and it is probably on that account that lay off compensation for 20 days and then for 45 days in a year has been allowed as per documents filed on record. In these circumstances it can not be called seasonal.

16. Under section 25-A of the I.D. Act industrial establishments which are seasonal in character have been exempted from the application of section 25-C of the act relating to lay off and retrenchment. The very fact that the lay off has been given shows that the Dal Mill is not a seasonal industry but an industry running for the whole year though remaining closed at times for non-availability of working materials for which lay off compensation has been provided by the management.

17. Now the question arises if the workman working in the Dal Mill are all casual workmen. Dictionary meaning of word Casual is happening by chance and a casual labour is not labour permanently and regularly engaged by an employer. Casual work for labour would be work which is not a recurring work but has come as a matter of chance or being a periodic work occurring in all year or so. So along Dal Mill runs and labourers required the work of the mill as well as all the labourer is of regular nature. If the work is of regular nature they are entitled to daily wages, weekly rest, medical leave, provident fund and bonus etc. If such a workman have put in continuous service for about a year they are entitled to certain rights for instance that if they have completed 240 days of work in a year or come within the definition of continuous service as given in section 25-B (1) of the Industrial Dispute Act they are entitled to retrenchment compensation on termination and acquire a temporary status and can not be called to be merely casual workman. They will be further entitled to termination on the basis of last come first go and re-employment when need arises in view of provision 25 G and 25 H of the I.D. Act. These are the benefits granted to a workman in an industry under industrial dispute act and which they acquired after having worked regularly under some employment and acquiring the category of temporary workman as against casual who are engaged for non recurring type of work for a short duration. All these workmen though called casual workmen acquired temporary status as their working was a continuing nature and not occurring by chance. Under item 10 schedule 5 recently added to the I.D. Act to employ workman as badli or casual or as temporary for years with the object of depriving them a status of permanent workman is an unfair labour practice. In view of the admission of the management witness that all those workmen passing few whose working in the Mill he has disputed which working in the Dall Mill since 1978. The documents filed and leave account of the some of the workmen show that they are working for more than 240 days in a year. Thus they all acquired temporary status long ago in 1979, 80 or at least in 1981.

18. Thus in view of these circumstances that they are working since long and the work is of a continuing type it had been unfair labour practice on the management not to have made them regular and started giving them regular pay of scale when they are admittedly paying them DA, bonus EPF, Leave lay off etc. action to regular employment. Out of those 54 workmen mentioned in the annexure of the reference order, the management has admitted that only 49 of them working, that as the five names namely Sant Ram, Pyare Lal, Vijai Kumar, Rameshwar II and Ramesajeewan are mentioned twice in the list. Deleting their names there remains 49, workmen. Their names appears at Sl. 22, 34, 36, 45 and 11 and again at serial Nos. 54, 51, 53, 52, and 48 respectively which names are called by the workman as wrongly written in the reference order. They are Desh Raj, Radhey Shyam Muneshwar and Melu Lal have been incorrectly described as Pesh Raj Raghai Saran, Mahishar and Mahi Lal at 21. The union should have got reference order amended suitably, in the absence of the same no relief can be given to those persons Munna or Munauna and Vinod Kumar which admittedly not working in the Dal Mill as admitted by Sant Ram. There is no evidence about Devi Lal and Mohilal though regarding Rajendra Pratap Trivedi the leave card shows that he is working in the Dal Mill and was there in the year 1981. The managements own paper shows that Shri Rajendra Prasad Trivedi was in service in the year 1980 and received payment. Thus disallowing to any right to Pesh Raj, Raghai Saran, Mohishar Munna, Devi Lal, Mohilal Mahi Lal and Vinood Kumar there remains 41 persons. In annexure to the reference order serial No. 41 is left blank. Thus the number of workmen who can be given relief comes to only 40.

19. Consequently I hold that the action of the Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Lucknow, in not regularising the services of 40 workmen instead of 54 workmen whose names at mentioned in the annexure and not bringing them on regular scale of pay is not justified and their services will be regularised forthwith.

I, therefore, give my award accordingly.

Let six copies of this award be sent to the Govt. for its publication.

Dt. 18-3-86.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-42011/6/82-FCI/D-IV(A)[D. II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

Sl. No.	Name of the workmen
1.	Shri Arun Kumar Singh
2.	Shir Krishna Kumar
3.	Shri Surendra Singh
4.	Shri Tika Bahadur
5.	Shri Raja Ram
6.	Shrimati Monoo
7.	Shri Guru Prasad
8.	Shri Shiv Narain
9.	Shri Man Bahadur
10.	Shri Sri Ram
11.	Shri Ram Aujar I
12.	Shri Budhoo
13.	Shri Ganga Mal
14.	Shri Sri Kishan
15.	Shri Sudhir Kumar
16.	Shri Nohar
17.	Shri Mohan

1	2
18.	Shri Ram Shai
19.	Shri Rameshwar
20.	Shri Chotai Lal
21.	Shri Debi Deen
22.	Shri Putti Lal
23.	Shri Ganga Ram
24.	Shri Asharfi Lal
25.	Shri Rakesh Chand Saxena
26.	Shri Bansi Lal
27.	Shri Uma Shanker
28.	Shri Bharat
29.	Shri Rajendra Pratap Trivedi
30.	Shri Bhagoti Prasad
31.	Shri Vijay Kumar II
32.	Shri Sunder Lal
33.	Shri Ram Dulari
34.	Shri Rameshwar II
35.	Shri Omkar Nath
36.	Shri Ram Sajiwan
37.	Shri Dwarika Prasad
38.	Shri Pyarelal
39.	Shri Vijay Kumar I
40.	Shri Sant Ram

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1986

का. आ. 1673 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, कानपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उसके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-3-86 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 7th April, 1986

S.O. 1673.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Kanpur and their workment, which was received by the Central Government on the 24th March, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 246A/1985

Reference No. L-12012/248/84-D.II(A) dated 20-5-1985

In the matter of dispute between:

Shri Rajendra Kumar C/o Shri N. C. Pande Authorised representative of the workman, C-323, Guruteg Bahadur Nagar, Kareli, Allahabad.

AND

The Regional Manager, Region III, State Bank of India, The Mall, Kanpur.

APPEARANCES :

Shri A. S. Saxena representative—for the Management.

Shri Mangalevdkar representative—for the workman.

AWARD

1. The Central Govt. Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/248/84-D.II(A) dated 20th May, 1985, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal;

Whether the action of the Management of State Bank of India, in terminating the services of Shri Rajendra Kumar messenger, State Bank of India, Muthiganj Branch, Allahabad with effect from 30-8-82 and not considering him for further employment while engaging fresh hands is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

2. The case of the applicant is that he was appointed as temporary messenger in the management bank in Moti Lal Nehru Regional Engineering College Branch, Allahabad, on 10-2-81 and worked there till 31-5-81, when his services were dispensed with. That thereafter he was again apopinted at managements Johnsonganj branch on 30-10-81 and worked till 20-2-82 and last of all he was appointed at Managements Muthiganj branch on 1-6-82 and worked there upto 30-8-82 with a artificial break of one day on 2-8-82, that for all these apointments he was never given any appointment letter nor any termination letter and thus the provision of para 495 and 522 of the Sastri Award were violated. He was further not given any notice or given notice pay at the time of termination of his services. That after his termination several other persons were appointed at the above said branches, their names being Raj Kumar Agrawal, A. K. Mishra at M. L. Nehru Engineering College Branch Ashok and Mahatma Mishra at Johnsonganj branch and Santosh Mishra at Muthiganj Branch. That though there was work but he was never given a chance nor called for work and in this way provisions of section 25F G and rule 77 and 78 of the Central Rules of ID Act were violated. That the appointment of workman for a particular period of number of days was deliberate with a view that the applicant may not take advantage of para 20.7 or 20.8 of the bipartite settlement, and that despite representations by the workman he was always told that as he has completed 89/90 days of service hence he would not be given further chance in view of the circular of the management resorting period of temporary apopintments.

3. The management has contested the case on a preliminary point that the reference was invalid as no demand was made. On merit it was contested on the ground that it is admitted that the workman was engaged as temporary messenger by way of fresh appointment at management's Muthiganj, Branch Allahabad, on 1-6-82 and continued to work there upto 30-8-82, when his services were terminated as no longer required and in this way the workman worked for a total period of 89 days. The management admits indirectly that no apopointment or termination letter was given to the workman as he never demanded the same. It is admitted that the workman was appointed at management's MLN Regional Engineering College branch, but that appointment can not be legally be clubbed together with the appointment at Muthiganj Branch. Similarly it is alleged that the workman was apopinted at Johnsonganj branch and that being fresh appointment has no relevancy with the appoitment at Muthiganj branch and can not be clubbed together for purpose of section 25-B of the I.D. Act. The management further admits non employment of the workman on 2-8-82 but it is averred that his services had automatically came to end on cessation of requirement of work and on expiry of the period of appointment known to the workman. The management has further admitted that few workmen were appointed as temporary hands against purely temporary and odhoc requirement prior to the appointment of workman which were not the same on which the workman was appointed and their services were terminated as and when bank's requirement were over and it has been denied that provision of 25G and H attracted in the instant case or provision of bipartite settlement have been violated.

4. On behalf of the management Shri A. K. Chatterjee has given his affidavit evidence and has reiterated the averments made in the written statement admitting that the workman worked at Muthiganj Branch of the management bank for 89 days. In cross examination he has admited that branch manager is the authority to appoint a sub staff in permanent capacity but appointment had to be done through interview etc. through personnel department. Information of selection of sub staff is made by branch manager who later does it only after informing the regional manager as it is the Regional Manager who is controlling authority. He however, stated in the end that prior approval has to be taken by the branch manager from the Regional Manager who

was the controlling authority in case of sub staff, in the end he stated that no attendance register is maintained in the case of temporary sub staff.

5. The workman has filed circular per list dt. 8-11-85, all of which have been admitted by witness Shri A. K. Chatterjee. They are in five documents. The first document is circular staff no. 168 dated 9th September, 1976 regarding temporary employees wherein it is laid down that while in the sub staff cadre temporary appointment can not be avoided on some places following guidelines must be observed while resorting such temporary appointments. That such appointment should be made subject to the condition that no such employee should be permitted to for a aggregate period exceeding 90 days in a year.

6. A similar circular was issued as circular staff no. 205 of 1978 dt. 30-11-78 which lays down that it is impressed upon the management (branch managers) once again that they should ensure personally that temporary employees are appointed in the prescribed manner only and for maximum period not exceeding 90 days and certificate was to be sent to the personnel department, that no temporary apopintments including casual labours were made and in case casual employee or temporary employee was permitted to exceed a total of 90 days except with the prior approval of the controlling authority. The witness further admitted in the written statemnet filed before the Assistant Labour Commissioner (Central) Kanpur in dispute raised by the workman where it was admitted that the workman worked at MLN Engineering College branch for 89 days in the year 1981 and at Muthiganj branch for 89 days and at Johnsonganj branch for 90 days. Another circular staff no. 129 of 83 dated 24-11-83 was also filed wherein it was again emphasised that temporary employees are still being allowed to work in excess of the prescribed limit of 90 days and lastly circular no. 23 of 1985 dated 17-1-1985, has been filed wherein it was emphasised that temporary appointments are to be resorted strictly in the guideline issued and for maximum period of 90 days with the approval of the controlling authority.

7. The workman has filed his affidavit evidence giving details that after his termination Raj Kumar Agrawal, and A. K. Mishra were appointed at MLN Engineering College Branch, Shri Ashok Kumar and Mahatma Mishra were appointed at Jonsonganj branch and lastly Shri Santosh Kumar Chadha was appointed at Muthiganj Branch of the management. In cross examination he has denied the managements suggestion that he was told the period for which he was apopinted or he was being employed rather he states that he demanded the letter of appointment which the management never gave him.

8. The preliminary objection raised by the management that no demand was made is repelled on the ground that the dispute was raised before the A.L.C. which itself communicated to a demand and if the management wanted to reconcile the matter then and there it has ample opportunity for the same.

9. It is admited case that neither appointment letter nor termination letter was issued to the workman, thus it can not be said that whether his appointment was for a fixed duration and whether temporary or in any other capacity. Even casual workman employed in the banking industry to perform the work of messenger will be deemed to be temporary workman and will be covered by definition of para 20.7 of bipartite settlement or 508 of the Sastri Award. I have just quoted above that the managements' all circular emphasises that in no circumstances a temporary employee should be continued beyond 90 days unless there is prior approval of the controlling authority. It is probably on this account that the workman was allowed to work in the temporary capacity MLN Engineering College Branch for 89 days, Muthiganj branch for 89 days and Jonsonganj branch for 90 days. In para 493 of the Sastri Award it is laid down that the mangement should maintained a register of all temporary employees also showing names of retrenched employees and in view of para 495 of the said award they should be given appointment letter specifying the kind of appointment and other details.

10. On the point of principles of last come first go it is laid down in paragraph 507 of the Sastri Award that in deciding that who is junior most amongst superflous A and B class bank should take down as unit while C and D class bank should take state. Admittedly State Bank is A class bank and MLN engineering College branch of the management as well Muthiganj and Jonsonganj branch of stationed at Allahabad would be taken as one unit for the purposes of deciding who is the junior most. It is laid down that retrenchment of a superflous workman should be on principles of last come first go.

11. Lastly as required under para 522(5) of the Sastri Award no termination letter or appointment letter was given to the workman and under sub rule (4) of the said para of Sastri Award no notice or notice pay was given to the workman for termination for any of the three temporary spells. Thus in view of the infringment of the mandatory provisions of the Sastri Award and bipartite settlement the termination of the workman would be illegal.

12. It is not disputed that temporary hands were appointed/recruitted in these branches after the termination of the workman, this is nothing but violation of the provisions of these rules 77 and 78 of the I.D. rules Central and section 25H of the I.D. Act.

13. In view of the discussions made above, I hold that the action of the management of State Bank of India, in terminating the services of Shri Rajendra Kumar, messenger, State Bank of India, Muthiganj Branch, Allahabad w.e.f. 30-8-82 and not considering him for further employment while engaging fresh hands is not justified, the result is that the workman has to be reinstated in service with full back wages.

14. I, therefore, give my award accordingly.

15. Let six copies of this award be sent to the Government for its publication.

Dated 20-3-1986.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012/248/84-D.II(A)]

का. आ. 1674 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, कानपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-3-86 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 1674.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Kanpur and their workmen, which was received by the Central Government on 25th March, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

REFERENCE No. L-12012/167/79-D.II(A) dt. 2-7-84,

L-12012/52/83-D.II(A) dt. 2-5-84

Industrial Disputs Nos. 57/1984 & 235/1983

In the matter of dispute between :

Shri Hori Lal & others (ID No. 57/1984) C/o General Secretary U.P. Bank Employees Union (Federation) 26/104 Birhana Road, Kanpur.

Shri Swarup Narain Pande C/o U.P. Bank Employees' Federation 26|104, Birhana Road, Kanpur.

AND

The Management of State Bank of India, through the Chief Manager, State Bank of India, Mahatma Gandhi Road, Kanpur.

APPEARANCE :

Shri V. N. Sekhari—for the workmen.

Shri A. S. Saxena—for the Management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-12012/167/79-D.II(A) dated 2-7-84, (I.D. No. 57/1984), has referred the following dispute for adjudication to this tribunal:

> Whether the action of the management of State Bank of India, Kanpur in terminating the services of S/Shri Hori Lal, Sunder Lal, Hari Shanker and Braham Prakash with effect from 30-8-78, 17-11-78, 16-8-78 and 16-11-78 respectively was justified in view of the provisions of section 25F, G and H of the Industrial Disputes Act, 1947? If not, to what relief each of them is entitled?

2. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-12012/52/83-S.II(A), dt. 2-5-84 in I.D. No. 235/83 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal;

> Whether the action of the management of State Bank of India, in relation to their main branch, Kanpur, in terminating the services of Shri Swarup Narain Pande, casual labour with effect from 16-8-78 is justified? If not to what relief is the concerned workman entitled?

3. The two cases were consolidated vide order in industrial dispute no. 57/84, as common question of law and facts arise in them and Industrial Dispute No. 57/84 was made leading case. The case on behalf of the union in industrial dispute no. 235/83 was that the workman was appointed on 16-3-75, and continued with breaks till 30-12-76, and was again employed on 2-3-77 and worked for 94 days in 1977, and again for 153 days in 78 and his services were discontinued from 16-8-78 without any notice, notice pay or retrenchment compensation. That he was doing work of a regular and permanent nature in the management bank but was designated as casual labour or daily rated employee in order to deprive him the benefits of regular employee. The said termination by the management was illegal and viod abinitio, the management have further infringement the provisions of section 25G and H of the Industrial Dispute Act as junior most man was not retrenched when workman was terminated and further so many new hands were re-employed but no chance was given to the workman He is consequently entitled to reinstatement with full back wages.

4. The management has contested the dispute on the ground that Shri Swarup Narain Pande was not a workman within the definition of section 2(s) of the I.D. Act in asmuch as he was engaged on job contact basis on payment of daiy rate in conection with ad hoc and casual job/work in the Regional Stationery department and for that he was posted there. It is further averred that casual workers has been excluded from the perview of the bipartite settlement vide para 69 of Desai Award, thus no industrial dispute could be raised for said casual workman. The management has however, further taken the plea that no demand was made, hence no valid industrial dispute. The management admits that he worked in management's main branch Kanpur as casual labour in 75, 76 and 77 only for 28 days, 179 days and 5 days respectively and from 77 till 8th June 78 he worked at Kanpur Local Head Office and in the end it is contended that the industrial dispute act and its provisions are not attracted as applicant is not a workman. In reioinder again workman has reiterated that in 75 he worked for 88 days in the main branch and again in 76 in the said main branch for 265 days thereafter in 77 he worked for 79 days at Local Head Office and in 78 he worked for 153 days. He has further named new hands who were appointed as temporary after his retirement.

5. In support of its contention, the workman filed certain documents and served introgatories on the management which was duly reolled regarding number of working days, the averments for working in the main branch for the same as mentioned in the written statement. Thereafter parties gave evidence in the leading case.

6. As regards I.D. No. 57/84, it may be pointed out that the dispute relates to four persons as mentioned in the reference order that their respective dates of termination given therein and the ground being non compliance of provision section 25F, G and H of the I.D. Act. In this case also on behalf of the workman it is averred that they worked in the banking industry for regular and permanent nature of the job but they were termed casual and temporary and were paid at daily rate which was illegal as they were temporary employees they should have been terminated by notice, notice pay and retrenchment compensation in the absence of the same the retrenchment being illegal they are entitled to be reinstated with full back wages. The management in this case also contested the case on similar grounds raising the disputed that they are not workmen within the definition of the I.D. Act, that they were engaged for adhoc and casual nature of work for which they are paid, that they never completed 240 days of work, the management has however admitted that Hori Laf worked for a few days or a month in 75 again in 77 and in 78 till month July working days were 305. Similarly Sunder Lal worked for December 75 till January 78 and total number of working days were 303. Hari Shanker from April 74 to January 78 worked for 293 days. It is further admitted that Hari Shanker worked for about 10 days in the stationery department in the management bank and Hari Shanker worked for 40 days in the stationery department Kanpur and Shri Brahma Prakash worked for 445 days from March 72 to November, 1976.

7. The workmen served introgatories to the management bank, which was replied. In support of their contention the workman filed the number of documents. The management representative Shri Viini Man Singh admitted that after the services of the workmen concerned were dispenced with several others for fresh and independent requirement were engaged from time to time, no attendance register is maintained for such appointments and no appointment or termination letter was issued for such casual labours. No register of casual labour showing the seniority is maintained by the management during the continuance of the casual workers or casual workman are also engaged for requirements. He further stated we can not say if the workmen who were dispensed with other workmen were engaged during the courde of engagement continued after workmen's dispensation of work or not.

8. On behalf of the management one Shri S. C. Mishra gave his affidavit evidence and was cross examined on behalf of workman Swarup Narain Pande and Hori Lal. Shri Hori Lal gave his affidavit evidence and were cross examined.

9. In cross examination he reiterated that no contract for work was seen between the workmen and the management and that they were neither appointed nor terminated but were simply engaged for casual work on daily wages basis and were paid by vouchers. He further admitted that what work was taken from them was not enumerated in any document. He further stated that engagement of sub staff was made from 1972 to 1978 for 90 days and those contracts continued at places upto 1984. He further admitted that no seniority list of temporary or casual staff was maintained in any branch of Kanpur and further the principles of last come first go was not observed in case of termination or discharge of casual temporary workmen. He further admited that it was during the banking hours that the workmen concerned worked in the bank but he was not able to tell what work was taken from them. He has no knowledge for how many years the payment vouchers are maintained in the bank.

10. On behalf of the workman Swarup Narain Pande and Hori Lal gave their affidavit. In cross examination Shri Swarup Narain Pande has stated that he worked in the bank during the period 16-9-75 to 16-8-78 and used to go to the bank regularly but whenever he was given work he worked there else. He used to come back. He admits that he was paid at daily rate basis by pitty cash vouchers. He admits that he was a water boy from 20-5-78 to 16-8-78 of seasonal water boy for 89 days on half pay but he used to work for whole day. Workman voluntarily said that he

used to work full time work and used to take dak etc., but nothing was given to him in writing to work as peon.

11. Hori Lal has also reiterated his stand taken in the claim statement in his affidavit . In cross examination he admitted working in the bank on 11-10-72 as sub staff and he was paid monthly at the rate of daily wages. He admits that he was not required by any order in writing to appear at 10 a.m. and work till 5 p.m. but he has stated that he used to reach at bank at 9.30 a.m. and stay there till 5.30 p.m. He has stated that he was required to lift records and opening and packing boxes. He admitted that provident fund was not deducted but voluntarily stated that some money was deducted which was returned to him. He admitted that he worked in Gwaltoli Swarup Nagar branches, he has denied that he was working there as casual labour.

12. In the case of Swarup Narain Pande the management has filed the photo copy of apopintment letter dt. 19-5-78, which is admitted. According to this the workman was appointed as part time seasonal water boy on half salary w.e.f. 20-5-78 for period of 89 days and the apopintment will be deemed to have come to an end after the expiry of the aforesaid period unless extended. The management thereafter, gave a certificate to hte workman photo stat copy of which is admited on 30th September, 78 that w.e.f. 20-5-78 to 16-8-78 workman worked as part time temporary seasonable water boy.

13. On the other hand workman has filed management's certificate ext. W-5 showing that in 74 from May to October he worked in the bank for 146 days on daily wages. He has filed another certificate of the management photo copy of which is ext. W-6 showing that in the year 1972 to 1977 he worked for 240 days as temporary massenger and four days as temporary Mali. The workman has filed the appointment letter Ext. W-7 and W-8 showing that he was appointed for one day as massenger on 12-10-72 and again on 11-10-72 on two days. This printed form of appointment contained a stipulation and the temporary appointment may be terminated also at the banks discretion subject to 14 days notice in lieu of notice pay without assigning reason but in those two appointment since the appointment was for a day that portion was scored out. Certificate Ext. W-10 shows that Hori Lal also worked as temporary messenger w.e.f. 27-12-77 to 23-3-78 i.e. for 7 days.

14. It is argued that these temporary appointments were given for 87 days or 89 days i.e. less than 90 days in response to staff circular no. 168 of 76 which specifically stated that no temporary employees should be permitted to work for a aggregate period exceeding 90 days in a year. This circular is marked as Ext. M-1 on record.

15. Sunder Lal gave application Ext. W-3, that during year 1976 he hopes to have complete 240 days as should be given a fresh. Sunder Lal has also filed Ext. W-15 showing that he has worked for 72 days in the management bank from 14th September 77 to 5th January 78. Ext. W-16 shows that the workman Hari Shanker had worked for 398 days as temporary part time water boy on Khapra Mohal branch during the period April 74 to August 74. Ext. W-18 is the termination letter given to Hari Shanker on 28-6-75 showing that the rainy season had started and therefore his services of temporary part time water boy cum massenger will be terminated on 30-6-75.

16. Regarding workman Brahma Prakash managements Regional Manager per ext. W-22 written to ALC that workman Brahma Prakash worked for 446 days as temporary massenger on our Mahatma Gandhi Road Branch during the period March 72 to November 76. Ext. W-23 certificate issued by the management filed shows that workman Brahma Prakash had worked for 446 days during the period 72 to 76 as temporary massenger. Management has filed a number of staff circular relating to curbing of temporary employees for working for more than 90 days.

17. The main argument of the management is that daily rated workmen similarly casual workmen were not appointed in any regular vacancies but were employed for casual or job work which does not pertained to regular nature of work in banking industry. They have referred para 16.9 of the Desai Award which lays down that casual/job workers have been specifically excluded from the perview of the bank award. That position is not disputed. If the management engages labourers or a workman for a particular job or a casual nature of job not occurring or recurring in the banking industry generally but arising by chance such workers would be out side the perview of the work in the banking industry and for them bipartite settlement, Sastri Award or industrial dispute act would not apply. But the moment it is established that the work was taken from them not for any extraneous job or casual nature not connected with the banking industry but work was taken in connection with the regular course of business in the banking industry such workmen would come within the definition of the temporary employees as given in para 20.7 of the bipartite settlement and as given in para 524 of Sastri Award. The dictionery meaning of word Casual is happening by chance or often occasional or random as opposed to regular. In a banking industry where customers arriving in number and there is need to serve them water which work becomes more important in the summer season. The work of water boy engaged in summer season would be a work in the banking industry. Similarly if the work is taken from him to work as Mali for maintenance for garden of the management bank the engagement will be in the bank and in connection with the banking industry and would not be an extra job to be termed as casual job. In the case of other workmen it is conceded that they worked as casual massenger of and on with breaks and they have worked for a good span of years. No doubt in circumstances they will be allowed to continue beyond 90 days. The work of temporary messenger though on daily wages would be nothing but a man engaged in the banking industry for managerial work and would be a workmen in the industry and would come within the definition of workman as given in the industrial dispute act, as he has worked for hire or reward.

18. The management is alive of situation that in case it engages temporary employees for a period 14 days or beyond and wants to terminate their services in between then it shall terminate his services by paying 14 days pay in lieu of notice as contained in the printed form in ext. W-7 and W-8. It is strange that all those workmen worked for more than 14 days and their engagement could be nothing but as temporary workmen in the banking industry they too should be terminated by 14 days notice as required in para 522(4) of the Sastri Award, none compliance of the same renders their termination illegal.

19. Further for the purpose of temporary employment town has to be taken as unit as laid down in para 507 of the Sastri Award. It is not disputed that after tremination of the workman temporary hands were appointed in bank, in the absence of any seniority list they were not given reemploment which should have been done in view of provision of para 507 or section 25H of the I.D. Act. None compliance of the same also renders termination illegal

20. On the point of 25G of the I.D. Act the management rentesentative Shri Vijai Man Singh stated that no register of casual labours showing their seniority was maintained by the bank and that during the continuance of his casual workers other casual workers were also engaged for casual requirement. Regarding them he stated that he could not say if the workmen who were dispensed with other workmen engaged during the course of employment continued after workman's dispensation of work or not. Hori Lal in his affidavit para 6 has stated that when his services were terminated persons junior to him including Chhotey Lal and others were allowed to continue and were subsequently made permanent massengers. The management has not controverted this position by filing any documents. Swarup Narain Pande in his affidavit para 6 has deposed that many junior hands were retained in service whereas he was retrenched and those junior hands were Shri Ram Kirpal Rajendra Prasad Singh and Rajendra Agrawal who were made regular massenger later on. The management has not controverted that those persons were not junior to Shri Swarup Narain Pande and were continued even after their termination. Thus in these circumstances on the principles of last come first go they should have been terminated and not the workman and the termination on that count is also illegal in view of infringement of section 25G of the I.D. Act and para 507(1) of Sastri Award.

20. In Lab. 1980 IC page 300 Allahabad Mahmood Versus Balwant Singh it was held that if an employer had employed persons for the purpose of trade or business then even though employment be of a casual nature he would still fall with in the category of workman provided other condition stated are satisfied.

21. In the instant case Swarup Narain Pande even though employed as part time seasonal water boy on half salary was employed for the purpose of trade or business in the banking industry.

22. In Tapan Kumar Versus General Manager Calcutta Telephones 1981 lab IC NOC 68 Calcutta wherein it was held thus if a casual labour is employed in an industry for hire or reward he will be the workman within the meaning of section 2(s), there is nothing in the definition which includes a casual employer on the contrary section 25-C of the I.D. Act gives a sufficient indication that a badli workman or a casual workman is workman when it includes then from the right of compensation thereof.

23. Thus in view of the matter Swarup Narain Pande engaged as water boy and other workman namely Hori Lal, Sunder, Hari Shanker and Brahma Prakash worked for sufficient period in the banking industry through not completing 240 days in any span of one year of claim benefit of section 25F yet they were temporary employees and as principles of last come first go was not observed nor were they called for reemployment when other persons were employed renders theirs termination illegal. Further admitedly on their termination they were not given 14 days notice nor notice pay in lieu thereof, the termination is illegal on that account also as provided by para 522(4) of the Sastri Award.

24. In these circumstances and in view of the discussions and law discussed above I hold (in Industrial Dispute No. 57/84) that the action of the management of SBI Kanpur in terminating the services of S/Shri Hori Lal, Sunder Lal, Hari Shanker and Brahma Prakash w.e.f. 30-8-78, 17-11-78, 16-8-78 and 16-11-78 respectively is not justified in view of the provisions of section 25G and H of the Act as well violative of para 522(4) of the Sastri Award. The result is that termination being illegal they are entitled to be reinstated with full back wages.

25. Similarly I further hold that termination of Shri Swarup Narain Pande (ID No. 235/83) Casual labour w.e.f. 16-8-78 was illegal and not justified, on account of vication of 25G and H and 522(4) of Sastri Award. The result is that he too is entitled to be reinstated with full back wages.

26. 26. I, therefore, give my award accordingly.

27. Let six copies of this award be sent to the Govt. for publication and further ordered that a copy of this award be sent on the record of industrial dispute no. 235/83 Swarup Narain Pande Vs. State Bank of India.
Dated : 18-3-86

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012/167/79-D.II(A)]

का. आ. 1675.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-3-86 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 1675.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th March, 1986.

24 GI/86—23.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri J. Venugopala Rao, Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 13 of 1982

BETWEEN

The Workmen of State Bank of India

Hyderabad (Alur Branch).

AND

The Management of State Bank of India

Hyderabad.

APPEARANCES :

Sarvasri D. S. R. Varma and K. Narasimham, Advocates—for the Workmen.

Sri K. Srinivasa Murthy, Advocate—for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-12012/188/81-D.II(A) dated 3rd March, 1982 referred the following dispute under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the management of State Bank of India and their Workman to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of India in relation to its Alur Branch in terminating the services of Sri Shaik Masthan Sab in July, 1980 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 13 of 1982 and notices were issued to the parties.

2. In the claims statement the workman stated that he was appointed at Alur Branch of State Bank of India and worked as Watchman/Sweeper-cum-Waterboy/Messenger from 25th October, 1974 to 10th July, 1976 and he worked for 240 days from October, 1974 to September, 1975 and 372 days till July 1980. It is his case that he attended for Zonal Interview in 1975 which was conducted at Kurnool. According to him he was not allowed to work continuously although the vacancy against which he was working were continuous vacancies and the same is unfair labour practice on the part of the Bank. Finally he mentioned that his services were terminated without any notice or wages in lieu of notice which is condition precedent to retrenchment under Section 25F of the I.D. Act and therefore termination is illegal and void. Even otherwise in view of his termination after 240 days of service it amounted retrenchment under Section 2(oo) of the I.D. Act and he is entitled for re-employment as retrenched employee under Section 25-H of the I.D. Act. According to him he is a victim of unfair labour practice on the part of the Bank as he is deprived of the benefits of the I.D. Act. The workman could not secure any job inspite of his best efforts. Therefore it is prayed that the termination of the services of the workmen is illegal and improper and that he should be reinstated with retrospective effect and back wages, including attendant benefits and pass such other orders.

3. The Management on the other hand filed a counter. It is denied that the Petitioner worked for 240 days from October, 1974 to September, 1975 and 372 days till July 1980. According to the Management he was given work depending upon the availability of work due to leave vacancies. It is the case of the Management that he put in 199 days of service and as such the question of issuing of any notice of wages in lieu of notice as contemplated under Section 25-F of the I.D. Act did not arise. It is the case of the Management that he is only a casual employee and non-allotment of work to the petitioner does not amount to retrenchment under Section 2(oo) of the I.D. Act. Therefore it is contended that the reference should be rejected and there is no award in favour of the workmen.

4. The workman himself examined as W.W1 on his behalf and marked Exs. W1 to W3. On behalf of the Management

two witnesses were examined and marked Exs. M1 to M3. Ex. M4 to M50 were marked by consent.

5. W.W1 mentioned that Shaik Mastan Sab who is a concerned workman in the matter. According to him he joined as Sweeper-cum-Water boy on 25th October, 1974 and worked with gaps till 10th July, 1976 on temporary basis and during that period he worked for 240 days. Ex. W1 is the certificate issued to him by the branch Manager to that effect. The termination order issued to him on 14th July, 1976 showing that he was terminated with effect from 31st March, 1976. It is marked as Ex. W2. It is his case that he was taken back into service in 1979 and worked again till July, 1980 and without any notice whatsoever he was terminated. According to him till July 1980 in all he had put in 385 days. But there were no written orders showing termination him in July, 1980. He was orally informed that he was removed from service and that juniors to him were continued that he was not given any interview and subsequently there were recruitments for temporary posts and he was not given 14 days notice prior to his termination and therefore prayed for reinstatement. In the cross-examination he mentioned that he continued for 219 days continuously in the first instance and they used to maintain an account of number of days worked and persons like Sweepers and Watchmen and the Bank used to give him debit vouchers for the wages payable to him. He conceded that he was not passing orders whenever he was taken back into service.

6. M.W1 is one G. Mahaboob Branch Manager of State Bank of India who worked at the relevant Branch where W.W1 worked (Molegavali). According to him the record pertaining to service particulars of employees of Molegavali would be in Alur Branch. He admitted that he worked in Molegavali for six months and that during that period Sk. Mastan Sab was working and Ex. M1 is the application, Ex. M2 is forwarding letter. The correction found in Ex. M1 were there from the beginning. According to him Ex. W1 contains that acknowledgement signed by him and he only certified the number of days worked as shown in it. It is the case that the records would be at Alur Branch and he did not certify the e figures by him as correct or not. He mentioned that in his covering letter he reported that there were "three enclosures" to that application and he was also sending his application for consideration. He conceded that he did not mention in the covering letter that he received the statement of particulars also along with the application from W.W1. He denied Ex. W1 is the certificate issued by him. But it is his case that the Regional Office record would show that he forwarded the application of the workmen to the Management. According to him Ex. M3 was sent in reply to a communication received from the Regional Office and that it is not available with them in the records.

7. M.W2 is the P.B.D. Manager (Personnel Banking Division), State Bank of India, Adoni. He worked for some time at Alur Branch of the State Bank of India. According to him he knew the petitioner W.W1 who worked as Messenger under him at Alur Branch at the relevant time. He also admitted that Molegavali was only a pay office of Alur Branch. According to him the Petitioner worked as Messenger for 199 days. By seeing Substitute Engagement Register maintained by them at Alur Branch which is marked as Ex. M51, he deposed the same. After seeing Ex. W1 he mentioned that it was the acknowledgement by the then Branch Manager of Molegavali G. Mahboob of State Bank of India on the basis of Ex. M2 given by the Petitioner. According to him the said Mahaboob (M.W1) did not verify Exs. W1 and M2 on the basis of Ex. M51 and M52 and certified the number of working days as 240 days, 380 days as shown thereunder. According to him on the basis of Ex. M4 to M50 the Messenger worked for only 190 days and not 240 days as contended by the worker. He came forward to depose that Mahboob (M.W1) simply forwarded Ex. M2 to the Head Office along with Ex. M1 and the said Branch Manager Mahboob never approached to certify Ex. M2 and he was never called to verify the said statement. Finally he admitted that the records Exs. M51 and 52 are in the custody of Alur Branch. Finally he mentioned that the petitioner never worked for 240 days as mentioned by him. He worked only for 199 days and the question of working for 240 days or 372 days continuously did not arise as he worked for 199 days only continuously in a period of 12 months. According to him Ex. M51 which is a substitute engagement and payment register whenever they enter the substitutes they mention in it showing the period and the amounts paid. He conceded that at page 84 he entered that one Smt. Immam Bee, mother of this workman worked as Sweeper-cum-Waterboy in Molegavali Sub-Office and the said entries were struck off in red ink, and for the month of June 1975 the wages were paid for the Sweeper-cum-Waterboy at Molegavali sub-office as seen at page 84 of Ex. M51. He could not deny or confirm the suggestion that W.W1 was paid before 30th June 1975 after seeing Ex. M52. According to him it might have been that Molegavali Sub-office was opened on 11th November, 1974 and he could not say how Shaik Mastan was removed in June 1975 when he worked as Sweeper-cum-Waterboy in April and May 1975. He conceded that there was an entry at page 84 of Ex. M1 showing that an amount of Rs. 30 was paid in June 1975 when the same was struck off. He denied the suggestion that it related to Shaik Mastan Sab. According to him that the date therein was rounded of in green ink and the same is marked as Ex. M51(a) and denied the suggestion that it related only to Shaik Mastan Sab. He asserted that those entries relate to Shaik Immam Bee, the mother of Shaik Mastan Sab. It is suggested to him that Shaik Mastan Sab worked in the month of June 1975 and to get over the Industrial Disputes Act showing that if he worked for 240 days period he would be entitled to certain benefits, his mother Shaik Imam Bee was substituted in his place for the purpose of these entries and Ex. M51 and M51(a) are false entries. He could not say from Ex. M51 readily who was paid wages for the period of four days as substituted Watchman after seeing page 71 of Ex. M52. As per the statement Ex. M53 during the calendar year 1st November, 1974 to 30th October, 1975 he admitted that W.W1 worked as part time employee for 190 days, as per Exs. M4 Shaik Mastan Sab worked for two days full time watchman on 11th and 18th November of 1974; and 2nd December, 1974 he was paid Rs. 40.65 as wages and as per Ex. M6 W.W1 worked as substitute on 16th and 17th December, 1974 and he was paid wages, and that on 24th December, 1974 Shaik Mastan Sab was paid a day full wages as per Ex. M7 and that as per Ex. M10 there was indication that he worked as substitute messenger and watchman full time on 9th December, 1974, 27th December, 1974, 2nd January, 1975 and 11th February, 1975 and similarly he admitted that under Ex. M12, M13 and M14 there were days he worked as substitute watchmen. Then a question put to him whether he worked as part time Sweeper-cum-Waterboy in 1/3rd scales for 199 days during the period October 1974 to October 1975 and in addition to that he attended as full time employee for 270 days and payments were made separately, the witness admitted same as correct. Then the witness was suggested that as per the Circular 73/73 27 days should be converted as part time employee in 1/3rd scale as 81 days. Thus he would be treated as completed 280 days, for which the witness denied the same as not tenable.

7. The admitted facts of the case are Shaik Mastan Sab worked as Sweeper-cum-Waterboy from 25th October, 1974 and with gaps he worked till 10th July, 1976. Now Ex. W1 is the particulars of service signed by G. Mahboob who is examined as M.W1 for the Management. M.W1 admitted that he worked at Molegavali Branch for six months and during that period Shaik Mastan Sab was working. It is his case that Shaik Mastan wanted him to forward his application to the Head Office which is marked as Ex. M1 and M2 is the forwarding letters. According to him the corrections in Ex. M2 were there in the beginning and acknowledgement of this Ex. M1 he signed in the copy Ex. W1 he signed it. So it is his case that Ex. W1 is not a certificate given by him for the number of days worked as shown in it but he admitted that he signed as a copy of the acknowledgement while forwarding Exs. M1 and M2. Now Ex. M2 would show that Shaik Mastan put in an application stating that those who worked for 240 days in 12 months period were being given appointment in Madras Circle and that in 1975 from January to September he worked in all for 240 days and further he worked for 145 days beyond September 1975 and thus he put in total period of 385 days upto 30th September, 1980. He further mentioned that copies of the certificates given by the Branch Manager was enclosed for his reference. He also mentioned that his mother Imam Bee was working as part time employee in Nandyal Branch. Therefore he requested in his application to kindly consider his case favourably and to absorb in a permanent vacancy for which he mentioned that he would be grateful.

Now M.W1 stated that he did not verify the records while forwarding Ex. M2 with its enclosures which is similarly to Ex. W1. It is his case that he acknowledged Ex. W1 as a statement which was furnished by the workmen himself. Now M.W1 is asked to explain what was the third enclosure

which was referred by him in Ex. M1 he mentioned that he could not remember the same. It is suggested to him that the other enclosure was a certificate issued by him concerning these particulars furnished under Ex. W1 which is shown as enclosure and he denied the same. Now Ex. M1 is admittedly having Ex. M2 and the original of Ex. W1 as per the Management. These are only two enclosures and third enclosure is not there. It is suggested that the third enclosure is the certificate issued by the Manager while forwarding the letter Ex. M1 after verifying the statement. M.W2 who worked as B. P. D. Manager at Adoni mentioned that he worked as Branch Manager Alur and Molegavali was the pay offices is under Alur Branch. He marked Ex. M51 as the Substitute Engagement Register. It is his case that the Mastan worked for 199 days and not 240 days on the basis of Exs. M4 to M50. Admittedly it is the Management case that M.W1 did not verify Ex. W1 particulars and Ex. M2 particulars on the basis of Ex. M51 and M52 and certified the number of working days 240 days and 285 days as shown thereunder. Since Ex. M51 and M52 are available it can be verified whether he worked for those number of days as alleged by him and whether the particulars furnished under Ex. W1 were really certified or not by the Management. On 27th June, 1975 at page 84 of Ex. M51 it is shown that one Imam Bee worked as Sweeper-cum-Waterboy at Molegavali sub-office and she is the mother of Shaikh Mastan Sab and the said entries were struck off. It is conceded by M.W2 that the Branch Manager is the authority to appoint substitute like Messengers, Waterboy etc. The witness after seeing Ex. M51 at page 84 and also after clarifying Ex. M52 with reference to June 1975 he could not say when the Sweeper-cum-Waterboy at Molegavali sub-office was paid wages. In other words Ex. M52 which is the charges account register did not indicate the payment of wages at Molegavali sub-office corresponding to page 84 of Ex. M51. M.W2 could not deny the suggestion or confirm the suggestion that Shaikh Mastan was paid the wages for June 1975 and even after verifying Ex. M52 at page 82 he was of opinion that Molegavali Sub-Office was opened probably on 11th November, 1974. That is the state of affairs, Now the case of the worker is that he worked as Sweeper-cum-Waterboy in April and May 1975 and finally M.W2 conceded that Shaik Mastan worked as seen from page 84 of Ex. M51 that there is entry showing that an amount of Rs. 30.00 was paid in June, 1975 and the same was struck off. The witness tried to deny that the same related to Imam Bee but not Shaik Mastan. He denied the suggestion that the date there was rounded of in green ink marked as Ex. M51(a) at page 84 and that it related only to Shaik Mastan and he tried to say that the entries related to Shaik Imam Bee and if Shaik Mastan worked for the month of June 1975 then the case of the workman that he completed 240 days during 1975 and that his mother's name was written in his place for the purpose of the entries and it is his case that these entries at Ex. M51 at page 84 was subsequently entered to deprive him of his length of service. It is a matter of verification. At any rate Ex. M51(a) entry is in a different ink and denial of M.W2 that the correction made at page 84 rounding off the date is not correct. He could not say to whom four days wages were paid as substitute watchman after seeing page 71 of Ex. M52. The witness was suggested that there was no record to show that xyz was paid under the relevant vouchers after seeing page 71 of Ex. M52. The witness merely said that it did not relate to Shaik Mastan. On the other hand Ex. W1 would show that he worked but the Management was not able to show to whom the substitute paid wages and when the workmen was clear and certain that he worked for that period and wages were paid to him it goes a long way to show when he is not an author of Ex. M52 and if they are not able to show to whom they paid the wages and when he is not given any dates as appointment and dates of termination is an oral assertain, then his evidence had great weightage when the records are not properly maintained to contradict him. Moreover Ex. W1 shows that he worked for that period and asserted; coupled with his evidence when there is no clinching material in the records maintained by the Management they paid wages to XYZ for that period go to show that what W.W1 is true and correct. Now Ex. W3 would show that there is a staff circular issued to regularise part time employees and it is dated 29th March, 1966. It showed that the temporary part time people were being regularised. M.W2 conceded that Ex. W3 applied to those part time temporary staff who have completed 240 days continuously in a calender year and not to others. Now as per the statement Ex. M53 during the calender year from 1st November, 1974 to 30th April, 1975 it is the case of the Management that he worked for 199 days. Under Ex. M4 Shaik Mastan worked for two days on full time wages on 11th and 18th November, 1974 and on 2nd December, 1974 he was paid Rs. 40.65 ps. as wages as Ex. M4 and as per Ex. M6 Shaik Mastan worked as substitute on 16th and 17th October, 1974 and paid wages Rs. 25.90 and that on 24th December, 1974 he worked for one day as full time watchman and paid Rs. 13.53 as per Ex. M7, and that Shaik Mastan was paid an amount of Rs. 101.63ps as substitute Messenger and Watchman full time for working on 9th December, 1974, 27th January, 1974, 2nd January, 1975 and 11th February, 1975 6th, 7th, 8th and 15th January, 1975 as Messenger as per Ex. M5 the petitioner was paid Rs. 12.37ps for working as substitute Messengers on 11th December, 1974 as per Ex. M8 he was paid Rs. 24.74ps for working as substitute duties for two days on 3rd and 4th February, 1975 at Molegavali as per Ex. M14 Shaik Mastan worked as substitute for six days and paid Rs. 76.08ps as per Ex. M13 Shaik Mastan was paid Rs. 13.88ps on 11th April, 1975 for preforming substitute watchman duties. At page 48 of Ex. M51 an amount of Rs. 38.04 was paid to Shaik Mastan for working on 14th, 17th and 27th April, 1975. Finally it is suggested to M.W2 that Mastan was working as part time Sweeper-cum-waterboy in 1/3 scales for 199 days during the October 1974 to October 1975 and in addition to that he worked as part time duty that he attended as full time employees for 27 days as per Ex. M4 to M13 and payment was paid separately and witness admitted the same to be correct and to the suggestion that 27 days should be converted as part time in 1/3rd scale then 81 days will be added to those 199 days and thus he will be completing 280 days by adding other days also. He denied the suggestion as not correct. He could not explain Ex. M1 contains two enclosures which are marked as Ex. M2 and what happened to the third enclosure. Ultimately after cross examination of M.W2 the denial of M.W2 that the record did not show actual period worked except saying paid amounts as vouchers seems to be incorrect. The records were not correctly maintained to show how many days he worked as part time and how many days he worked as full time and how many days he worked as Sweeper-cum-Waterboy. These vouchers Exs. M4 to M50 and the substitute engagement register Ex. M51 as well as the charges register Ex. M52 reveal that the number of days Shaik Mastan was engaged during November 1974 to October 1975 would come to more than 240 days continuous service though Ex. W1 is signed as Bank Manager M.W1, they take up the stand it is only acknowledgement and it is not a certificate and the third enclosures is not forthcoming. Ex. M53 was worked out by the Respondent Bank itself on the basis of vouchers Ex. M4 to M50 and the same was filed as statement showing the particulars wages paid to Sri Shaik Mastan temporary messenger/watchmen/waterboy. In fact the evidence of M.W2 would reveal when the same read with Ex. M53 that during the calendar year 1st November, 1974 to 30th October, 1975 the petitioner worked for part time for 199 days and it is also admitted to be correct by M.W2. When a suggestion was put to him. Further Ex. M4 to M13 would show that the employee worked as full time substitute for 27 days and he was paid accordingly arrived at on the basis of vouchers referred to above. The same can be seen at page 48 of Ex. M51 and also the same was conceded by M.W2. So the same would come to 199 days plus 27 days would come to 226 days.

8. The workman contention that his services were terminated from July 1975 and not from June 1975 as made to appear in the record Ex. M51 at page 84 as seen from page 84. The salary for June 1975 was intended to be paid on 26th June, 1975 and noted as "Ditto" and the said "Ditto" to Shaik Mastan Sab who was shown above as Sweeper-cum-Waterboy for April and May, 1975 in June 1975. Though the word "Ditto" was there that was rounded of and in its place Immam Bee name was written. It was specially marked as Ex. M51(a) if this is added for June 1975 30 days then it would show that he worked for 256 days from November 1974 to October 1975 till and thus the contention is certified by Ex. W1 and Ex. M2 of Ex. M51 correction made therein would also justify the same and M.W2 can not deny the said facts in so many words and though he gave evasive and negative replies to a specific question.

9. Thus on a careful consideration of the entire record I am of opinion that Shaik Mastan worked for 240 days continuously in a year as per Section 25(B)(2)(a) of the I.D. Act and his services are terminated admittedly without any notice and notice compensation and thus it is violative

of Section 25F of the I.D. Act there is no doubt that non-compliance of Section 25F of the I.D. Act is held abinitio void by number of decisions.

10. If the contention of the Management is right that Shaik Mastan did not put in 240 days continuous service even then for the purpose of argument, it must be held that his termination without notice of 14 days as required under Sastry Award 522(4) must be held abinitio void. It says that the service of any employee other than the permanent employee or probationer may be terminated after 14 days notice if such an employee leaves service without giving such notice he shall be liable for two weeks pay including of allowances and an order relating to discharge or termination of service should be in writing and a copy of such order shall be applied to the employee concerned. So even that was not done in the instant case. Therefore it must be held that the procedure for termination of employees as contemplated under Sastry Award was not one.

11. Now the Management contended that the petitioner is only a casual worker in the question of giving 14 days notice has no bearing. But the Sastry's Award 522(4) directs that service of any employee other than the permanent employee requires 14 days notice for termination. Therefore Sastry Award applied to the temporary employees as well and Bank is bound to apply para 522(4) of the Sastry Award. Para 522(4) is a mandatory directions and under Section 25F of the I.D. Act there is a stipulation that no workmen employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons and also paying wages in lieu of such notice etc. The Sastry Award with reference to Banking Companies as modified by the Bank Award Commission has the force of statute law. Therefore the non-compliance para 522(4) renders the termination in case of Shaik Mastan as void and he is entitled for reinstatement with back wages and all attendant benefits. Moreover the procedure as contemplated under Section 25G of the I.D. Act that the employer shall ordinarily retrench the workman who was the last person to be employed in that category unless for reasons to be recorded the employer retrenches any other workman is not followed. The evidence of Shaik Mastan as W.W1 would show that recruitment was made for temporary post after his termination and he was not called for interview at the time of recruitment. This fact was not denied in the cross-examination of the said witness. At any rate his mother who was said to be preferred as indicated under Ex. M51 at page 84 is preferred to him to avoid continuity of service and the record would show that his Mother Shaik Immam Bee was appointed in his place for subsequent periods and wages were paid to her, from July, 1975. So this is in violation of Section 25G. It is not the case of the Management that Shaik Immam Bee was acting even earlier to him and therefore she was preferred when such a retrenchment was done. So the Managements theory that he is only a casual employee and therefore the non-allotment of work to him did not amount to retrenchment under Section 2(oo) of the I.D. Act and that he has no claim for re-employment under Section 25H are all made to cover up the violations under the I.D. Act after taking the place that the retrenchment did not arise when the workman is terminated.

12. As a matter of fact Messengers/Watchmen/Waterboy in the regular posts and so that the employees engaged in such posts are casual employees is contrary to the provisions of Sastry Award and Desai Award. Even under Ex. M53 which is the statement given by the Management in the Bank Shaik Mastan is referred as temporary Messenger/Watchmen/Waterboy. Therefore the Bank cannot deny that Shaik Mastan was a temporary employee as per its own record whether temporary or casual, the records reveal that he worked as part time employee against permanent vacancy and as full time substitute employee against temporary vacancies. Therefore it is needless to contend that he is not a workman within the meaning of Section 2(s) of the I.D. Act. Even Sastry Award and Desai Award treated as temporary employee as workman and covered them and it is in Digwadih Colliery v. Their Workmen (AIR 1966 SC page 75) The Supreme Court held while considering amendment of 1964 with reference to Section 25F that Jaldhar Singh who was a Badli workman being a substitute for permanent employee and he worked for more than 240 days in each calendar year though with interruptions and when a dispute arose the Supreme Court held when the termination of service of Badli workman will be illegal when he has put in service of 240 days in each of the years as there was no work for him. The termination of service of Colliery workman 1961 was held illegal when he had put in service of 240 days in each of the year 1959 and 1960. It is laid down that no uninterrupted service is necessary if the total service is 240 days in a period of 12 calendar months either before the several changes or after this. So even if Badli worker is entitled for the benefit of retrenchment as pointed out therein, even when there was lay off, the Badli workman who fell within the Section 25C were held to be entitled to lay off compensation in Laxmi Mills v. Labour Court [1965(I)LLJ page 92]. P. Joseph v. Management of Gopal Textiles [1975(I)LLJ, page 136 at pages 137 and 138]. Therefore the protection benefit which are available under the I.D. Act, for a temporary workman who comes within the meaning of Section 2(s) must be protected. Even in Management Willcox Buckwell India Ltd. v. Jagannath (AIR 1974 SC. page 1166). It was held by the Supreme Court that they find no distinction between the case of Badli worker and that of a temporary employee. In that case the management case the ground for termination of services as surplus labour. The Supreme Court pointed out that there is no escape from the conclusion that the concerned workman were retrenched and could not have been done without giving them the benefit provided by the relevant provisions of the Act as the same was not done, the Labour Court was justified in ordering their reinstatement.

13. At any rate it is the contention of the Management that the workman did not complete continuous service of 240 days and as such he is not entitled for any benefits, as pointed out whenever there is clear vacancy and he is working as temporary Sweeper-cum-Waterboy. He is substituted by his mother and as such non-allotment of work to him cannot be argued as no retrenchment. First of all the stipulation of 240 days requirement of continuous service is only in relation to Section 25F of the I.D. Act but it cannot be tagged in to every other sections of I.D. Act. If a workman had 240 days and more in a year under Section 25F he is entitled to notice or pay in lieu of notice and compensation for having put in not less than 240 days in a year still the termination is only retrenchment provided it is done for want of vacancy. In the instant case there is vacancy yet his services are terminated. So it is not a case of want of vacancy which prevented him from completing 240 days of continuous service even taking for granted that under Ex. M51 at page 84 that his mother Shaik Imam Bee substituted him for the months of June and July 1975. It shows that it is only after terminating him which amounts to retrenchment she was appointed in the said vacancy. The principle of last come first go is not followed and it is not a case where there is no vacancy for which the termination or retrenchment arose. Under Section 25G and 25H the employer shall ordinarily retrench the workman who was the last person to be employed in category and under Section 25H where any workmen are retrenched and when the employer proposes to take into employment any person should give an opportunity to the retrenched workmen who are citizens of India to offer themselves for re-employment. So under Section 25G and 25F of the I.D. Act which are independent of Section 25F the stipulation of continuous service of 240 days is not there. These sections 25G and 25H of the I.D. Act, apply to all cases of retrenchment irrespective of 240 days continuous service in a year and the principle of last person in the employment to go and that in case of re-employment the employer should give opportunity to the retrenched workman apply to all such cases of workmen who are terminated or retrenched in the given circumstances.

14. In the instant case the evidence of clearly culled out that Shaik Mastan Sab termination is due to non-allotment of work at the instance of the Management. So to it is say that not retrenchment is nothing but trying to cover up the mistakes of the Management as discussed or as could be seen. All 'retrenchment' is termination of service but all termination of service may not be 'retrenchment' (page 322 of Vol. I. Malhotra edition). In order to be 'retrenchment' the termination of service has to fall within the ambit of the definition of 'retrenchment' in Section 2(oo) of the Act. Further more Section 25F prescribed the requirements of notice and compensation as conditions precedent to retrenchment of workman. Section 25F introduces the rule "last come first go" in effecting 'retrenchment' of workmen. A termination of service, without satisfying these statutory requirements will be no 'retrenchment' in the eye of law. Hence non-compliance of these mandatory provisions will render retrenchment as invalid. The industrial adjudication therefore

has jurisdiction to see whether infact, these preconditions are complied with or not. So as laid down in Workmen of Subong Tea Estate v. Subong Tea Estate [1964(1)LLJ, page 555]. The proposition laid down therein are useful for the industrial adjudication. It is laid down firstly that the Management can retrench its employees only for proper reasons which means that it must not be actuated by any motive of victimisation or any unfair labour practice. Secondly it is for the management to decide the strength of its labour force and the number of workers to carry out the efficiently of the work in an industrial undertakings. Thirdly if the number of employee may exceed reasonable and legitimate needs of the undertaking if any workmen becomes surplus it is open to the Management to retrench them. Fourthly the workman became surplus on the ground of rationals or on the ground of economy. Fifthly the right of the employer to effect retrenchment cannot normally be challenged but when there is a dispute in regard to the validity of any retrenchment it would be necessary for the Tribunal to consider whether the impugned retrenchment was justified for proper reasons and it would not be open to the employer either capriciously or without any reasons at all to say that it proposes to reduce its labour force for no rhyme or reason.

15. Of course the burden in such cases is one the workmen who is retrenched to put forward his claim. The employee who is retrenched must prove that he was retrenched from service without proper reasons and that it is nothing short of unfair labour practice in the instant case. It is not a case of voluntary retirement of the workman or any other ground mentioned in Section 2(oo) of the I.D. Act. Moreover Shaikh Mastan Sab termination is not on account of any disciplinary action or due to ill-health or retrenchment of age of superannuation. Sri D. S. R. Varma who argued for the workman clearly proved from the evidence of M.Ws.1 and M.W2 admissions as well as the evidence of W.W1 and the documents filed by him that the Management retrenched the said Sweeper-cum-Waterboy without any reasons and with a motive of victimisation which amounted to unfair labour practice, and that same violated the Sections 25F and 25G and 25H and the said termination is not retrenchment on any count under Section 2(oo) of the I.D. Act. As already pointed out the said termination and breaks shown to Shaik Mastan Sab were contrary to the provisions of the I.D. Act and also the porvisions of Sastry Award para 522(4). Therefore I hold that the action of the Management of State Bank of India in terminating the services of Shaik Mastan Sab in July, 1980 is not justified and he is entitled to all the attendant benefits and back wages.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of the Tribunal, this the 25th day of Febraury, 1986.

Sd/-
Industrial Tribunal

Appendix of Evidence

Witnesses Examined for the Workmen :	Witnesses Examined for the Management :
W.W1 Shaik Mastan Sab.	M.W1 G. Mahaboob M.W2 D. Dada Hayat

Documents marked for the Workmen :

Ex. W1—True copy of the service particulars of Shaik Mastan Sab.

Ex. W2—Letter No. F26 dt. 14-7-76 addressed by Branch Manager State Bank of India, Alur Branch to S. Mastan Sab with regard to Temporary appointments, Temporary/Substitute basis.

Ex. W3—Photostat copy of the staff circular No. 18 dt. 29-3-66 with regard to terms and conditions of service of Temporary and part time employees.

Documents marked for the Management:

Ex. M1—Letter F. No. 26/1, dt. 2-1-81 addressed by Branch Manager, State Bank of India, Molagavalli to the Regional Manager, State Bank of India, Region II Hydreabad with regard to staff subordinates/ Menials.

Ex. M2—Representation of Shaik Mastan Sab dated 29-12-80 forwarded by Branch Manager, State Bank of India, Molagavalli to the Regional Manager, State Bank of India. Hyderabad Region-III.

Ex. M3—Letter dt. 25-6-1981 addressed by Branch Manager, State Bank of India, Molagavalli to the Regional Manager, State Bank of India Region II, Hyderabad with regard to staff Miscellaneous with regard to appointment of Shaik Mastan Sab as temporary Messenger/Watchman.

By consent

Ex. M4—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Waterboy on 11-11-74, 18-11-74 and 2-12-74 with voucher dt. 10-12-74 for Rs. 40.65.

By consent

Ex. M5—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger Watchman/Waterboy on 11-12-74 with voucher dt. 13-12-74 for Rs. 12.37.

By consent

Ex. M6—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman|Waterboy on 16-12-74 and 17-12-74 with voucher dt. 26-12-74 for Rs. 25.90.

By consent

Ex. M7—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Wichman/Waterboy on 24-12-74 with voucher dt. 28-12-74 for Rs .13.53.

By consent

Ex. M8—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Waterboy on 3-2-75 and 4-2-75 with voucher dt. 8-2-75 for Rs. 24.74.

By consent

Ex. M9—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Waterboy from 17-11-74 to 28-12-75 with voucher dt. 6-3-75 for Rs. 104.00.

By consent

Ex. M10—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Waterboy for 9-12-74, 2-1-75, 27-12-74, 11-2-75, 6-1-75, 7-1-75, 8-1-75 and 15-1-75 with voucher dt. 6-3-75 for Rs. 101.63.

By consent

Ex. M11—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Waterboy for April, 1975 with voucher dt 1-5-75 for Rs. 30/-.

By consent

Ex. M12—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Waterboy for March, 1975 with voucher dt. 9-4-75 for Rs. 30/-.

By consent

Ex. M13—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Waterboy on 7-3-75 with voucher dt. 11-4-75 for Rs. 13.88.

By consent

Ex. M14— Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/

Watchman/Waterboy for 24-2-75, 6-3-75, 25-3-75, 31-3-75, 3-3-75 and 8-4-85 with voucher dt 16-4-75 for Rs. 76.08.

By consent

Ex. M15—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Waterboy for 14-4-75, 17-4-75 and 22-4-75 with Voucher dt. 9-5-75 for Rs. 38.04.

By consent

Ex. M16—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Waterboy for May 1975 with voucher dt. 12-6-75 for Rs. 30.00

By consent

Ex. M17—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 15-10-75 and 21-10-85 with Voucher dt. 31-10-75 for Rs. 25.45.

By consent

Ex. M18—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 2-12-75, 9-12-75, 16-12-75, 17-12-75, 18-12-75, 23-12-75 and 25-12-75 with voucher dt. 26-12-75 for Rs. 93.10.

By consent

Ex. M19—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 15-11-75 with Voucher dt. 25/28-11-75 for Rs. 13.70.

By consent

Ex. M20—Statement showing the particulars of Wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 13-11-75 and 14-11-75 with voucher dt. 15/20-11-75 for Rs. 25.10.

By consent

Ex. M21—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 6-1-76, 12-1-76, 13-1-76, 20-1-76 and 27-1-76 with voucher dt. 16-2-76 for Rs. 67.75.

By consent

Ex. M22—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 3-2-76, 4-2-76, 10-2-76, and 15-2-76 with voucher dt. 4-3-76 for Rs. 54.20.

By consent

Ex. M23—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 2-3-76 with voucher dt. 13-4-76 for Rs. 25.27.

By consent

Ex. M24—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 9-3-76 to 14-3-76, 16-3-76 to 21-3-76 and 23-3-76 with voucher dt. 7-4-76 for Rs. 171.73.

By consent

Ex. M25—Statement showing the particulars of Wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 64-76, 13-4-76, 20-4-76, 23-4-76 and 27-4-76 with voucher dt. 20-5-76 for Rs. 78.11.

By consent

Ex. M26—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 9-7-76, 4-7-76 and 11-5-76 with Voucher dt. 20-6-78 for Rs. 37.98.

By consent

Ex. M27—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 17-5-76 to 25-5-76 with voucher dt. 8-6-76 for Rs. 100.17.

By consent

Ex. M28—Statement showing the particulars of Wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 5-3-79 with petty cash voucher dt. 12-4-1979 for 12.40.

By consent

Ex. M29—Statement showing the particulars of Wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 6-3-79 with petty cash voucher dt. 14-4-79 for Rs. 12.40.

By consent

Ex. M30—Statement shoiwng the particulars of Wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 1-5-79 to 30-5-79 with cash voucher dt. 8-6-79 for Rs. 395.40.

By consent

Ex. M31—Statement showng the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 23-7-79 to 27-7-79 with cash voucher dt. 8-8-79 for Rs. 65.90.

By consent

Ex. M32—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 3-9-79 with petty cash voucher dt. 4-9-79 for Rs. 12.65.

By consent

Ex. M33—Statement showing the particulars ow wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 5-10-79 with petty cash voucher dt. 17-10-79 for Rs. 13.18.

By consent

Ex. M34—Statementing showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 10-11-79 with petty cash voucher dt. 28-11-79 for Rs. 12.80.

By consent

Ex. M35—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 10-12-79 with cash voucher dt. 24-12-79 for Rs. 12.80.

By consent

Ex. M36—Statement showing the particulars of Wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 16-1-80 to 19-1-80 with voucher dt. 25-1-80 for Rs. 59.20.

By consent

Ex. M37—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 8-2-80 with petty cash voucher dt. 29-2-80 for Rs. 14.80.

By consent

Ex. M39—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 9-2-80 and 15-2-80 with voucher dt. 18-2-80 for Rs. 29.08.

By consent

Ex. M39—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 6-3-80 with voucher dt. 8-3-80 for Rs. 13.60.

By consent

Ex. M40—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 14-3-80 with voucher dt. 21-3-80 for Rs. 13.60.

By consent

Ex. M41—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenegr/ Watchman/Water Boy for 22-3-80 with voucher dt. 31-8-80 for Rs. 13.60.

By consent

Ex. M42.—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 31-3-80 with voucher dt. 3-4-80 for Rs. 13.60.

By consent

Ex. M43—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger Watchman/Water Boy for 23-4-80 and 24-4-80 with voucher dt. 25-4-80 for Rs. 29.10.

By consent

Ex. M44—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 2-5-80 and 7-4-80 with voucher dt. 27-5-80 for Rs 28.65.

By consent

Ex. M45—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 5-5-80 to 19-5-80 with voucher dt. 22-5-80 for Rs. 218.25.

By consent

Ex. M46—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 7-4-80 with voucher dt. 1-5-80 for Rs. 14.55.

By consent

Ex. M47—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 4-7-80, 5-7-80, 8-7-80, 9-7-80 and 7-7-80 with voucher dt. 19-7-80 for Rs. 72.75.

By consent

Ex. M48—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger Watchman/Water Boy for 23-7-80 with voucher dt. 28-8-80 for Rs. 14.55.

By consent

Ex. M49—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger Watchman/Water Boy for 2-5-80 with voucher dt. 8-5-80 for Rs. 14.10.

By consent

Ex. M50—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 7-6-80 with voucher dt. 18-6-80 for Rs. 14.55.

Ex. M51—Substituted engaged and payment register from January 1973 to 12-7-77.

Ex. M51(a)—Service particulars pertaining to Smt. Imamboo in Ex. M51 at page 84.

Ex. M52—Charges account register from 8-3-74 to 26-4-76.

Ex. M53—Statement showing the particulars of wages paid to S. Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy.

Dated : 12-3-86.

J. VENUGOPALA RAO, Presiding Officer
[No. L-12012/188/81-D.II(A)(Pt.)]

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1986

का. आ. 1676 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-3-86 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 8th April, 1986

S.O. 1676.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th March, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. L-12012/127/84-D.II(A)

Dated 22-11-84

Case No. 216/1984

In the matter of dispute between :

Shri G. C. Srivastava S/o Shambhoo Dayal Srivastava, 415/13-A Gali Jiyalal, Chaputia, Lucknow.

AND

The Chief Manager, State Bank of India, Main Branch Hazaratganj, Lucknow.

APPEARANCE :

Shri Brijendra Kumar—for the workman.

Shri Mahesh Chandra—for management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour vide its notification no. L-12012/127/84-D.II(A) dt. 22-11-84 has refrered the following dispute for adjudication:

Whether the action of the Management of State Bank of India, Main Branch, Lucknow in terminating the services of Shri G. C. Srivastava, temporary Badli Guard with effect from 9-12-83, and not considering him for reemployment while appointing fresh hands under section 25-H of the I.D. Act is justified? If not, to what relief is the concerned workman is entitled?

2. The case of the appilcant is that he was appointed as temporary badli guard w.e.f 30-5-83 and was continued till 7-12-83 as such by issuing various extension letters annexure I to VII. That the applicant was given extension letters and appointment letter as mentioned in annexure I to VII but the workman was required to work beyond 25-11-83 upto to 7-12-83 and 8-12-83 was his weekly rest day but when he reached the management bank on 9-12-83, for duty he was verbally told that his services were trominated. The

applicant has been paid his salary upto 25-11-83, but despite request he has not been paid from 26-11-83 to 8-12-83. It is further averred that after terminating the workman management appointed Shri Bhim Chandra, Jeet Narain Pande and Lal Bahadur as temporary badli guard, who were still working and Mohd. Yusuf who was appointed as badli guard on 29-11-83 being junior to the workman was retained in service whereas the workman was terminated. That despite making representation annexure 1 to 10 the workman was not taken on duty. In the end it is prayed that the termination be declared illegal and he be reinstated with full back wages.

3. It is admitted by the management that the workman worked from 30-5-83 to 7-12-83, and the termination letter was issued by the competent authority was personally sought to be served on the workman but he refused to accept the same and refused the bank as the workman failed to turn up on subsequent date either to receive his termination letter or to settle his account, the termination letter was sent to him by post. It is further averred that the management tendered the workman at the time of termination two cheques but the workman refused to accept the same also. The two cheques have since been revalidated and being deposited with the court for payment of the workman. In the end it is averred that badli guard were appointed against leave vacancies/casual requirements of the bank and they had no right to claim continuity of employment and the workman employment automatically came to an end as soon as specified period or period of work came to an end.

4. On behalf of the management one Shri J. P. N. Tripathi an officer of the bank management dealing with the personnel matters has filed his affidavit evidence. He has reiterated the stand of the written statement. In cross examination he has stated that initially the workman was appointed for two days i.e. for 30th and 31st May, and letter of appointment was given to the workman at the time of joining the duty, and he was allowed to continue till the subsequent extension letter/apopintment letter was given to him on 8th June, 1983. He has stated that only weekly rest is given and not Sundays or holidays. He admits that it is likely the appointment letters are given few days later but it is mentioned that service will stand on a particular date. The last appointment letter photo copy of which was given to the workman bears an endorsement of Shri P. R. Pande Clerk concerned that the workman did not receive it. The witness states that it must have been sent to the workman by messenger. The witness was recalled again to testify and rebut the evidence by the workman after close of the case. He has deposed that no one was appointed in place of the workman and that duty register from 20-12-83 to 4-4-84 was thoroughly searched out but the same is not traceable and it is presumed that it is lost. In cross examination he admitted that no information was given either to the police authorities or higher authorities of the bank about the loss of the duty register in his knowledge. Letter, he stated that higher authorities have been informed but no such letter has been filed. He however, admitted that in the duty register the name of Mohd. Yusuf is shown from 23-11-83 to 19-12-83. He further stated that he does not know if Shri Jeet Narain Bhim Chandra were appointed from 19-12-83 on the duty register is not traceable. He specifically admitted that Mohd. Yusuf was junior to the workman and states that Mohd. Yusuf was in service when services of the concerned workman were terminated.

5. On the other hand workman gave his affidavit evidence reiterating the stand taken in statement of claim. He admits that he was appointed as badli guard but was not given any appointment letter and that was only at the time of giving him pay that extension letters were issued to him which were filed. Regarding first appointment letter Ext. I, he says that it was given to him on 8-6-83 at the time of payment and the Letter of extension of June was given to him at the time of payment in the month of July, 83 . He admits that he never raised any objection for the delayed appointments. He simply made verbal objection to the dealing clerk who told him that it was on that letter that the payment authority was made. He denied that the two cheques filed by the management in this case were ever tendered to him and that he was not paid for the period 26-11-83 to 8-12-83 for which he made representation but did not receive any reply. He however, stated that he can accept the two cheques if the tribunal directs him to accept those cheques. In the end he stated that he has come to know that badli guard Jeet Bahadur and Lal Bahadur were appointed after his termination out of Shri Bhim Singh was appointed in December, 1983, and Jeet Narain and Lal Bahadur were appointed in the month of February, 1984 and he also came to know about other appointment from them obky as they were known to him.

6. As the management has taken the plea about subsequent appointments of Bhim Chandra, Jeet Narain and Lal Bahadur on the ground that the register of temporary appointments is not traceable and is presumed lost, I am inclined to believe the testimony of the workman that the three persons were appointed after the termination of the workman. Further the management witness has admitted that one junior badli guard Mohd. Yusuf was working at the time of termination of the workman.

7. The only question is to be considered now, as to what is the status of badli guard even in view of the appointment letters annexure I to VII given though the last letter has not been given.

8. Badli workman and casual workman were considered to be a workman in industry if they were engaged for work connected with the industry, though they were not recognised for purpose of lay off compensation as their name were not borne on muster roll, however, their status in industry was recognised under Section 25C of the Industrial Dispute Act. Serial No. 10 of the 5th Schedule of the Act where it is laid down that to employ a workman as badli guard or casual or temporary and to continue them as such for years with the object of depriving them with the privilages and status of permanent workman is an unfair labour practice. Thus the position of such badli workman was casual workman would be nothing but temporary workman as given in para 20-7 of the bipartite settlement and para 508 of the Sastri Award. For termination of such temporary employee there should be a register of temporary employees as given in Sastri Award's para 493 and the principles of 250G of the Act should be observed on the principles of last come first go as given in para 507 of the Sastri Award and a termination for such temporary employees as given in para 522(4) should have been observed. Non compliance of all these renders termination illegal.

9. The termination is illegal on account of non compliance of section 25-H of the act and rule 77 of the I.D. Central Rules in which it was incumbant on the part of the management to have considered the retrenched workman before employing other temporary employees in the name of badli guards.

9. In these circumstances and for the reasons discussed above, I hold that the action of the management of State Bank of India Main Branch, Lucknow in terminating the services of Shri G. C. Srivastava temporary badli guard with effect from 9-12-83, and not considering him for reemployment while appointing fresh hands under section 25-H of the I.D. Act is not justified. The result is that the workhas to be reinstated in service with full back wages.

10. I, therefore, give my award accordingly.

Let six copies of this award be sent to the Government for its publication.

Dated : 17-3-86.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012/127/84-D.II(A)]

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1986

का. आ. 1677:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ बड़ौदा, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक

विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-4-86 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 9th April, 1986

S.O. 1677.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda, and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st April, 1986.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I. D. 13/86

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bank of Baroda.

AND

Their workman—Raj Kumar Mukhi.

INDUSTRY : Banking STATE : Haryana

AWARD

Dated, the 25th of March, 1986

1. The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, as per their Order No. L-12012/138/73-LP-III/D-II (A) dated the 6th January, 1986 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of the Bank of Baroda in terminating the services of Shri Raj Kumar Mukhi, Ex-Temporary Clerk Sonepat Branch of the said Bank with effect from the 13th May, 1973 is justified ? If not to what relief is the said workman entitled ?"

2. According to the claim statement filed by the petitioner workman he was engaged in the clerical cadre on temporary basis by the Respdt. Bank at their Sonepat Branch for 15 days' fixed tenure w.e.f. 20-2-1973; that in view of the terms of appointment he was entitled for 7 days notice or equivalent salary in lieu thereof in case of premature termination and 14 days notice or equivalent salary in lieu thereof in case he was allowed to continue on the aforesaid fixed tenure of 15 days, but sought to be disengaged thereafter. The petitioner complained that by the time of his abrupt termination on 13-5-1973 he had completed 83 days service and thus earned a right to 14 days notice or equivalent salary in lieu thereof, but for the reasons better known to them the management did not abide by the agreement and so much so that they even turned a deaf ear to his protests. He, therefore raised an issue through his Union. Since it defied any amicable settlement despite the intervention of the A.L.C. (C) at the Conciliation stage; hence the reference.

3. On joining the proceedings before this Tribunal the management raised a preliminary objection questioning the propriety of the Appropriate Government in making the reference because according to them, the same ve dispute between the parties had already been adjudicated upon by my predecessor Tribunal and so much so that even its Award had also been published in the Gazette of India. In short the principle of resjudicata, as envisaged by Section 11 of the C.P.C., was invoked and a photostat copy of the relevant Award in the previous dispute registered at No. 88/1977 was also filed.

4. On a careful scrutiny of the entire available data I am inclined to sustain the management's objection because a mere perusal of photostat copy of the Award dated 13-3-1980 in the previous proceedings between the parties would leave no manner of doubt that the same very dispute had been referred by the Appropriate Government to my learned predecessor per their Order No. L-12012/38/73/LRIII dated 5th January 1976, and after having been contested on merits by the parties on an elaborate trial, the issue was returned against the petitioner; in short; his termination was held to be valid. In due course of time the Award was accepted by the Central Government per their Notification u/s 17 of the Industrial Disputes Act 1947 dated 28-2-1980 published in the Gazette of India dated 26-4-1980 at page No. 1221 in part II-Sec. 3(ii).

5. It goes without saying that neither in the Claim-statement nor any where in our schedule of reference any such indication is available which could vitiate the previous Award or justify any re-opening of the matter. I, therefore, on following the ratio of the case of L.H. Sugar Factories and Oil Mills Pvt. Ltd. Vs. Labour Court AIR 1961 S.C. 1457 sustain the management's objection against the maintainability of the instant preceeding and returns my Award against the petitioner/workman.

Chandigarh,
Dated : 25-3-1986.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer
[No. L-12012/138/73-LR. III/D. II (A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1986

का. आ. 1678 :—भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की तारीख 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3871 द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हुआ है ।

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री जी. एस. कालरा को उक्त औद्योगिक अधिकरण में 6-4-1986 से पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है ।

[सं. एस. 11020/1/83-डी-I(ए. II)]

New Delhi, the 8th April, 1986

S.O. 1678.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal, New Delhi, constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3871 dated the 30th September, 1976.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri G. S. Kalra as the Presiding Officer of the said Industrial Tribunal with effect from 8-4-1986.

[No. S-11020(1)/83-D.I.(A) (ii)]

का. आ. 1679 :—भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की तारीख 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या का. आ. 4286 द्वारा गठित श्रम न्यायालय नई दिल्ली के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हुआ है ।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री जी. एस. कालरा को उक्त श्रम न्यायालय में 8-4-1986 से पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है ।

[सं. एस-11020/1/83-डी.-I (ए) (ii)]
ए. वी. एस. शर्मा, डैस्क अधिकारी,

S.O. 1679.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Labour Court, New Delhi,

constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4286 dated the 30th September, 1976.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri G. S. Kalra as Presiding Officer of the said Labour Court with effect from 8-4-1986.

[No. S-11020(1)/83-D.I (A)(i)]
A. V. S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1986

का. आ. 1680.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ए डी. वी. सी. बरमो कोलियरी, डाक बरमो जिला गिरिडिह के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-86 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 9th April, 1986

S.O. 1680.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad.

As shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of DVC Bermo Colliery, P.O. Bermo District Giridih and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th April, 1986.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD.

PRESENT :

Shri I. N. Singha, Presiding Officer.

Reference No. 144 of 1985

In the matter of Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of DVC Bermo Colliery Dist. Giridih and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers.—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

On behalf of the workmen.—Shri R. V. Singh, President, DVC Karamchari Sangh.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 31st March, 1986.

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24012|(33)|85-D. IV(B) dated the 16th October, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of DVC Bermo Colliery, P.O. Bermo, Distt. Giridih in denying promotion to Shri R. V. Singh to the post of Special Grade when the Orders have been issued in his favour by the Management is legal and justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

In this case both the parties filed their respective W.S. After completion of the document stage two adjournments were granted to the parties. But ultimately on 3-2-86 both the parties appeared before me and filed a memorandum of settlement. I have gone through the terms of settlement which appear to be fair and proper. Accordingly I have accepted the same and pass an Award in terms of the memorandum of settlement which forms part of the Award as Annexure.

Dt. 31-3-86.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-24012|33|86-D. IV (B)]
MADAN MOHAN, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II, DHANBAD

Reference No. 144 of 1985

Management of DVC, Bermo Mines.

AND

Their Workman.

The parties above named beg to submit that the above case has been settled between the parties on the following terms :—

That it has been decided that the promotion of the concerned workman namely Shri R. V. Singh will be considered alongwith other cases by the management that in view of the above it has been decided that the workman or his representative does not want to proceed further with the above reference.

That the above terms have finally decided the dispute between the parties and no further adjudication is required.

It is therefore submitted that an award be passed in the terms mentioned above and the reference may be disposed off accordingly.

For Employer.
Sd/- Illegible

For Workman.
R. V. SINGH, President
D.V.C. K. S. Bermo Mines
I. N. SINHA, Presiding Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986